

[2023] 10 एससीआर 595:2023 आई. एन. एस. सी 324

क.

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। (2022 की सिविल अपील संख्या 8129) अप्रैल 05, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और हिमा कोहली, जे।]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (2)-बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-प्रेस की स्वतंत्रता-उचित प्रतिबंध-राष्ट्रीय सुरक्षा-केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एम. आई. बी.) ने माध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड को "मीडिया वन" नामक एक समाचार और वर्तमान मामलों के टेलीविजन चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति को रद्द कर दिया था-एम. आई. बी. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारण 'मीडिया वन' को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति को रद्द कर दिया था-अपीलकर्ताओं ने पहले प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की-एक एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिखित अपील खारिज कर दी गई थी -एम. आई. बी. के आदेश और प्रक्रियात्मक आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की अनुमति है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का मूल प्रक्रिया में तर्कसंगतता की सांस लेता है-यह साबित करने का बोझ दावेदार पर है कि प्रक्रिया का पालन किया गया प्रक्रिया प्रक्रियात्मक गारंटी के मूल का उल्लंघन करती है-अपीलकर्ताओं ने साबित कर दिया है कि एम. आई. बी. के अनुचित आदेश और अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने और केवल अदालत में इसका खुलासा करने से एम. बी. एल. के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है-तब यह साबित करने का बोझ उत्तरदाताओं पर पड़ता है कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वह उचित थी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की आवश्यकताओं के अनुपालन में थी-हालांकि गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा वैध हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

595 ए.

596 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

सभी जांच रिपोर्टों के प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है-राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों की भागीदारी के दावे की वैधता का मूल्यांकन इस परीक्षण पर किया जाना चाहिए कि (i) क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का गैर-प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है; और (ii) क्या एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति रिकॉर्ड पर सामग्री से समान निष्कर्ष निकालेगा-यह मानते हुए भी कि गैर-प्रकटीकरण गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए साधन आनुपातिकता मानक के अन्य पहलुओं को पूरा नहीं करते हैं-एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों के सारांश का खुलासा नहीं करना, जो प्रक्रिया संबंधी गारंटी का मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम गठन करता है, उपयुक्तता को पूरा नहीं करता है।

ग

डी.

ई.

राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएँ: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से निरस्त करने की अनुमति न दें-केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की भागीदारी राज्य के निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य को बाधित नहीं करेगी-हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को तब बाहर रखा जा सकता है जब मामले के तथ्यों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएँ निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक होती हैं-इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा उन कुछ आधारों में से एक है जिन पर एक उचित प्रक्रियात्मक गारंटी का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है-यदि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने के अपने कर्तव्य को त्याग देता है, तो इसे मामले के तथ्यों पर अदालत के समक्ष उचित ठहराया जाना चाहिए-सबसे पहले, राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शामिल हैं-दूसरा, राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (ओं) को निरस्त करना उचित है-ये दो मानक

च

जी.

एच.

597

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

औचित्य का परीक्षण आवश्यकता और संतुलनकारी पहलुओं से मिलता-जुलता है-राज्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे व्यापक वैचारिक शब्दों में अपने उद्देश्य की पहचान करना पर्याप्त नहीं है-बल्कि, राज्य के लिए ठोस सामग्री प्रस्तुत करने के माध्यम से यह साबित करना अनिवार्य है कि गैर-प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है-यह आकलन करना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या ऐसी राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है-इस तरह के निष्कर्ष के लिए भौतिक समर्थन के बिना दावा नहीं किया जा सकता है-न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या राज्य प्रामाणिक तरीके से दावा करता है-न्यायालय को यह निर्धारित करके उद्देश्य के दावे की वैधता का आकलन करना चाहिए (i) क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री है कि सूचना का गैर-प्रकटीकरण हित में है। जाँच एजेंसियाँ-आयोजित की गई रिपोर्ट: खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट केवल तथ्य-खोज रिपोर्ट नहीं हैं-यह तर्क देना कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में गोपनीय जानकारी हो सकती है, एक बात है, लेकिन यह तर्क देना कि ऐसी सभी रिपोर्ट गोपनीय हैं, दूसरी बात है-इस तरह का तर्क गलत है और इसे संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है-जांच एजेंसियों की रिपोर्ट व्यक्तियों और संस्थाओं के जीवन, स्वतंत्रता और पेशे पर निर्णयों को प्रभावित करती है, और ऐसी रिपोर्टों को प्रकटीकरण से पूर्ण प्रतिरक्षा देना एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के विपरीत है-सभी जांच रिपोर्टों के प्रकटीकरण से एक पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।

ग

डी.

ई.

च

अभ्यास और प्रक्रिया-प्रासंगिक सामग्री का प्रकटीकरण-खुला न्याय-सीलबंद आवरण प्रक्रिया-प्रभाव-कम प्रतिबंधात्मक साधन-जनहित प्रतिरक्षा दावा-कार्रवाई का सुझावात्मक पाठ्यक्रम-आयोजित: सीलबंद आवरण प्रक्रियाएँ प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय दोनों सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं-जब प्रासंगिक सामग्री को सीलबंद आवरण में प्रकट किया जाता है, तो दो चोटें होती हैं जो स्थायी होती हैं-पहला,

जी.

एच.

598 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

प्रभावित पक्ष के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं-दूसरा, दलीलों के दौरान विरोधी पक्ष (जो अक्सर राज्य होता है) द्वारा दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है, और अदालत सामग्री पर भरोसा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचती है-ऐसे मामले में, प्रभावित पक्ष के पास कानूनी उपचार का कोई सहारा नहीं है क्योंकि वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सामग्री से किसी भी निष्कर्ष को साबित करने में असमर्थ होगा-निर्णय का यह रूप गोपनीयता और अपारदर्शिता की संस्कृति को कायम रखता है, और निर्णय को चुनौती की पहुंच से बाहर रखता है-प्रभावित पक्ष "त्रुटियों का खंडन करने, चूक की पहचान करने, सूचना देने वालों की विश्वसनीयता को चुनौती देने या झूठे आरोपों का खंडन करने" में असमर्थ होगा-न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार जिसे अब पढ़ा गया है। 14 और 21 प्रतिबंधित है-सीलबंद आवरण प्रक्रिया का एक संगत प्रभाव एक गैर-तर्कपूर्ण आदेश है-यदि उद्देश्य को सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा कार्यवाही या किसी अन्य कम प्रतिबंधात्मक साधनों द्वारा प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, तो सीलबंद आवरण प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाना चाहिए-अदालत को संभावित प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों का विश्लेषण करना चाहिए जिनका उपयोग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और ऐसे साधन जो प्रक्रियात्मक गारंटी के कम प्रतिबंधात्मक हैं, उन्हें अपनाया जाना चाहिए-अदालतें दस्तावेज के गोपनीय हिस्सों को संशोधित करने और दस्तावेज की सामग्री का सारांश प्रदान करने का कोर्स कर सकती हैं ताकि एक सफल सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे के बाद सामग्री को निष्पक्ष रूप से बाहर किया जा सके।

ग

डी.

ई.

अभ्यास और प्रक्रिया-सीलबंद आवरण प्रक्रिया और जनहित प्रतिरक्षा दावों के बीच अंतर-आयोजित:सीलबंद कवर प्रक्रिया और सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पूर्व में, अदालत उस सामग्री पर निर्भर करती है जो कार्यवाही के दौरान एक सीलबंद कवर में प्रकट की जाती है, जबकि उत्तरार्द्ध में जहां दस्तावेजों को पूरी तरह से कार्यवाही से हटा दिया जाता है और दोनों पक्ष और न्यायनिर्णायक ऐसी सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकते हैं-अदालतें सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों की वैधता का आकलन करती हैं, जो संरचित आनुपातिकता मानक के आधार पर सीलबंद कवर प्रक्रिया के समान नुकसान को संबोधित करती हैं-सार्वजनिक प्रतिरक्षा के मूल्यांकन के दायरे के साथ विरोधाभासी होने पर सीलबंद कवर में सामग्री को सुरक्षित करने की अदालतों की शक्ति-जनहित प्रतिरक्षा दावों में अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली समीक्षा का मानक और इस तरह के मानक की कमी।

च

जी.

एच.

599

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की रक्षा करना इंगित करता है कि सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे कम प्रतिबंधात्मक साधन हैं-इसके अतिरिक्त, जबकि सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं, सीलबंद आवरण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

अभ्यास और प्रक्रिया-जनहित प्रतिरक्षा दावा-आयोजित:जबकि जनहित प्रतिरक्षा दावा एक कम प्रतिबंधात्मक साधन है, दावे की सुनवाई करते समय प्रक्रियात्मक गारंटी को कम करने को न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जनहित प्रतिरक्षा दावे का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपक्रम करते समय आवेदक के मामले में सामग्री की प्रासंगिकता जैसे कारकों पर विचार करे।

ग

मीडिया-प्रेस-भूमिका और स्वतंत्रता-आयोजित:एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है-एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालती है-प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले, और नागरिकों को कठिन तथ्यों के साथ पेश करे जो उन्हें सही दिशा में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले विकल्प चुनने में सक्षम बनाते हैं-प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी दृष्टिकोण के साथ सोचने के लिए मजबूर करता है-सामाजिक-आर्थिक राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा करेगा-तथ्यों पर, चैनल, मीडिया-वन के आलोचनात्मक विचारों को सरकार की नीतियों पर 'स्थापना विरोधी' नहीं कहा जा सकता है-इस तरह की शब्दावली का उपयोग अपने आप में एक उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस को ऐसा करना चाहिए। नीति-केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एम. आई. बी.)-भारत से टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश-'अनुमति पत्र' द्वारा संशोधित अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10.4 से संकेत मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम. एच. ए.) राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

600 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, एमएचए से सुरक्षा मंजूरी उन शर्तों में से एक है जिसे समाचार चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है।

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय-तर्कपूर्ण आदेश की आवश्यकता-आयोजित:प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय न केवल किया जाता है, बल्कि यह भी किया जाता है-एक तर्कपूर्ण आदेश निष्पक्ष प्रशासन की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है-एक गैर-तर्कपूर्ण आदेश इनपुट की सत्यता का आकलन करने में न्यायिक दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को कायम रखता है-यदि कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है तो आदेश के कारणों की सांठगांठ पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

ग

शब्द और वाक्यांश-अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय सुरक्षा"-का अर्थ-आयोजित:राष्ट्रीय सुरक्षा अभिव्यक्ति का कोई निश्चित अर्थ नहीं है-हालांकि अदालतों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सार्वजनिक व्यवस्था से वैचारिक रूप से अलग करने का प्रयास किया है, लेकिन इस अभिव्यक्ति की एक पाठ्यपुस्तक परिभाषा निर्धारित करना असंभव (और शायद मूर्खतापूर्ण) है जो अदालतों को यह तय करने में मदद कर सकती है कि क्या तथ्यात्मक स्थिति वाक्यांश के अर्थ के भीतर आती है-वाक्यांश संदर्भ से अपना अर्थ प्राप्त करता है।

डी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

ई.

पकड़ना: **1.** अपीलों की अनुमति दी जाती है और **31** जनवरी **2022** के एम. आई. बी. के आदेश और **2** मार्च **2022** के उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: **(i)** सुरक्षा मंजूरी अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के नवीनीकरण के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक है; **(ii)** एम. आई. बी. के आदेश और प्रक्रियात्मक आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी गई है: **(क)** मेनका गांधी के मामले में इस न्यायालय के फैसले से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक बनाया गया था। प्रभाव यह है कि अदालतों ने माना है कि मामले के परिणाम से स्वतंत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने में एक अंतर्निहित मूल्य है। प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों को रद्द किया जा सकता है, भले ही गैर-अनुपालन मामले के परिणाम को प्रभावित न करे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का मूल प्रक्रिया में तर्कसंगतता की सांस लेता है। भार ए के दावेदार पर है

च

जी.

एच.

601

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

यह साबित करें कि अपनाई गई प्रक्रिया प्रक्रियात्मक गारंटी के मूल का उल्लंघन करती है; **(बी)** अपीलकर्ताओं ने साबित कर दिया है कि **31** जनवरी **2022** के एम. आई. बी. के अनुचित आदेश और अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने और केवल अदालत को इसका खुलासा करने से एम. बी. एल. के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद उत्तरदाताओं पर यह साबित करने का बोझ पड़ता है कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वह उचित थी और संविधान के अनुच्छेद **14** और **21** की आवश्यकताओं का अनुपालन करती थी। आनुपातिकता के मानक का उपयोग प्रक्रिया की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए किया गया है। **((c))** के निर्णय

पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं और डिजी केबल में यह अदालत

नेटवर्क ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब मामले के तथ्यों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक होती हैं; **(घ)** हालांकि गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियात्मक गारंटी को सीमित करने के उद्देश्य से वैध उद्देश्य हैं, लेकिन राज्य यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि ये विचार वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में उत्पन्न होते हैं। सभी जांच रिपोर्टों के प्रकटीकरण से पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है; **(ङ)** राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों में शामिल होने के दावे की वैधता का मूल्यांकन इस परीक्षण पर किया जाना चाहिए कि **(i)** क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का प्रकटीकरण न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है; और **(ii)** क्या एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति रिकॉर्ड पर सामग्री से समान निष्कर्ष निकालेगा; **(च)** यह मानते हुए भी कि प्रकटीकरण न करना गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए साधन आनुपातिकता मानक के अन्य पहलुओं को पूरा नहीं करते हैं। एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों के सारांश का खुलासा न करना, जो कि प्रक्रिया संबंधी गारंटी का मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम है, उपयुक्तता को संतुष्ट नहीं करता है; **(छ)** अदालतें सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों की वैधता का आकलन करती हैं, जो संरचित आनुपातिकता मानक के आधार पर सीलबंद सुरक्षा प्रक्रिया के समान नुकसान का समाधान करती हैं। सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों के मूल्यांकन के दायरे के साथ विरोधाभासी होने पर सीलबंद लिफाफे में सामग्री को सुरक्षित करने की अदालतों की शक्ति बल्लि निर्देशित और तदर्थ है। लोकहित प्रतिरक्षा दावों में अदालतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समीक्षा के मानक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए सीलबंद आवरण कार्यवाही में इस तरह के मानक की कमी इंगित करती है कि सार्वजनिक

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

602 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

ब्याज प्रतिरक्षा दावे कम प्रतिबंधात्मक साधन हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि जनहित प्रतिरक्षा के दावे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं, सीलबंद आवरण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है; (ज) अदालतें दस्तावेज के गोपनीय हिस्सों को संशोधित करने और दस्तावेज की सामग्री का सारांश प्रदान करने का काम कर सकती हैं ताकि एक सफल सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे के बाद सामग्री को उचित रूप से बाहर रखा जा सके; और (iii) एम. आई. बी. के आदेश को चुनौती देने की अनुमति ठोस आधारों पर दी गई है। मीडिया चैनल के संचालन की अनुमति का नवीनीकरण न करना प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है जिसे केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों पर ही यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। एम. बी. एल. को प्रतिभूति मंजूरी से इनकार करने के कारण, अर्थात् इसका कथित स्थापना विरोधी रुख और जे. ई. आई.-एच. से शेरधारकों का कथित संबंध, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिबंध के लिए वैध उद्देश्य नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, शेरधारकों के किसी भी संबंध को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था। एम. आई. बी. अब चार सप्ताह के भीतर इस निर्णय के संदर्भ में नवीकरण अनुमतियाँ जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा और अन्य सभी प्राधिकरण आवश्यक अनुमोदन जारी करने में सहयोग करेंगे। इस न्यायालय का अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाती। [पारस 170 और 174] [708-ई-एच; 709-ए-एच; 710-ए-एफ; 711-एच; 712-ए]

ग

डी.

ई.

2. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। मनमानेपन के खिलाफ गारंटी को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की सामग्री के विस्तार के बाद, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के आधार का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक रूप से समीक्षा (i) अनुचितता या तर्कहीनता; (ii) अवैधता; और (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार पर की जा सकती है। उपरोक्त आधारों के अलावा, आनुपातिकता के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है यदि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को प्रभावित करता है। सामान्य कानून से प्राप्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के दो प्राथमिक पहलू हैं-ऑडी अल्टेरम पार्टेम और नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ। ऑडी अल्टेरम पार्टेम निष्पक्ष सुनवाई के नियम को समाहित करता है। नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ ए के खिलाफ नियम को समाहित करता है।

च

जी.

एच.

603

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

पक्षपात, अर्थात्, किसी भी व्यक्ति को अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।[पारस 31 और 32] [630-एच; 631-ए-सी]

3. निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य जो सामान्य कानून से प्राप्त होता है, ठोस सिद्धांतों के एक समूह में पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। भारत और विदेशों दोनों में न्यायालयों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्थितिजन्य भिन्नताओं के साथ ठीक से जोड़कर उन्हें लागू करने में काफी लचीलापन दिखाया है। इस न्यायालय ने पहले कहा है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को 'स्ट्रैटजैकेट सूत्र' में नहीं रखा जा सकता है और यह 'सटीक परिभाषा' में असमर्थ है। अदालतों ने यह परीक्षण करने के लिए एक अंत-आधारित तर्क शुरू किया है कि क्या कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सामान्य कानून सिद्धांत का उल्लंघन करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और प्राकृतिक न्याय का पालन न करने से पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अदालतें, पूर्वाग्रह का आकलन करते हुए, यह निर्धारित करती हैं कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन से पक्ष को न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में लाभ हो सकता था।[पैरा 42] [635-बी-डी]

ग

डी.

4. तर्कसंगतता एक मानक अवधारणा है जिसे प्रासंगिक विचारों के मूल्यांकन और उनके वजन के अनुसार उन्हें संतुलित करके पहचाना जाता है। यह मूल्य उन्मुख है और उद्देश्य उन्मुख नहीं है। यही कारण है कि अदालतें यह पहचानने के लिए खुली रही हैं कि कार्रवाई उचित है या नहीं, यह पहचानने के बजाय कि कार्रवाई अनुचित है। यही कारण है कि अदालतों ने मौलिक अधिकारों पर सीमाओं की तर्कसंगतता का आकलन करते हुए आनुपातिकता के रूप में जांच के उच्च मानक को अपनाया है। आनुपातिकता विश्लेषण उद्देश्य और उपयोग किए गए साधनों दोनों का आकलन करता है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करते समय प्रासंगिक आवश्यकताएं हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आनुपातिकता मानक का उपयोग मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। आनुपातिकता के मानक का उपयोग प्रक्रियात्मक अधिकारों की सीमा की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए भी किया जाना चाहिए। न्यायालयों को निर्विवाद रूप से यह तय करते समय एक संतुलन अभ्यास करना पड़ता है कि अधिकार पर सीमा वैध है या नहीं।[पारस 49-51] [639-डी; 640-बी-सी, डी]

ई.

च

जी.

5. मामले के तथ्यों पर, एम. आई. बी. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने वाले तर्क के सारांश का भी खुलासा करने से इनकार कर दिया है।

एच.

604 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

इसने अनिवार्य रूप से एमबीएल को कोई उपाय के बिना छोड़ दिया है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता को निर्णय को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी और उचित अवसर प्रदान किए बिना प्रभावी रूप से कुचल दिया गया है। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के मूल का उल्लंघन करता है। अपीलार्थियों ने साबित कर दिया है कि उचित सुनवाई के लिए कारणों का खुलासा करना आवश्यक है। कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब और रद्द करने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका से यह भी संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ऐसी स्थिति में विवश हैं जहां वे निर्णय के खिलाफ प्रभावी रूप से चुनौती देने में असमर्थ हैं। एमएचए ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के लिए राय बनाने वाली सामग्री का खुलासा केवल उच्च न्यायालय को किया। उच्च न्यायालय ने यह तय करने के बजाय कि क्या कोई अन्य कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी साधनों का उपयोग किया जा सकता था, तुरंत बिना किसी दिमाग के एक सीलबंद लिफाफे में सामग्री प्राप्त की। यह अब प्राकृतिक न्याय का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए। यह नियम

यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित पक्ष अपील करने के अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम है। जब राज्य सरकार साक्ष्य अधिनियम की धारा **124** के तहत जनहित के आधार पर गैर-प्रकटीकरण का दावा करती है, तो सामग्री को मुकदमे से ही हटा दिया जाता है। इस विधि के विपरीत, जब प्रासंगिक सामग्री को एक सीलबंद आवरण में प्रकट किया जाता है, तो दो चोटें होती हैं जो स्थायी होती हैं। सबसे पहले, प्रभावित पक्ष को दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, दलीलों के दौरान दस्तावेजों पर विरोधी पक्ष (जो अक्सर राज्य होता है) द्वारा भरोसा किया जाता है, और अदालत सामग्री पर भरोसा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। ऐसे मामले में, प्रभावित पक्ष के पास कानूनी उपचार का कोई सहारा नहीं है क्योंकि वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सामग्री से किसी भी निष्कर्ष को साबित करने में असमर्थ होगा। निर्णय का यह रूप गोपनीयता और अपारदर्शिता की संस्कृति को कायम रखता है, और निर्णय को चुनौती की पहुंच से बाहर रखता है। प्रभावित पक्ष "त्रुटियों का खंडन करने, चूक की पहचान करने, सूचना देने वालों की विश्वसनीयता को चुनौती देने या झूठे आरोपों का खंडन करने" में असमर्थ होगा। न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार, जिसे अब अनुच्छेद **14** और **21** में पढ़ा गया है, प्रतिबंधित है। सीलबंद आवरण प्रक्रिया का एक संबंधित प्रभाव एक गैर-तर्कसंगत क्रम है। [पारस **57-59**] [**643-F; 644-A-G**] **A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

605

मध्यम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

6. राष्ट्रीय सुरक्षा उन कुछ आधारों में से एक है जिन पर उचित प्रक्रियात्मक गारंटी के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की भागीदारी निष्पक्ष रूप से कार्य करने के राज्य के कर्तव्य को बाधित नहीं करेगी। यदि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने के अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, तो इसे मामले के तथ्यों पर अदालत के समक्ष उचित ठहराया जाना चाहिए। सबसे पहले, राज्य को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। दूसरा, राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (ओं) को निरस्त करना उचित है। विदेशों में न्यायशास्त्र से उभरे ये दो मानक आनुपातिकता मानक से मिलते-जुलते हैं। पहला परीक्षण वैध लक्ष्य प्रांग जैसा दिखता है, और औचित्य का दूसरा परीक्षण आवश्यकता और संतुलन प्रांग जैसा दिखता है। [पैरा **75**] [**656-डी-एफ**]

ग

7. इस तरह के निष्कर्ष के लिए भौतिक समर्थन के बिना दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या राज्य प्रामाणिक तरीके से दावा करता है। न्यायालय को यह निर्धारित करके उद्देश्य के दावे की वैधता का आकलन करना चाहिए कि **(i)** क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है; और **(ii)** क्या एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति सामग्री के आधार पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति मानक जो किसी कार्रवाई की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए सबसे निचले मानकों में से एक है, का उपयोग ऐसे दावों के प्रति उनकी अव्यावहारिक धारणा के कारण सभी न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दावों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें मानती हैं कि यह तय करने के लिए राज्य सबसे अच्छी स्थिति में है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को पूरा किया जाएगा। न्यायालय राज्य को अपनी राय बनाने के लिए उचित सम्मान की अनुमति देता है, लेकिन इस सीमित आधार पर राय की समीक्षा करता है कि क्या सामग्री और निष्कर्ष के बीच संबंध है। न्यायालय राज्य के फैसले का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकता है कि पहचाने गए उद्देश्य से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होगा। यह कार्यकारी शाखा है

न कि न्यायिक शाखा जिसे यह आकलन करने के लिए भारत के भू-राजनीतिक संबंधों की जानकारी है कि क्या कोई कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है।[पैरा **84**] [661-ई-जी; 662-ए-बी]

डी.

ई.

च

जी.

8. प्रत्यर्थियों ने लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं किया, प्रासंगिक का खुलासा नहीं किया

एच.

606 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

सामग्री, और केवल सीलबंद लिफाफे में अदालत को सामग्री का खुलासा करने से संविधान के अनुच्छेद **21** के तहत संरक्षित निष्पक्ष सुनवाई के अपीलार्थी के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रत्यर्थी यह साबित करने में असमर्थ थे कि अपीलार्थियों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रतिबंध उचित थे। इसलिए, लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार करने वाले **31** जनवरी **2022** के एम. आई. बी. के आदेश और **2** मार्च **2022** के उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को प्रक्रियात्मक गारंटी के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए।[पैरा **159**] [704-जी-एच; 705-ए-बी]

9. जे. ई. आई.-एच. की कथित भूमिका और गतिविधियों पर आई. बी. द्वारा प्रस्तुत नोट में कहा गया है कि संगठन को तीन बार प्रतिबंधित किया गया था और तीनों प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया था। इस संगठन को पिछली बार **1992** में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम **1947** के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अदालत ने **1994** में प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। इस प्रकार, जब जे. ई. आई.-एच. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, तो राज्य के लिए यह तर्क देना अनिश्चित होगा कि संगठन के साथ संबंध राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त, एमबीएल को जे. ई. आई.-एच. से जोड़ने के लिए फाइल में एकमात्र सबूत जे. ई. आई.-एच. के कैडरों द्वारा एमबीएल के शेरों में कथित निवेश है। इसके समर्थन में आईबी ने शेरधारकों की एक सूची प्रस्तुत की है। हालाँकि, उन्हें जे. ई. आई.-एच. से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इस प्रकार, यह आरोप कि एमबीएल जे. ई. आई.-एच. से जुड़ा हुआ है, गलत है, पहला, क्योंकि जे. ई. आई.-एच. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जे. ई. आई.-एच. के समर्थकों द्वारा निवेश भारत की सुरक्षा को प्रभावित करेगा, और दूसरा, भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि जे. ई. आई.-एच. के समर्थकों द्वारा निवेश राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करेगा, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शेरधारक जे. ई. आई.-एच. के समर्थक हैं। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने का उद्देश्य एक वैध लक्ष्य या उचित उद्देश्य नहीं है।[पैरा **168**] [707-एफ-एच; 708-ए-बी]

ग

डी.

ई.

च

जी.

एक्स-आर्मीमेन प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम

भारत संघ (2014) 5 एससीसी 409:[2014] 3 एससीआर 359

और डिजी केबल नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट बनाम भारत संघ

आकाशवाणी **2019** एससी **455:[2019] 1** एस. सी. आर. **88**-समझाया।

एच.

607

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

क.

केएस पुट्टास्वामी **(9 जे)** बनाम भारत संघ **(2017) 10** एससीसीसी **1:[2017] 10** एस. सी. आर. **569**; मेनका गांधी बनाम संघ

भारत **(1978) 1** एससीसीसी **248:[1978] 2** एस. सी. आर. **621**; आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ **(1970) 1** एस. सी. सी. **248:[1970] 3**

एस. सी. आर. **530**; पंजाब राज्य बनाम सोधी सुखदेव सिंह **[1961] 2** एस. सी. आर. **371** और एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ

(1981) एस. सी. सी. **87:[1982] 2** एस. सी. आर. **365**-अनुसरण किया गया।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ **(2020) 3** एससीसीसी **637** और मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ **(2021)** एससीसीसी

ऑनलाइन एससीसी **985**-पर निर्भर था।

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मैकडोवेल **(1996) 3** एस. सी. सी. **709:[1996] 3** एस. सी. आर. **721**; टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ

ग

(1994) 6 एससीसीसी **651:[1994] 2** पूरक।एससीआर **122**; परिषद

सिविल सेवा संघ बनाम सिविल सेवा मंत्री **(1985)** ए. सी. **374**; ओम कुमार बनाम भारत संघ **(2001) 2**

एससीसीसी **386:[2000] 4** पूरक।एससीआर **693**; भारत संघ बनाम जी. गणयुथम **(1997) 7** एससीसीसी **463:[1997] 3** पूरक।

डी.

एससीआर **549**; एन. के. प्रसाद बनाम भारत सरकार **(2004)**

6 एससीसीसी **299:[2004] 3** एस. सी. आर. **1178**; मोटर वाहन टायर

विनिर्माता संघ बनाम नामित प्राधिकरण

(2011) 2 एससीसीसी **258:[2011] 1** एस. सी. आर. **198**; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. **1950** एस. सी. **27:[1950]** एससीआर **88**;

ई.

जहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य **(2004)**

4 एससीसी 158:[2004] 3 एससीआर 1050; एसएल कपूर बनाम जगमोहन (1980) 4 एससीसी 379:[1981] 1 एससीआर 746;

स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ ए. आई. आर **1981** एस. सी.

818 :[1981] 2 एस. सी. आर. 533; ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) 3 एस. सी. सी. 545:[1985] 2

च

पूरक।एस. सी. आर. **51**; सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ (**1993**)

एससीसी 78:[1992] 3 पूरक।एस. सी. आर. 12; सहारा इंडिया (फर्म),

लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, केंद्रीय-I

(2008) 14 एस. सी. सी. 151:[2008] 6 एससीआर 427; केसर

एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (**2011**) **13** एस. सी. सी. **733**:[**2011**] **9** एस. सी. आर. **19**;
आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (**2016**) **4**

जी.

एससीसी 346:[2016] 3 एससीआर 575; टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम.केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (2004)
2 एस. सी. सी. 130:[2003] 6 पूरक।

एस. सी. आर. **1235**; एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (**1978**)

एच.

608 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

3 एससीसी 544:[1979] 1 एस. सी. आर. 192; आधुनिक दंत महाविद्यालय

& अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016)

7 एससीसी 353:[2016] 3 एससीआर 579; एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990) 4 एससीसी 594:[1990]
1 पूरक।एससीआर 44;

सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम

भारत संघ (1976) 2 एससीसी 981:[1976] पूरक।एससीआर 489; सीसीआई बनाम सेल (2010) 10 एससीसी
744:[2010]

11 एस. सी. आर. 112; क्रांति एसोसिएट्स बनाम मसूद अहमद खान

(2010) 9 एससीसी 496:[2010] 10 एससीआर 1070; रानी लक्ष्मी

बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम जगदीश धरण वाष्ण्य

(2009) 4 एससीसी 240:[2009] 5 एससीआर 326; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अल्पना रॉय (2005) 8 एससीसी
296:[2005] 3

ग

पूरक।एस. सी. आर. **482**; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ

(1995) 1 एससीसी 400:[1994] 6 पूरक।एससीआर 261; न्याय

के एस पुट्टास्वामी **(5 जे)** बनाम भारत संघ **(2019) 1 एससीसी 1:[2018] 8 एस. सी. आर. 1**; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण

(1975) 4 एससीसी 428:[1975] 3 एससीआर 333; ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001) 2 एससीसी 386: [2000] 4 पूरक।

डी.

एससीआर **693**; भारत संघ बनाम गणयुथम **(1997) 7 एससीसी**

463 :[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 549; रोमेश थापर बनाम

मद्रास राज्य (1950) एस. सी. सी. 436; राम मनोहर लोहिया

बिहार राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 740:[1966] 1 एससीआर

709; बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ **(2010) 6 एस. सी. सी. 331**; कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ

ई.

(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1570-संदर्भित।

चारकौई बनाम कनाडा (नागरिकता और आप्रवासन) **[2007] 1 एस. सी. आर. 350**; गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाम रहमान **(2003) 1 ए. सी. 153**; सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री **1985 ए. सी. 374**; नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल बनाम इवांस **(1982) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1155**; कांडा बनाम मलाया सरकार **(1962) 28 एम. एल. जे. 169**; द किंग बनाम लेमन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के निरीक्षक, एक्स पार्ट वेनिकॉफ **(1920) 3 के. बी. 72**; नक्कूदा अली बनाम एम. एफ. डी. एस. जयरत्ने **[1951] एसी 66**;

च

जी.

रिज बनाम बाल्डविन **[1964] ए. सी. 40**; आर बनाम ओक्स **[1986] 1**

एस. सी. आर. **103**; ए. बनाम यूनाइटेड किंगडम, आवेदन सं. **3455/05**; गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाम एएफ **[2009] यूकेएचएल 28**; टोटेन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका **92 यूएस 105,107 (1876)**; चहल बनाम यूनाइटेड किंगडम **(1996) 23 ए**

एच.

609

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

ईएचआरआर **413**; रॉबर्ट्स बनाम पैंरोल बोर्ड **(2005) 2 एसी 738**; आर बनाम एच **(2004) एसी 134**; डंकन बनाम कैमेल लेयरड **(1942) एसी 624**; कॉनवे बनाम रिमर **(1968) एसी 910**; रेग बनाम मुख्य कांस्टेबल, **W.Midlands**, एक्स पी।विली **[1994] डब्ल्यू. एल. आर. 433**; आर. (मोहम्मद) बनाम विदेश मंत्री और

राष्ट्रमंडल मामले **[2009] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 152** (प्रशासक);

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रेनॉल्ड्स 345 यू. एस. 1 (1953); बिन्यम मोहम्मद बनाम जेपसेन डेटाप्लान 614 एफ 3 डी 1070; कैरी

बनाम महामहिम (1986), 72 एन. आर. 81 (एस. सी. सी.); रिबिक बनाम कनाडा

(महान्यायवादी) 2003 एफसीए 246; आर बनाम अहमद (2011) एससीसी 6; अल रावी बनाम सुरक्षा सेवा (2011) यूकेएससी 34 और ए एंड ओआरएस। वी.यूनाइटेड किंगडम, आवेदन

ग

नहीं। 3455/05-संदर्भित।

मार्क इलियट, जैक बीटसन, मार्टिन मैथ्यूज,

प्रशासनिक कानून:पाठ और सामग्री (तीसरा संस्करण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस); लॉरेंस जनजाति, अमेरिकी संविधान कानून (दूसरा संस्करण)।पेज। 666 21; डी. जे. गैलिंगन, उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष प्रक्रियाएँ:प्रशासनिक प्रक्रियाओं का एक अध्ययन (क्लेरेंडन प्रेस 1996) 22 टीआरएस एलन, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सम्मान का कर्तव्य (ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज) पी।510; रयीसा वकील, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कानून को संवैधानिक बनाना:प्राकृतिक न्याय और मौलिक अधिकार, (खंड 16, अंक 2, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, 2018)p.475-502; अहरोन बराक, आनुपातिकता:संवैधानिक अधिकार और उनकी सीमाएँ (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012), 374। 39 जियासिंटो डेला कैनानिया, तर्कसंगतता और कानून में प्रशासनिक कानून में तर्कसंगतता (जियोर्जियो बोनिओवन्नी, जियोवानी सातार, चियारा वैलेंटिनी द्वारा संपादित); सर अल्फ्रेड डेनिंग, फ्रीडम अंडर द लॉ (स्टीवंस एंड संस 1949) पी।92; डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, भारत की संविधान सभा की बहस (खंड। VII, 9 दिसंबर 1948; डेविड बिलचिट्ज़, 'आवश्यकता और आनुपातिकता':एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर?लियोरा लाज़र और अन्य (संस्करण) में, तर्क अधिकार:तुलनात्मक न्यायिक संलग्नता (हार्ट 2014) 49. मार्टिन चेम्बरलेन, विशेष अधिवक्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यवाही में न्यायमित्र

डी.

ई.

च

जी.

एच.

610 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

यूनाइटेड किंगडम, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लॉ जर्नल, समर 2018, वॉल्यूम। 68, सं. 3, स्वदेशी कानून पर विशेष मुद्दा (ग्रीष्मकालीन 2018), पृ. 496-510-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2014] 3 एससीआर 359

समझाया।

पैरा 11 (ii)

[2019] 1 एससीआर 88

समझाया।

पैरा **11 (ii)**

(2020) 3 एस. सी. 637

पर भरोसा किया

पैरा **15 (ii)**

पैरा **15 (ii)**

[2017]10 एससीआर 569

पीछा किया।

ग

[1996] 3 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[1994] 2 पूरक।एस. सी. आर. 122 संदर्भित

पैरा **31**

[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 693 को संदर्भित किया गया

पैरा **31**

[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 549 को संदर्भित किया गया

पैरा **31**

डी.

[1978] 2 एससीआर 621

पीछा किया।

पैरा **41**

[2004] 3 एससीआर 1178

संदर्भित किया गया है

पैरा **42**

पैरा **42**

[2011] 1 एससीआर 198

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा **44**

ई.

[1970] 3 एससीआर 530

पीछा किया।

पैरा **45**

[2004] 3 एससीआर 1050

संदर्भित किया गया है

पैरा **45**

[1981] 1 एससीआर 746

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

[1981] 2 एससीआर 533

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

च

पैरा **47**

[1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 51 को **[1992] 3 पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. 12**
संदर्भित

पैरा **47**

[2008] 6 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

जी.

[2011] 9 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

[1986] 1 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पैरा **49**

[2016] 3 एससीआर 575

संदर्भित किया गया है

पैरा **49**

[2003] 6 पूरक।एस. सी. आर. 1235 संदर्भित

पैरा **51** ए

एच.

611

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ।

[1979] 1 एससीआर 192

संदर्भित किया गया है

पैरा **51**

[2016] 3 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा **52**

[2018] 8 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **52**

[1990] 1 पूरक।एस. सी. आर. 44 संदर्भित

पैरा **56**

पैरा **56**

[1976] पूरक।एस. सी. आर. 489 संदर्भित **[2010] 11 एस. सी. आर. 112** संदर्भित

पैरा **56**

[2010] 10 एससीआर 1070

संदर्भित किया गया है

पैरा **56**

[2009] 5 एससीआर 326

संदर्भित किया गया है

पैरा **56**

ग

[2005] 3 पूरक।एस. सी. आर. 482 को संदर्भित किया गया

पैरा **56**

पैरा 59

[2007] 1 एससीआर 350

संदर्भित किया गया है

[1994] 6 पूरक।एस. सी. आर. 261 संदर्भित

पैरा 61

[1982] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

डी.

(1950) एस. सी. सी. 436

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

पैरा 83

[1966] 1 एससीआर 709

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

(2010) 6 एससीसी 331

संदर्भित किया गया है

[1961] 2 एससीआर 371

पीछा किया।

पैरा 115

ई.

[1975] 3 एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[1982] 2 एससीआर 365

पीछा किया।

पैरा 118

[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 693 संदर्भित

पैरा 164

[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 549 को संदर्भित किया गया

पैरा **164**

च

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 8129।

2022 के डब्ल्यू. ए. सं. 218 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

जी.

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 8130 और 8131।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., दुष्यंत ए. दवे, हुज़ेफा ए. अहमदी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, अज़हर असीस, अमीन हसन, सुश्री शाहरुख आलम, अक्षत मालपानी,

एच.

612

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क.

सुश्री पल्लवी प्रताप, राधा श्याम जेना, शैलेश मडियाल, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अपूर्व कुरूप, रजत नायर, टी. एस. सबरिश, अनिरुद्ध शर्मा-II, अमरीश कुमार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, सीजेआई

इस निर्णय में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

ए. तथ्य. 4 * बी. प्रस्तुतियाँ. 15 * सी. मुद्दे. 19 * डी. नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता

ग

अनुमति. 21 * ई. प्रक्रियात्मक आधार पर न्यायिक समीक्षा. 26 * ई. 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत:उद्देश्य और विषय-वस्तु. 28 * ई. 2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक बनाना:

डी.

प्रक्रिया की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए मेनका गांधी. 33 * ई. 3 मानक का प्रभाव:

ई.

तर्कसंगतता के रूप में आनुपातिकता. 37 * एफ. निष्पक्ष सुनवाई के लिए एमबीएल के अधिकार का उल्लंघन. 40 * जी. क्या निष्पक्ष सुनवाई के लिए एमबीएल के अधिकार का उल्लंघन उचित है. 46 * जी. 1 प्राकृतिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा:डिजी और पूर्व सैनिकों में निर्णय. 47 * जी. 2 आनुपातिकता मानक का अनुप्रयोग. 59 * जी. 2 (ए) वैध लक्ष्य चरण. 60 * (आई) गोपनीयता और आईबी रिपोर्ट. 62 * (II) राष्ट्रीय सुरक्षा. 63 * (III) सीलबंद लिफाफा खोलना. 67 * जी. 2 (बी) उपयुक्तता. 76 *

च

जी.

एच.

एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

613

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

जी. 3 (सी) न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन. 78 * (आई) टोटन का दावा: इस मुद्दे की गैर-न्यायसंगतता. 80 * (II) बंद सामग्री प्रक्रिया और विशेष

अधिवक्ता. 81 * (III) जनहित प्रतिरक्षा. 82 * एच. जनहित प्रतिरक्षा दावों पर न्यायशास्त्र. 88 * एच. 1 भारत. 88 * एच. 2 यूनाइटेड किंगडम. 96 * एच. 3 संयुक्त राज्य अमेरिका. 100 * एच. 4 कनाडा. 101 * आई. जनहित प्रतिरक्षा दावों का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक. 109 * जे. जनहित प्रतिरक्षा या सीलबंद कवर: कम प्रतिबंधात्मक साधन. 113 * के. महत्वपूर्ण चुनौती: अनुमति का नवीनीकरण करने से इनकार करने में एम. आई. बी. की कार्रवाई की वैधता. 124 * एल. निष्कर्ष और निर्देश. 129 * 1. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1 ने माध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड 2 को "मीडिया वन" नामक एक समाचार और वर्तमान मामलों के टेलीविजन चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति को रद्द कर दिया था। अपीलकर्ताओं, जिसमें एमबीएल, कामकाजी पत्रकारों का ट्रेड यूनियन, और संपादक, वरिष्ठ वेब डिजाइनर और प्लैनेटकास्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ कैमरामैन शामिल हैं, ने पहले प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की। 8 फरवरी 2022 के एक फैसले द्वारा, एक एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2 मार्च 2022 के एक फैसले द्वारा रिट अपील को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उस सामग्री पर भरोसा किया जिसका खुलासा केवल दूसरे प्रतिवादी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को किया गया था। स्थापित किए गए अपीलार्थी

ग

डी.

ई.

च

जी.

1 "एम. आई. बी. "2" एम. बी. एल ". 3" एम. एच. ए ".

एच.

614

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले की शुद्धता को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही।

ए. तथ्य

2. 19 मई 2010 को, एमबीएल ने 'मीडिया वन' नामक एक समाचार और वर्तमान मामलों के टेलीविजन चैनल को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। 7 फरवरी 2011 को एम. एच. ए. ने चैनल के संचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी दी। 30 सितंबर 2011 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने एम. बी. एल. को 'भारत से टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों' के तहत दस साल की अवधि के लिए 'मीडिया वन' को अपलिक करने की अनुमति दी। 4. अनुमति पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन दी गई थी। अपलिकिंग अनुमति के अनुलग्नक में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं: “(i) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को आवश्यकता पड़ने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।

ग

((ii)) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति होगी।

((iii)) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के पास विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव आदि के लिए प्रतिकूल माने जाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी।

डी.

ई.

(iv) अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि को सभी उपकरणों और अभिलेखों/प्रणालियों की पहुंच सुविधा प्रदान करनी चाहिए; (v) अनुज्ञप्ति को उपकरण और उसके स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए;

(vi) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण सार्वजनिक आपातकाल की घटना या सार्वजनिक सुरक्षा/व्यवस्था के हित में स्टेशनों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा।

च

(7. निगरानी केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि तकनीकी मानकों के उल्लंघन और कानून और लाइसेंस समझौतों में निर्धारित प्रावधानों के खिलाफ निवारक कार्रवाई के लिए त्वरित हस्तक्षेप की सुविधा हो सके।

जी.

(IX) आवेदक उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी लाइसेंस प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।”

(जोर दिया गया)

4 “अपलिकिंग दिशानिर्देश ”

एच.

615

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

उसी दिन, एम. आई. बी. ने 'टेलीविजन चैनलों की डाउनलिकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश' के प्रावधानों के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए मीडिया वन चैनल की डाउनलिकिंग के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया। 5. डाउनलिकिंग अनुमति में निर्धारित किया गया था कि ऊपर निकाले गए अनुलग्नक में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के अलावा, चैनल को केबल टेलीविजन नेटवर्किंग (विनियमन) अधिनियम 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक था।

3. 2012 में, एमबीएल ने 'मीडिया वन लाइफ' नामक एक 'गैर-समाचार टेलीविजन चैनल' और समाचार टेलीविजन चैनल, 'मीडिया वन ग्लोबल' की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए आवेदन किया। एमबीएल ने 'मीडिया वन ग्लोबल' के लिए आवेदन वापस ले लिया। 26 अगस्त 2015 को, एम. आई. बी. ने दस साल की अवधि के लिए 'मीडिया वन लाइफ' को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति दी।

ग

4. 12 फरवरी 2016 को, एम. आई. बी. ने एम. एच. ए. द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार के मद्देनजर मीडिया वन और मीडिया वन लाइफ को दी गई अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति को रद्द करने के प्रस्ताव के लिए एम. बी. एल. को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया। कारण दर्शाओ नोटिस नीचे दिया गया है: कारण सूचना दिखाएँ

डी.

जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मेसर्स मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को 30.09.2011 पर एक समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल, अर्थात् "मीडिया वन" और 26.08.2015 एक गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल, अर्थात् "मीडिया वन लाइफ" को भारत में अपलोड और डाउनलिक करने की अनुमति दी है। जबकि, इस मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमतियाँ समय-समय पर संशोधित अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

ई.

च

जबकि, अपलिकिंग दिशानिर्देशों का खंड 9.2 निर्धारित करता है कि कंपनी और उसके निदेशकों को सुरक्षा मंजूरी टीवी चैनलों के लिए अनुमति देने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्त है।

जबकि अनुमति पत्र के साथ संलग्न सुरक्षा संबंधी शर्तों में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर लाइसेंस/अनुमति को रद्द किया जा सकता है। जबकि गृह मंत्रालय ने हाल ही में सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया है।

जी.

5 "डाउनलिकिंग दिशानिर्देश "

एच.

616

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

जबकि सुरक्षा मंजूरी वापस लेने के कारण, कंपनी अपलिकिंग और डाउनलिकिंग टीवी चैनलों की अनुमति देने के लिए बहुत ही बुनियादी पूर्व-आवश्यकता को पूरा करना बंद कर देगी। कंपनी मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति पत्रों के माध्यम से दी गई सुरक्षा संबंधी शर्तों का भी उल्लंघन कर रही है।

जबकि उपरोक्त गैर-अनुपालनों के कारण, अनुमतियाँ वापस ली जा सकती हैं/रद्द की जा सकती हैं।

इसलिए अब मेसर्स माध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड से इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार के मद्देनजर उनकी अनुमति को क्यों रद्द या रद्द नहीं किया जाना चाहिए।"

ग

इस बीच, कारण बताएँ नोटिस जारी होने के सात दिन बाद, एमबीएल ने चैनल मीडिया वन को डाउनलिक करने के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन किया क्योंकि शुरू में पांच साल के लिए दिया गया लाइसेंस समाप्त हो गया था।

11 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने 'मीडिया वन' की डाउनलिकिंग अनुमति को पांच साल की और अवधि के लिए नवीनीकृत किया। 11 सितंबर 2019 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने मीडिया-वन लाइफ को अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति को रद्द कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि मीडिया-वन लाइफ और मीडिया वन दोनों को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन केवल मीडिया को दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया था।

डी.

5. 3 मई 2021 को, एमबीएल ने मीडिया वन को संचालित करने के लिए दी गई डाउनलिकिंग और अपलिकिंग अनुमतियों को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन किया क्योंकि वे 30 सितंबर 2021 और 29 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाले थे।

ई.

6. 5 जनवरी 2022 को, एम. आई. बी. ने अपलिकिंग दिशानिर्देशों के खंड 9.2 को लागू करते हुए एम. बी. एल. को एक और कारणदर्शक नोटिस जारी किया और मीडिया वन के संचालन के लिए दी गई अनुमति को 'रद्द' करने का प्रस्ताव रखा। कारण दर्शाओ नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है कि (i) अपलिकिंग दिशानिर्देशों के खंड 9.2 के अनुसार, सुरक्षा मंजूरी अनुमति देने के लिए एक पूर्व शर्त है और सुरक्षा संबंधी शर्तें अनुमति देने वाले पत्र के साथ जुड़ी हुई हैं; (ii) गृह मंत्रालय ने एमबीएल के प्रस्तावों को अतीत में सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया है और इसे 'वर्तमान मामले में भी अस्वीकार माना जा सकता है'; (iii) चूंकि सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया है, इसलिए एमबीएल ने अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति के नवीनीकरण के लिए पात्रता शर्त को पूरा करना बंद कर दिया है। कारण दर्शाओ नोटिस का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

च

जी.

एच.

617

मध्यम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

“कारण सूचना दिखाएँ

[...]

3. जबकि, अपलिकिंग दिशानिर्देशों का खंड 9.2 निर्धारित करता है कि कंपनी और उसके निदेशकों को सुरक्षा मंजूरी टीवी चैनलों के लिए अनुमति देने के लिए पूर्व-आवश्यकता है।

[...]

5. जबकि अनुमति पत्र के साथ संलग्न सुरक्षा संबंधी शर्तों में कहा गया है कि लाइसेंस/अनुमति को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

ग

6. जबकि कंपनी ने 03.05.2021 दिनांकित पत्र के माध्यम से अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। एमएचए ने सूचित किया है कि कंपनी के प्रस्तावों को अतीत में सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया है और वर्तमान मामले में भी सुरक्षा मंजूरी को अस्वीकार माना जा सकता है।

डी.

7. जबकि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारण, कंपनी ने टीवी चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति के नवीनीकरण के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करना बंद कर दिया।

8. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड से इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, उपरोक्त टीवी चैनल की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए उन्हें दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कहा जाता है।"

ई.

7. 19 जनवरी 2022 को, एम. बी. एल. ने कारणदर्शक नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि:

च

(i) उसे अपने मीडिया वन चैनल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने की कोई सूचना नहीं मिली, जैसा कि कारण बताए जाने के नोटिस में कहा गया है। इसे कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था और इस संबंध में उन्हें कोई सामग्री नहीं दी गई थी।

((ii) सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी।

जी.

(iii) एम. बी. एल. और मीडिया वन चैनल ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं जिससे सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया जा सके; (iv) एम. बी. एल. को मीडिया वन चैनल के संबंध में 12 फरवरी 2016 को इसी तरह का कारण बताने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एमबीएल ने 11 जुलाई 2019 को एक जवाब प्रस्तुत किया, 11 जुलाई 2019 को लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था;

(v) एम. आई. बी. के कार्य मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं; और

(vi) लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने की एम. आई. बी. की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एम. बी. एल. के अधिकार का उल्लंघन है।

8. 31 जनवरी 2022 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारण 'मीडिया वन' को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति को रद्द कर दिया। अनुमति रद्द करने के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

ग

"जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को 30.09.2011 पर एक समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल, "मीडिया वन" को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति दी, जो 29.09.2021 तक वैध था। 2. जबकि, अपलिकिंग दिशानिर्देशों का खंड 9.2 निर्धारित करता है कि कंपनी और उसके निदेशकों को सुरक्षा मंजूरी टीवी चैनलों के लिए अनुमति देने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्त है।

डी.

3. जबकि, कंपनी मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने दिनांक 03.05.2021 के आवेदन के माध्यम से अपने एक अनुमत समाचार और वर्तमान मामलों के टीवी चैनल, "मीडिया वन" को 10 साल की अवधि के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। 1 30.09.2021 से 29.09.2021)

ई.

4. जबकि, भारत-2011 से टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 9.2 और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों, 2011 के पैरा 8.3 के अनुसार, गृह मंत्रालय से 10 साल की अवधि के लिए समाचार और वर्तमान मामलों के टीवी चैनल, "मीडिया वन" की अनुमति के नवीनीकरण के लिए कंपनी (मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड) की सुरक्षा मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था।

च

जी.

5. जबकि, गृह मंत्रालय ने न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल "मीडिया वन" की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति के नवीनीकरण के लिए मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

एच.

619

माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

6. तदनुसार, कंपनी को 05.01.2022 दिनांकित एक कारण दिखाएँ नोटिस (SCN) दिया गया था कि उन्हें दी गई अनुमति को उपरोक्त टीवी चैनल के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए क्यों रद्द या रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एस. सी. एन. की प्रति अनुलग्नक-I में संलग्न है।

7. कंपनी ने एस. सी. एन. को उनके दिनांकित 19.01.2022 पत्र के माध्यम से जवाब दिया है। जवाब में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया है कि वे सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के आधारों से अनजान हैं और मामले में आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं करने का अनुरोध किया है। कंपनी द्वारा दिया गया जवाब अनुलग्नक-II में संलग्न है।

ग

8. कंपनी के जवाब की जांच की गई है। सुरक्षा मंजूरी गृह मंत्रालय के सुरक्षा मानकों पर आधारित है। चूंकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। चैनल को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डी.

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को एक समाचार और करंट अफेयर्स टीवी चैनल, "मीडिया वन" को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है और तदनुसार इस चैनल का नाम अनुमत चैनलों की सूची से हटा दिया गया है।"

ई.

(जोर दिया गया)

9. एम. बी. एल. ने मीडिया वन को दी गई अपलिकिंग और डाउनलिकिंग अनुमति को 'रद्द' करने के एम. आई. बी. के आदेश को चुनौती देने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा: (i) मीडिया-वन को दी गई अनुमति को रद्द करने के 31 जनवरी 2022 के आदेश को दरकिनार करना; (ii) एम. आई. बी. और एम. एच. ए. को अनुमति को रद्द करने से पहले एम. बी. एल. को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश देना; और (iii) यह घोषणा करना कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने या लाइसेंस को रद्द करने की कोई परिस्थिति नहीं है क्योंकि एम. बी. एल. ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है या राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है।

च

जी.

10. भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल 6 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान दायर कर कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था, जो "संवेदनशील और गुप्त प्रकृति" के हैं।

6 "एसजी "

एच.

620

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एमएचए "नीति के मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में" इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं कर सकता है।

11. 8 फरवरी 2022 के एक फैसले से केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि:

(i) अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10.4 और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9.4 में कहा गया है कि जब अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, तो कंपनी के निवल मूल्य और शीर्ष प्रबंधन के अनुभव को निर्धारित करने वाले पात्रता मानदंड लागू नहीं होंगे। हालांकि, अन्य नियम और शर्तें जो अपलिकिंग की अनुमति पर लागू होती हैं, नवीनीकरण पर लागू होती हैं। इस प्रकार, सुरक्षा मंजूरी एक ऐसा कारक है जिस पर मौजूदा अनुमति के नवीनीकरण के समय भी विचार किया जाना चाहिए।

ग

((ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में लागू नहीं होते हैं।

डी.

प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 7 और डिजी केबल नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

भारत 8) और

(iii) गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत फाइलों से संकेत मिलता है कि अधिकारियों की समिति 9 ने खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर ध्यान दिया और पाया कि इनपुट गंभीर प्रकृति के हैं और सुरक्षा मूल्यांकन मानकों के अंतर्गत आते हैं। उन परिस्थितियों में, अधिकारियों की समिति ने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने की सलाह दी। अधिकारियों की समिति की सिफारिशों को एम. एच. ए. द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और सहायक सामग्री द्वारा मजबूत किया गया था।

ई.

च

12. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत फाइलों को उसके समक्ष रखा जाएगा क्योंकि एकल न्यायाधीश ने 'फाइलों पर भरोसा करके' याचिका को खारिज कर दिया था। फाइलों को देखने पर, खंड पीठ ने कहा कि:

जी.

(i) हालांकि इस मुद्दे की प्रकृति और गंभीरता फाइलों से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होगी यदि

7 (2014) 5 एससीसी 409 8 एआईआर 2019 एससी 455

एच.

9 "सीओओ "

621

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

चैनल के संचालन के लिए एमबीएल को दी गई अनुमति का नवीनीकरण किया जाता है।

((ii) जबकि राज्य सामान्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।

(iii) भारत संघ तब जानकारी प्रदान करने से इनकार कर सकता है जब "संवैधानिक विचार मौजूद हों, जैसे कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, या जब किसी विशिष्ट कानून के तहत कोई विशिष्ट प्रतिरक्षा हो।" राज्य के लिए प्रतिरक्षा का अनुरोध करना पर्याप्त नहीं है और उसे न्यायालय में हलफनामे पर इसे उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए (एम. एल. शर्मा बनाम भारत संघ 10 पर भरोसा किया गया); और

ग

(iv) राज्य ने गैर-प्रकटीकरण की याचिका को उचित ठहराया है क्योंकि एकल न्यायाधीश के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर बयान से संकेत मिलता है कि "गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि मामले में सुरक्षा मंजूरी से इनकार करना खुफिया सूचनाओं पर आधारित है, जो संवेदनशील और गुप्त प्रकृति के हैं, इसलिए, नीति के मामले में और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, एमएचए इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करता है।"

डी.

13. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही शुरू की। 15 मार्च 2022 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई प्रासंगिक फाइलों को देखने के बाद 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके द्वारा मीडिया वन चैनल को संचालित करने की अनुमति रद्द कर दी गई थी। आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे निकाला गया है:

ई.

च

"6. पहले के निर्देश के अनुसरण में, फाइलों को अदालत में पेश किया गया था।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत ए. दवे ने याचिकाकर्ताओं को फाइलों की सामग्री का खुलासा करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना की। श्री डेव ने अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा फाइलों को देखने पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, सुनवाई के दौरान, अदालत द्वारा फाइलों का अध्ययन किया गया है।

जी.

एच.

10 आकाशवाणी 2021 एससी 5396

8. वर्तमान स्तर पर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम राहत देने के लिए एक मामला बनाया गया है, जिसमें अदालत द्वारा देखी गई फाइलों की सामग्री का उचित सम्मान किया गया है।

9. हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि आगे के आदेशों के लंबित रहने तक, याचिकाकर्ता, मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को दी गई सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने वाले केंद्र सरकार के 31 जनवरी 2022 के आदेशों पर रोक बनी रहेगी। याचिकाकर्ताओं को उसी आधार पर मीडिया वन नामक समाचार और वर्तमान मामलों के टीवी चैनल का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस आधार पर 31 जनवरी 2022 को मंजूरी रद्द होने से ठीक पहले चैनल का संचालन किया जा रहा था।"

ग

इस न्यायालय ने यह भी कहा कि फाइलों की सामग्री का खुलासा अपीलार्थियों को किया जाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से खुला रखा गया है: "11. यह मुद्दा कि क्या फाइलों की सामग्री का याचिकाकर्ताओं को खुलासा किया जाना चाहिए ताकि वे इन कार्यवाहियों में अपनी चुनौती को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए लेने से पहले स्पष्ट रूप से हल करने के लिए खुला रखा जाता है।[...]"

डी.

13. हम स्पष्ट करते हैं कि इस स्तर पर न्यायालय द्वारा फाइलों का अवलोकन याचिकाकर्ताओं की दलीलों की दृढ़ता पर एक अभिव्यक्ति नहीं है कि वे फाइलों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे। इस मुद्दे को अंतिम निपटान के चरण में हल करने के लिए खुला रखा जाता है।"

ई.

B. प्रस्तुतियाँ

14. एम. बी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

च

(i) एम. आई. बी. द्वारा चैनल, मीडिया वन को अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने का आदेश निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक है:

(क) सुरक्षा मंजूरी केवल चैनल के संचालन की अनुमति देने के लिए एक पूर्व शर्त है न कि मौजूदा अनुमति के नवीनीकरण के लिए। अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के खंड 10.2 के तहत, मौजूदा अनुमति का नवीनीकरण केवल उस चैनल के अधीन है जो पांच या अधिक अवसरों पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया गया है।

जी.

एच.

(ख) उपरोक्त तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा मंजूरी से उन आधारों पर इनकार नहीं किया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित प्रेस की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों से अधिक हैं। अनुमति को रद्द करने का आदेश अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9.2 को संदर्भित करता है। पैराग्राफ 9.2 'अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया' का एक हिस्सा है जिसमें प्रावधान है कि अनुमति के लिए एक आवेदन सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। सुरक्षा मंजूरी देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 की धारा 4 (6) के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित सीमाओं के अधीन होनी चाहिए; और

ग

(ग) अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.2 और 5.9 में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दी गई अनुमति को निलंबित करने के लिए सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के सीमित आधार निर्धारित किए गए हैं।

डी.

(ii) 2011 में, एम. आई. बी. ने मीडिया वन के संचालन की अनुमति दी। यह पूर्व-मान लेता है कि अनुमति दिए जाने से पहले अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9.3 और 9.4 के तहत आवश्यक सुरक्षा मंजूरी दी गई थी। 2011 और 2022 के बीच सुरक्षा मंजूरी वापस नहीं ली गई थी। नवीनीकरण स्वचालित रूप से दिया जाना चाहिए था, विशेष रूप से इसलिए कि कारण बताएँ नोटिस में अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10.2 के तहत निर्धारित शर्तों के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है; और

ई.

(iii) एम. बी. एल. को उस सामग्री तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी जिसे एम. आई. बी. ने कारण दर्शाओ नोटिस में लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। भारत संघ ने 'सीलबंद लिफाफे' में सामग्री प्रस्तुत करके और उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान उस पर भरोसा करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नकार दिया। यह प्रक्रिया एक खुली अदालत और पक्षों के लिए निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। 15. संपादक, वरिष्ठ वेब डिजाइनर और मीडिया वन 11 के वरिष्ठ कैमरा मैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा ए अहमदी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

च

जी.

11 2922 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 4331

एच.

624

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(i) एम. आई. बी. द्वारा जारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित एम. बी. एल. की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अनुमति के नवीनीकरण से इनकार करने वाली एम. आई. बी. की कार्रवाई अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों द्वारा संरक्षित नहीं है। एमबीएल के मौलिक अधिकारों को एक मनमाना परिकल्पना पर संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है:

(क) कारण दर्शाओ नोटिस और अनुमति को रद्द करने का आदेश कारणों और विवरणों से रहित है;

(ख) उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, एम. आई. बी. ने केवल यह तर्क दिया कि सामग्री संवेदनशील है और 'नीति के मामले के रूप में, और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, गृह मंत्रालय इनकार के कारणों का खुलासा नहीं करता है';

ग

(ग) उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्वीकार करती है कि एम. आई. बी. द्वारा प्रस्तुत फाइलों से मुद्दे की 'गंभीरता', 'प्रभाव', 'प्रकृति' और 'गहराई' स्पष्ट नहीं है। यह भी देखा गया कि 'हमारे सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं' और (घ) इस न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यापक उपयोग पर लगातार नाराजगी जताई है।

डी.

ई.

((ii) आनुपातिकता के सिद्धांत में यह परिकल्पना की गई है कि मौलिक अधिकारों को रोकने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन होना चाहिए।

उपयोग करने के लिए।(अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 12 और के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) बनाम भारत संघ 13) द अपलिकिंग

और डाउनलिकिंग दिशानिर्देश विभिन्न समय अवधि के लिए संचालन के लिए लाइसेंस के निलंबन पर विचार करते हैं। अनुमति को निरस्त करना एम. आई. बी. के पास उपलब्ध कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन नहीं था; और

च

(iii) उच्च न्यायालय ने रद्द करने के आदेश की चुनौती को अस्वीकार करने के लिए सीलबंद लिफाफे में रखी गई सामग्री पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

जी.

12 (2020) 3 एससीसी 637 13 (2017) 10 एससीसी 1 ए

एच.

625

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

16. केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स 14 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान स्वतंत्रताओं में से एक है और इसका कठोरता से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि अनुमति के नवीनीकरण की शर्तें अनुमति देने की शर्तों से अलग हैं, उच्च न्यायालय ने अनुमति देने और लाइसेंस के नवीनीकरण दोनों के लिए एक ही मानक लागू किया। सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय को प्रासंगिक सामग्री के प्रकटीकरण पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि सामग्री में संवेदनशील जानकारी थी, तो प्रतिवादी अपीलार्थियों को फाइल का अध्ययन करने की अनुमति देने से पहले इसे संशोधित कर सकता था। यह तर्क दिया गया था कि सामग्री की संवेदनशीलता प्रभावित पक्ष को शेष भागों को देखने से नहीं रोक सकती है। 17. प्रतिवादियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ग

(i) अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9.2 और 10 से पता चलता है कि सुरक्षा मंजूरी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक पूर्व शर्त है।

डी.

(ii) मीडिया वन को दी गई अनुमति को रद्द करने में एम. आई. बी. को उचित ठहराया गया था क्योंकि एम. एच. ए. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया था; और (iii) जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होते हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बाहर रखा जाता है (पूर्व सैनिक (ऊपर))

ई.

और डिजी केबल (ऊपर))।ग. मुद्दे

18. टेलीविजन चैनल, मीडिया वन के संचालन के लिए एमबीएल को दी गई अपलिकिंग और डाउनलिकिंग अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार करने वाले एमआईबी द्वारा जारी आदेश की वैधता निर्धारित करने के क्रम में निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

च

(i) क्या अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी आवश्यक शर्तों में से एक है;

जी.

((ख) क्या अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इनकार करने और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपनाई गई कार्रवाई ने संविधान के तहत अपीलार्थी की प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन किया है; और

14 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4678

एच.

626

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(iii) क्या लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एमबीएल के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक मनमाना प्रतिबंध है।

19. विश्लेषण पर आगे बढ़ने से पहले, कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 मई 2021 को, एम. बी. एल. ने एम. आई. बी. को अपलिकिंग और डाउनलिकिंग अनुमति के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में कहा गया है कि मीडिया वन को दी गई अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति क्रमशः 30 सितंबर 2021 और 29 सितंबर 2021 को समाप्त हो जाएगी। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एसएसजी द्वारा दायर बयान में यह प्रस्तुत किया गया था कि:

(i) एम. बी. एल. द्वारा दायर 'नवीकरण' के लिए आवेदन एम. आई. बी. द्वारा एम. एच. ए. को भेज दिया गया था; और

ग

(ii) 29 दिसंबर 2021 के एक पत्र द्वारा, एमएचए ने अपलिकिंग और डाउनलिकिंग अनुमति के 'नवीनीकरण' के लिए एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

डी.

20. एम. आई. बी. ने एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार के कारण एम. बी. एल. ने अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए अनुमति के 'नवीनीकरण' के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करना बंद कर

दिया है। एम. बी. एल. से कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें दी गई अनुमति को रद्द या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 31 जनवरी 2022 के अपने पत्र द्वारा, एम. आई. बी. ने आदेश दिया कि मीडिया वन को अपलिक और डाउनलिक करने के लिए एम. बी. एल. को दी गई अनुमति को 'रद्द' कर दिया जाए। हालांकि कारण दर्शाओ नोटिस में कहा गया है कि सुरक्षा मंजूरी जो लाइसेंस के 'नवीनीकरण' के लिए एक आवश्यकता है, को अस्वीकार कर दिया गया है, एम. आई. बी. को कारण दिखाने के लिए कहा गया था कि इसका लाइसेंस 'रद्द' क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश में 'निरसन' के इसी तरह के वाक्यांश का उपयोग किया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2 मार्च 2022 के अपने फैसले में 'नवीकरण' आवेदन और 'निरसन' आदेश में उपयोग किए गए वाक्यांशों के बीच असंगति का उल्लेख किया। 21. कारण बताने का नोटिस और रद्द करने का आदेश 'लाइसेंस रद्द करने' को संदर्भित करता है। हालांकि, पहले और बाद वाले दोनों ने नोट किया कि एमबीएल ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए शर्तों में से एक को पूरा नहीं किया है क्योंकि इसे एमएचए द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थियों के वकील ने 'नवीकरण' और 'निरसन' वाक्यांशों के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग से उत्पन्न असंगति पर प्रस्तुतियाँ नहीं दी हैं। इस प्रकार, हम इस समझ पर आगे बढ़ेंगे कि 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश ने चैनल के संचालन के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया।

ई.

च

जी.

एच.

627

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

घ. अनुमति के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता

22. अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 में मौजूदा अनुमतियों के नवीनीकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। पैराग्राफ 10 के अनुसार, अनुमति के नवीनीकरण पर दस साल के लिए विचार किया जाना है, इस शर्त के अधीन कि चैनल को अनुमति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए, जिसमें पांच या अधिक अवसरों पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का कोई भी उल्लंघन शामिल है। पैराग्राफ 10.4 में कहा गया है कि अनुमति दिए जाने के समय लागू होने वाले नियम और शर्तें नवीनीकरण के समय लागू होंगी, जो अनुमति की शर्तों द्वारा किए गए संशोधनों के अधीन होगी। प्रावधान के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

ग

“10. समाप्त होने की शर्तों का नवीनीकरण

10.2 अनुमति के नवीनीकरण पर एक बार में 10 साल की अवधि के लिए विचार किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि चैनल को पांच या अधिक अवसरों पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन सहित अनुमति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। स्थापित स्व-विनियमन तंत्र के परामर्श से यह निर्धारित किया जाएगा कि उल्लंघन क्या होना चाहिए।

डी.

[...]

ई.

10.4 मौजूदा अनुमति धारकों की अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करते समय, कंपनी के निवल मूल्य और शीर्ष प्रबंधन के अनुभव के पात्रता मानदंड लागू नहीं होंगे। हालांकि, अनुमति के संशोधित नियमों और शर्तों के अनुसार अन्य नियम और शर्तें लागू होंगी।"

च

23. डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 9, जो डाउनलिकिंग के लिए मौजूदा अनुमतियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है, अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 के समान है। यह प्रावधान इंगित करता है कि मौजूदा अनुमति का नवीनीकरण एक निहित अधिकार नहीं है। पैराग्राफ 10.2 में कहा गया है कि अनुमति का नवीनीकरण किया जाएगा।

जी.

considered.subject शर्तों के लिए। 'इसके बाद लिखा गया।

अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के नवीनीकरण के लिए पैराग्राफ 10 में निर्धारित शर्तें हैं:

(i) चैनल को पांच या अधिक अवसरों पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था;

एच.

628

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

((ii) चैनल को अनुमति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए था; और

(iii) चैनल को उन सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा जो अनुमति पत्र द्वारा संशोधित अनुमति देने पर लागू होते हैं।

शर्त 1: कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन

24. मीडिया वन को पाँच या अधिक मौकों पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है। 28 फरवरी 2020 को, एम. आई. बी. द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर रिपोर्ट प्रसारित करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। 25.6 मार्च 2020 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 20 (2) और 20 (3) और अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 8.1 और 8.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 48 घंटों के लिए मीडिया-वन चैनल के प्रसारण और पुनः प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

ग

डी.

26. हालाँकि, 7 मार्च 2020 के एक आदेश द्वारा, एम. आई. बी. ने निर्देश दिया कि एम. बी. एल. उसी दिन सुबह 9:30 बजे से चैनल मीडिया वन की अपलिकिंग फिर से शुरू कर सकता है। इस उदाहरण के अलावा, इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मीडिया वन ने कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है। अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10.2 में कहा गया है कि चैनल को पांच से अधिक मौकों पर कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघन की एकमात्र घटना दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 की पहली शर्त को पूरा नहीं करती है।

ई.

च

शर्त 2 और 3:लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता

27. अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10.4 में कहा गया है कि नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय, चैनल को उन सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना चाहिए जो अनुमति पत्र द्वारा संशोधित अनुमति देने पर लागू होते हैं। अनुमति देने के लिए लागू होने वाले नियम और शर्तें अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों में फैले हुए हैं और किसी विशिष्ट पैराग्राफ या खंड में केंद्रित नहीं हैं। अपलिकिंग दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2 (और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 1) ए के मानदंड निर्धारित करता है।

जी.

एच.

629

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

आवेदक कंपनियों पर लागू पात्रता। शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम निवल संपत्ति और पूर्व प्रबंधकीय अनुभव शामिल हैं। अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3 (और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2) एक समाचार और वर्तमान मामलों के टीवी चैनल को अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं। अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9 (और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 8) "चैनलों की अनुमति देने की प्रक्रिया" निर्धारित करते हैं। प्रावधान नीचे निकाला गया है:

“9. चैनलों की अनुमति देने की प्रक्रिया

9.1. आवेदक कंपनी सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तीन बार, निर्धारित प्रारूप "फॉर्म 1" में आवेदन कर सकती है, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली में निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क के बराबर राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट शामिल है, जो वेतन और लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पक्ष में देय है।

ग

डी.

9.2. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर, यदि आवेदक योग्य पाया जाता है, तो उसका आवेदन सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और उपग्रह उपयोग की मंजूरी के लिए अंतरिक्ष विभाग (जहां भी आवश्यक हो) को भेजा जाएगा।

ई.

[...]”

(जोर दिया गया) 28। पैराग्राफ 9.2 में कहा गया है कि एक आवेदन जो योग्य पाया जाता है, उसे सुरक्षा मंजूरी के लिए एमएचए को भेजा जाएगा। पैराग्राफ 3 और 9 इंगित करते हैं कि आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद, एम. आई. बी. यह निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास करेगा कि पैराग्राफ 2 और 3 में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। यदि शर्तों को पूरा किया जाता है, तो आवेदन को सुरक्षा मंजूरी के लिए एमएचए को भेजा जाता है। इस प्रकार, पैराग्राफ 9.2 अपलिकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 और 3 में निर्धारित शर्तों के अलावा एक शर्त निर्धारित करता है।

च

जी.

29. पैराग्राफ 9 का शीर्षक, अर्थात्, "अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया", एक मूल शर्त के प्रिस्क्रिप्शन से अलग नहीं है। पैराग्राफ 10.4 में कंपनी के निवल मूल्य और प्रबंधकीय अनुभव के पात्रता मानदंड को शामिल नहीं किया गया है।

नवीनीकरण आवेदन। अनुमति के नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तें लागू होती हैं। प्रतिभूति मंजूरी की आवश्यकता पैराग्राफ 2 और 3 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद एक चरण में उत्पन्न होती है। यदि निर्धारित प्रारंभिक शर्तें नवीनीकरण के समय लागू होती हैं, तो अनुमति के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता के आवेदन को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

30. इसके अलावा, अनुच्छेद 10। अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के 4 में कहा गया है कि 'अनुमति पत्र द्वारा संशोधित' शर्तें लाइसेंस के नवीनीकरण के समय लागू होती हैं। 'अनुमति पत्र' के अनुलग्नक में सुरक्षा मंजूरी की शर्त को संशोधित करने या समाप्त करने के लिए कोई शर्त निर्दिष्ट नहीं की गई है। बल्कि, अनुलग्नक में प्रावधान है कि 'सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा' के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 को देखते हुए, लाइसेंसधारक के पास अनुमति के नवीनीकरण के लिए निहित हित नहीं है, लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के आधार लाइसेंस को रद्द करने के आधारों से भौतिक रूप से अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइसेंस का नवीनीकरण न करना और लाइसेंस को रद्द करना दोनों ही प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध हैं। नवीनीकरण आवेदन के उद्देश्य के लिए निवल मूल्य और प्रबंधकीय अनुभव के पात्रता मानदंडों को बाहर करने के पीछे का इरादा यह है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत शर्तों के अलावा अन्य आधारों पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 10। 'अनुमति पत्र' द्वारा संशोधित अपलिंकिंग दिशानिर्देशों में से 4 इंगित करता है कि एम. एच. ए. राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर सकता है। इस प्रकार, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएचए से सुरक्षा मंजूरी उन शर्तों में से एक है जिसे समाचार चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए पूरा करना आवश्यक है।

ग

डी.

ई.

च

ई. प्रक्रियात्मक आधार पर न्यायिक समीक्षा

31. संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के साथ असंगत सभी कानून अमान्य होंगे। अनुच्छेद 13 (3) (ए) में कहा गया है कि इस प्रावधान के उद्देश्य के लिए, कानून में 'कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखता है।' इस प्रकार, यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि किसी प्रशासनिक कार्रवाई को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की सामग्री के विस्तार के बाद मनमानेपन के खिलाफ गारंटी को शामिल करने के लिए, ए के लिए आधार

जी.

एच.

प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक रूप से समीक्षा (i) अनुचितता या तर्कहीनता; (ii) अवैधता; और (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार पर की जा सकती है।¹⁵ इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि उपरोक्त आधारों के अलावा, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को प्रभावित करता है तो आनुपातिकता के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है।¹⁶ 32. सामान्य कानून से प्राप्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के दो प्राथमिक पहलू हैं-ऑडी अल्टरम पार्टेम और नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ। ऑडी अल्टरम पार्टेम निष्पक्ष सुनवाई के नियम को समाहित करता है। नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ पक्षपात के खिलाफ नियम को समाहित करता है, अर्थात्, किसी भी व्यक्ति को अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। एम. बी. एल. का यह मामला है कि एम. आई. बी. ने ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत का पालन नहीं किया क्योंकि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों और रद्द करने के निर्णय से संबंधित सामग्री का खुलासा नहीं किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि यह एमबीएल के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर, एम. आई. बी. का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सुरक्षा मंजूरी से इनकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले पर है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए एक स्थापित अपवाद है।

ग

डी.

33. तीन महत्वपूर्ण विचार हैं जिनका संदर्भ में उत्तर दिया जाना चाहिए:

ई.

(i) क्या सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के निर्णय के कारणों और प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षित है;

((ख) क्या निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करने से निर्णय अमान्य हो जाएगा; और

च

((ग) यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए एक स्थापित अपवाद हैं, तो न्यायालय को प्राकृतिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिस्पर्धी हितों का समाधान कैसे करना चाहिए।

जी.

15 आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मैकडॉवेल, (1996) 3 एस. सी. सी. 709; टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651; और सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, (1985) ए. सी. 374 देखें।

16 ओम कुमार बनाम भारत संघ, (2001) 2 एस. सी. सी. 386; भारत संघ बनाम जी. गणयुथम, (1997) 7 एस. सी. सी. 463 देखें।

एच.

632

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

34. यह मामला न्यायालय को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के शामिल होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर कानून को स्पष्ट करने और निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से निरस्त करने की अनुमति देने या राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संतुलित करने का प्रयास

करने के दो दृष्टिकोण के बीच चयन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम इन दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के बीच चयन करने से पहले प्राकृतिक न्याय के उद्देश्य और प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के न्यायशास्त्रीय विकास का विश्लेषण करें।

ई. 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत: उद्देश्य और विषय-वस्तु

35. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कानून में पढ़ा गया और निष्पक्षता हासिल करने के उद्देश्य से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन किया गया। ये सिद्धांत निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं:

ग

36. उचित परिणाम: निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह और अन्याय के रिसाव को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक नियम स्थापित किए जाते हैं। प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने के बाद जो निर्णय लिया जाता है, वह निष्पक्ष होने की उम्मीद है। एक परिणाम जो एक निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वह विश्वसनीय और सटीक होता है। आपराधिक कार्यवाही के संदर्भ में, 'सही' परिणाम को सुरक्षित करने और 'सत्य' की पहचान करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित किए गए हैं।

डी.

ई.

37. नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य सिपाही बनाम इवांस 17,

अपीलार्थी नॉर्थ वेल्स पुलिस बल का परिवीक्षाधीन सदस्य था। उन्हें उनके खिलाफ आरोप लगाए बिना बल से हटा दिया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस आधार पर निर्णय को दरकिनार कर दिया कि आरोपों का खुलासा न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। अदालत ने आगाह किया कि उनके खिलाफ आरोप लगाए बिना कार्यवाही करने में अत्यधिक खतरा था क्योंकि आरोपों की सत्यता की कभी जांच नहीं की जा सकती थी:

च

“इस तरह से आगे बढ़ने के अत्यधिक खतरे के एक उदाहरण के रूप में, यह देखा जाना चाहिए कि, दो निर्णायक मामलों में से एक के रूप में, जिसने उसे प्रभावित किया है, अपीलार्थी अपने हलफनामे में कहता है: “इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों को यह पता चला कि आवेदक और उसकी पत्नी टायडिन माइनिडिंग फार्म, बांगोर में 'हिप्पी' प्रकार की जीवन शैली जीते थे।” यह कभी भी प्रत्यर्थी के सामने नहीं रखा गया था, और इसमें अपीलार्थी या उसका प्रतिनिधि था जिसे वह

जी.

एच.

17 (1982) 1 डब्ल्यूएलआर 1155 ए

633

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यदि जांच को प्रत्यर्थी से इसके बारे में पूछने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उसे तुरंत पता चल गया होगा कि यह कथित रूप से आरोप स्पष्ट रूप से असत्य था, और बस एक गलत पते का परिणाम था। संक्षेप में, यह एक पूरी तरह से गलत बयान था जिस पर प्राकृतिक न्याय की विफलता के कारण भरोसा किया गया था, जिसकी शिकायत की गई है।”

38. उचित प्रक्रिया में अंतर्निहित मूल्य: निष्पक्ष प्रक्रिया न केवल उचित परिणाम प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि अपने आप में एक अंत है। निष्पक्ष प्रक्रिया कार्यवाही में समानता को प्रेरित करती है। कार्यवाही 'प्रतीत' होती है और निष्पक्ष देखी जाती है।

कांडा बनाम मलाया सरकार 18 में, एक पुलिस निरीक्षक ने उनकी बर्खास्तगी को इस आधार पर चुनौती दी कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई थी। यह तर्क दिया गया कि उन्हें जांच रिपोर्ट की सामग्री के बारे में जानकारी नहीं थी जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष थी। मामले का सार यह था कि क्या रिपोर्ट की सामग्री के बारे में उनकी जानकारी की कमी से पूर्वाग्रह की संभावना पैदा हुई-सचेत और अचेतन दोनों। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षपात परीक्षण की संभावना का उपयोग केवल प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को पक्षपात या पूर्वाग्रह साबित करना चाहिए। बल्कि, यह पर्याप्त है यदि गैर-प्रकटीकरण पक्षपात और पूर्वाग्रह की संभावना को जन्म देगा क्योंकि "कोई भी व्यक्ति जो एक मामला हार गया है वह यह विश्वास नहीं करेगा कि उसके साथ उचित व्यवहार किया गया है यदि दूसरे पक्ष को उसकी जानकारी के बिना न्यायाधीश तक पहुंच प्राप्त है।" हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि सूचना का खुलासा न करना निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

ग

डी.

ई.

39. निर्णय लेने और निर्णय लेने के अधिकार की वैधता: जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई निर्णय लिया जाता है, तो यह धारणा होती है कि निर्णय सटीक और न्यायपूर्ण है। यह प्रणाली की अखंडता को बनाए रखता है क्योंकि निर्णय निष्पक्ष होने के अलावा, निष्पक्ष भी प्रतीत होते हैं। आम जनता की यह धारणा कि निर्णय निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, संस्थानों में जनता का विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण है, जो अदालतों और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों की वैधता को सुरक्षित करने में सहायता करते हैं। 19 40. व्यक्तियों का सम्मान: गैर-परिणाम मूल्य, अर्थात् वे मूल्य जो निर्णय की सटीकता और दृढ़ता से स्वतंत्र हैं, आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्षता के सिद्धांत इस प्राथमिक विचार को व्यक्त करते हैं कि एक चीज के बजाय एक व्यक्ति होने के लिए कम से कम परामर्श किया जाना चाहिए।

च

जी.

18 (1962) 28 एमएलजे 169

19 मार्क इलियट, जैक बीटसन, मार्टिन मैथ्यूज, प्रशासनिक कानून: पाठ और सामग्री (3 वां संस्करण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

एच.

634

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एक 'के साथ क्या किया जाता है। 20 डी. जे. गैलिंगन ने अपनी पुस्तक "ड्यू प्रोसेस एंड फेयर प्रोसीजर्स: प्रशासनिक प्रक्रियाओं का एक अध्ययन" 21 बताता है कि निष्पक्ष व्यवहार पर जोर देना नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों की नई समझ पर निहित है:

“यह एक विशुद्ध रूप से तार्किक गतिविधि के बजाय एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में निर्णय लेने के विचार पर आधारित है, जो अंतर्निहित अनिश्चितता और मानकों की आकस्मिकता पर आधारित है। प्रशासनिक निकायों द्वारा व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार पर जोर देना नागरिक और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर उन अंतर्निहित प्रतिबद्धताओं और समझ पर आधारित है।”

टीआरएस एलन का तर्क है कि अक्सर सही परिणाम अपने आप में विवाद का विषय होता है। अलग-अलग विचारों पर पहुंचना संभव है, जो दोनों ही उचित हैं। उनका तर्क है कि जब प्रक्रियाएं विचारों की वास्तविक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा की अनुमति देती हैं, तो कानून के शासन द्वारा शासित समाज में एक नागरिक के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है।²²

ग

डी.

41. भारतीय न्यायालय प्राकृतिक न्याय की व्याख्या, अनुप्रयोग और सामग्री पर इंग्लैंड की अदालतों से काफी प्रभावित हुए हैं, मुख्य रूप से क्योंकि सिद्धांत सामान्य कानून से प्राप्त होते हैं और कानून के शासन में आधारित होते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित अन्य सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में न्यायशास्त्र संबंधी विकास आमतौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो भारतीय क्षेत्राधिकार तक फैलते हैं। हमारे न्यायालय जल्द ही इसका अनुसरण करने वाले थे जब इंग्लैंड की अदालतों ने कार्यकारी और गैर-न्यायिक 23 कार्यों के बीच और अधिकारों से वंचित करने वाली कार्रवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता तय करने के लिए विशेषाधिकार से वंचित करने वाली कार्रवाई के बीच एक कार्यात्मक अंतर किया। रिज बनाम बाल्डविन 25 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने न्यायनिर्णायक निकाय की प्रकृति के आधार पर कार्यात्मक भेद को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है

ई.

च

20 लॉरेंस जनजाति, अमेरिकी संविधान कानून (दूसरा संस्करण)। पेज। 666

21 डी. जे. गैलिंगन, उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष प्रक्रियाएँ: प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन

जी.

(क्लैरेंडन प्रेस 1996)

22 टीआरएस एलन, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सम्मान का कर्तव्य (ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल)

अध्ययन) पी. 510

23 राजा बनाम लेमन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के निरीक्षक, एक्स पार्ट वेनिकॉफ, (1920) 3 के. बी. 72

24 नक्कूदा अली बनाम एम. एफ. डी. एस. जयरत्ने, [1951] एसी 66 25 [1964] एसी 40 ए

एच.

635

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

निर्णय की प्रकृति और निर्णय लेने वाले निकाय की प्रकृति नहीं। अदालतों ने समय के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की शब्दावली के उपयोग को 'निष्पक्षता' के सिद्धांत के साथ प्रतिस्थापित किया है क्योंकि प्राकृतिक न्याय दूरदर्शिता के सिद्धांत में निहित है; जैसा कि न्यायमूर्ति भगवती ने इसे "खेल में निष्पक्ष कार्रवाई" कहा है।²⁶

42. निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य जो सामान्य कानून से प्राप्त होता है, ठोस सिद्धांतों के एक समूह में पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। भारत और विदेशों दोनों में न्यायालयों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्थितिजन्य भिन्नताओं के लिए ठीक-ठीक जोड़कर उन्हें लागू करने में काफी लचीलापन दिखाया है। इस न्यायालय ने पहले कहा है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को 'स्ट्रैटजैकेट सूत्र' 27 में नहीं रखा जा सकता है और यह 'सटीक परिभाषा' देने में असमर्थ है।²⁸ अदालतों ने यह परीक्षण करने के लिए एक अंत-आधारित तर्क शुरू किया है कि क्या कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सामान्य कानून सिद्धांत का उल्लंघन करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई

ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और प्राकृतिक न्याय का पालन न करने से पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 30 अदालतें पूर्वाग्रह का आकलन करते हुए यह निर्धारित करती हैं कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन से पक्ष को न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में लाभ हो सकता था। यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मेनका गांधी बनाम भारत संघ 31 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक बनाए जाने के बाद प्राकृतिक न्याय की इस सामग्री और गैर-अनुपालन की न्यायिक समीक्षा के मानक में बदलाव आया है।

ग

डी.

ई.

ई. 2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक बनाना: मेनका गांधी का प्रभाव

43. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संवैधानिककरण के प्रभाव को समझने के लिए संविधान के भाग III की व्याख्या पर दो न्यायशास्त्रीय विकासों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, द्वारा स्थापित 'प्रक्रिया' अभिव्यक्ति के अर्थ का विस्तार है

च

26 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248 (पैराग्राफ 9) में न्यायमूर्ति भगवती

27 एनके प्रसाद बनाम भारत सरकार, (2004) 6 एससीसी 299

जी.

28 ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण, (2011) 2 एससीसी 258

29 रयीसा वकील, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कानून को संवैधानिक बनाना: प्राकृतिक न्याय और मौलिक अधिकार, (खंड 16, अंक 2, I इंटरनेशनल जर्नल ऑफ

संवैधानिक कानून, 2018, पी. 475-502

30 एनके प्रसाद (संख्या 27) 31 मेनका गांधी (संख्या 26)

एच.

636

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

कानून 'जैसा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया को शामिल करने के लिए जगह पाता है। दूसरा, संविधान के भाग III के प्रावधानों को अलग-थलग करने के रूप में पढ़ने से मौलिक अधिकारों की अतिव्यापी प्रवृत्तियों को समझने की ओर बदलाव है।

44. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 32 में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' वाक्यांश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इसके दायरे में शामिल करता है। जबकि बहुमत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी प्रसिद्ध असहमति में कहा कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति को सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि वाक्यांश में प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए जिसमें (i) नोटिस जारी करना (ii) सुनवाई का अवसर; (iii) एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण; और (iv) प्रक्रिया का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम शामिल है। न्यायमूर्ति फजल अली की राय का पालन किया गया

ग

यह न्यायालय मेनका गांधी (ऊपर) में है। मेनका गांधी (ऊपर) में, यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो। उस मामले में, अपीलार्थी ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के उसके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी। जब्त करने के आदेश में इस तरह की कार्रवाई के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (5) पर भरोसा करते हुए कार्रवाई के अपने कारणों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट जब्त करने का कारण नहीं दिया जा सकता है, जहां पासपोर्ट प्राधिकरण की राय है कि कारणों का खुलासा भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम जनता के हित में नहीं है। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा कारण बताने से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

डी.

ई.

च

45. इस न्यायालय ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार है। यह देखा गया कि इस अधिकार को केवल एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा सकता है जो अनुचित, मनमाना और अनुचित नहीं है। आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ 33 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार जल-रोधी खंड नहीं हैं, यह देखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत तर्कसंगतता का सिद्धांत इस पर आधारित है -

जी.

32 AIR 1950 SC 27 33 (1970) 1 SCC 248 A

एच.

637

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात है। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति ने

उचित सुनवाई का अधिकार:

“[.....] हम पाते हैं कि सिद्धांत रूप में भी अनुच्छेद 21 पर अनुच्छेद 14 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया में तर्कसंगतता की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए। [...] तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर-मनमानेपन का एक आवश्यक तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है और अनुच्छेद 21 द्वारा परिकलित प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए। यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह। यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी।”

ग

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रिया में तर्कसंगतता का संचार करते हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निर्धारित नहीं हैं और अपनी प्रकृति से ही परिवर्तनीय हैं। इसलिए, प्राकृतिक न्याय की प्रत्येक अवधारणा का उल्लंघन आवश्यक रूप से प्रक्रिया को अनुचित और अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राकृतिक न्याय के गैर-अनुपालन ने एक अनुचित प्रक्रिया को जन्म दिया है, जिस परीक्षण का पालन किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था (या जिस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था) वह प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों-निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और पूर्वाग्रह के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करता है।

डी.

ई.

46. मामले के तथ्यों पर, न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत पासपोर्ट जप्त करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत थी। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्व-निर्णायक सुनवाई से इनकार करना उचित था क्योंकि अन्यथा, पासपोर्ट को जप्त करने का उद्देश्य जो त्वरित कार्रवाई करना है, विफल हो जाएगा, और असाधारण परिस्थितियों ने पूर्व-निर्णायक सुनवाई के तय किए गए सिद्धांत से प्रस्थान को उचित रूप से उचित ठहराया।

च

47. मेनका गांधी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले ने प्राकृतिक न्याय के संवैधानिककरण के कारण प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर दो सैद्धांतिक बदलावों का नेतृत्व किया। सबसे पहले, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को अब केवल एक न्यायसंगत परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि एक ऐसी आवश्यकता के रूप में देखा जाता था जो अपने आप में एक अंतर्निहित मूल्य रखती है। इस बदलाव को देखते हुए,

जी.

34 ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य, (2004) 4 एस. सी. सी. 158 देखें, जहाँ इस न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को मान्यता दी।

एच.

638

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

न्यायालयों को अब केवल इस आधार पर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का आकलन करने से रोक दिया गया है कि क्या प्रक्रिया ने मामले के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।³⁵ इसके बजाय, अदालतों को यह तय करना होगा कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था, वह परिणाम से स्वतंत्र, एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं। इस विचार के अनुपालन में, अदालतों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक अधिनियम में पढ़ा है ताकि इसे प्रक्रियात्मक आधार पर असंवैधानिक घोषित होने से बचाया जा सके।³⁶ दूसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रिया में तर्कसंगतता की सांस लेते हैं। इस तर्क के जवाब में कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत स्थिर नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ढाले जाने में सक्षम हैं, यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय का मूल एक उचित प्रक्रिया की गारंटी देता है जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक संवैधानिक आवश्यकता है। ऑडी अल्टरम पार्टम के पहलू में नोटिस के घटक, नोटिस की सामग्री, पूछताछ की रिपोर्ट और ऐसी सामग्री शामिल हैं जो अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं। जबकि स्थितिजन्य संशोधन स्वीकार्य हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों को स्थिति की जरूरतों के अनुरूप इस हद तक संशोधित नहीं किया जा सकता है कि सिद्धांत के मूल को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि यह मूल है जो प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता को प्रभावित करता है। आवेदक पर यह साबित करने का भार है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था (या उसका पालन नहीं किया गया था), वास्तव में, निष्पक्ष और उचित सुनवाई के अधिकार के मूल का उल्लंघन करता है।³⁷

ग

डी.

ई. 3 प्रक्रिया की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए मानक:तर्कसंगतता के रूप में आनुपातिकता

ई.

48. एक बार जब आवेदक यह साबित कर देता है कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मूल के संदर्भ में उचित नहीं था, तो राज्य पर यह साबित करने का बोझ पड़ता है कि अधिकार की सीमा उचित और उचित है। राज्य आमतौर पर दावा करता है कि अधिकार की सीमा उचित है क्योंकि एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल होगा। न्यायालयों को सीमा की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए समीक्षा के किस मानक का उपयोग करना चाहिए? अधिकार

च

35 एस. एल. कपूर बनाम जगमोहन, (1980) 4 एस. सी. सी. 379; "प्राकृतिक न्याय का गैर-पालन स्वयं किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह है और प्राकृतिक न्याय से इनकार के प्रमाण से स्वतंत्र रूप से पूर्वाग्रह का प्रमाण अनावश्यक है; स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 818 भी देखें।

जी.

36 ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) 3 एस. सी. सी. 545); सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ (1993) 1 एस. सी. सी. 78; सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, केंद्रीय-I (2008) 14 एस. सी. सी. 151; केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 733

37 मेनका गांधी में न्यायमूर्ति भगवती के फैसले के पैराग्राफ 12 को देखें।

एच.

639

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

संवैधानिक लोकतंत्र में निरपेक्ष नहीं हैं। इस न्यायालय से जो न्यायशास्त्र निकला है वह यह है कि अधिकार सीमित हो सकते हैं लेकिन इस तरह की सीमा को तर्कसंगतता के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। हालांकि, संविधान का केवल अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सीमा उचित होनी चाहिए, आर. सी. कूपर (ऊपर) और मेनका गांधी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों के बाद यह निर्णायक है कि तर्कसंगतता का धागा प्रक्रियात्मक और मूल सीमाओं के प्रयोग का मार्गदर्शन करने वाले मौलिक अधिकारों पर पूरे अध्याय से गुजरता है। यह हमें सीमा की 'तर्कसंगतता' का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए छोड़ देता है। संविधान का पाठ समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करता है। तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए अलग-अलग मानकों को निर्धारित करने में इस न्यायालय से बहुत स्याही निकली है: तर्कसंगतता, वेड्सबरी अनुचितता, आनुपातिकता और सख्त जांच। 49. तर्कसंगतता एक मानक अवधारणा है जिसे प्रासंगिक विचारों के मूल्यांकन और उनके वजन के अनुसार उन्हें संतुलित करके पहचाना जाता है। 38 यह मूल्य उन्मुख है और उद्देश्य उन्मुख नहीं है। यही कारण है कि अदालतें यह पहचानने के लिए खुली रही हैं कि कार्रवाई उचित है या नहीं, यह पहचानने के बजाय कि कार्रवाई अनुचित है। 39 यही कारण है कि अदालतों ने मौलिक अधिकारों पर सीमाओं की तर्कसंगतता का आकलन करते हुए आनुपातिकता 40 के रूप में जांच के उच्च मानक को अपनाया है। न्यायसंगतता और आनुपातिकता के बीच संबंध और मौलिक अधिकारों पर सीमा का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग करने की आवश्यकता को न्यायमूर्ति जैक्सन द्वारा आर बनाम ओक्स 41 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दौरान पकड़ा गया है:

ग

डी.

ई.

“यह स्थापित करने के लिए कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है, दो केंद्रीय मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, उद्देश्य, जिसे चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता की सीमा के लिए जिम्मेदार उपायों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या freedom.Second को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए।

च

38 अहरोन बराक, आनुपातिकतासंवैधानिक अधिकार और उनकी सीमाएँ (कैम्ब्रिज

जी.

यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012), 374.

39 जियासिंटो डेला कैनानिया, तर्कसंगतता और कानून में प्रशासनिक कानून में तर्कसंगतता (जियोर्जियो बोनिओवन्नी, जियोवानी सारतार, चियारा वैलेंटीनी द्वारा संपादित)

40 मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 4 एससीसी 346, न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1

41 (1986) 1 एस. सी. आर. 103; इस परिच्छेद को मॉडर्न डेंटल में संविधान पीठ के फैसले में पुष्टि के साथ उद्धृत किया गया था।

एच.

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

धारा 1 को लागू करने से यह पता चलना चाहिए कि चुने गए साधन उचित और स्पष्ट रूप से उचित हैं। इसमें "आनुपातिकता परीक्षण का एक रूप" शामिल है।"

(जोर दिया गया)

50. आनुपातिकता विश्लेषण उद्देश्य और उपयोग किए गए साधनों दोनों का आकलन करता है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करते समय प्रासंगिक आवश्यकताएं हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आनुपातिकता मानक का उपयोग मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।⁴² हालाँकि, अदालतों ने आज तक आनुपातिकता मानक का उपयोग केवल अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित स्वतंत्रताओं जैसे मूल अधिकार के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए किया है। न्यायालय प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया पर सीमाओं की वैधता का आकलन करने के लिए तर्कसंगतता परीक्षण के एक अस्पष्ट और असंरचित मानक का उपयोग कर रहे हैं।

ग

51. हमारी राय है कि आनुपातिकता के मानक का उपयोग प्रक्रियात्मक अधिकारों की सीमा की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए भी किया जाना चाहिए। न्यायालयों को निर्विवाद रूप से यह तय करते समय एक संतुलन अभ्यास करना पड़ता है कि अधिकार पर सीमा वैध है या नहीं। एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य ⁴³ के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों

की पीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता में तर्कसंगतता का एक अमूर्त मानक नहीं है। इसका मूल्यांकन कई कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए। कारक उन विचारों को सूचीबद्ध करते हैं जो संतुलन चरण में किए जाते हैं। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है: “28. [...] उल्लङ्घन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित स्थितियां, ये सभी किसी विशेष प्रावधान की तर्कसंगतता पर विचार करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। अधिनियम में सन्निहित प्रक्रिया को समस्या की तात्कालिकता और परिमाण, प्रतिबंधों के अंतर्निहित उद्देश्य और प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए।” 52 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) में इस न्यायालय के निर्णय

डी.

ई.

च

जी.

(उपर्युक्त) और आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य 44, आनुपातिकता स्थापित करना

42 ओम कुमार (संख्या 16); टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, (2004) 2 एससीसी 130। 43 (1978) 3 एस. सी. सी. 544

44 (2016) 7 एससीसी 353 ए

एच.

641

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

मूल अधिकारों पर उल्लंघनों की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए मानक प्रक्रियात्मक गारंटी पर सीमाओं की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक के अनुप्रयोग को नहीं रोकते हैं। आनुपातिकता का मानक औचित्य की संस्कृति को प्रेरित करता है, जहां राज्य को यह उचित ठहराने का बोझ उठाना पड़ता है कि उसका कार्य उचित था और मनमाना नहीं था। 45 एक बार जब तर्कसंगतता के सिद्धांत को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में पड़ा जाता है, तो अदालत के लिए मूल और प्रक्रियात्मक कार्यों की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए विभिन्न मानकों का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है।

एफ. निष्पक्ष सुनवाई के लिए एमबीएल के अधिकार का उल्लंघन

ग

53. एम. बी. एल. का तर्क है कि एम. आई. बी. के आदेश और उच्च न्यायालय के फैसले से एक तर्कपूर्ण आदेश, प्रासंगिक सामग्री का खुलासा और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि इन तीन सिद्धांतों का निरसन निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का मूल है।

डी.

((ii) युक्तियुक्त आदेश: वर्तमान मामले में, कारण बताने के नोटिस में कहा गया है कि एमएचए ने अपने चैनल, मीडिया वन को संचालित करने के लिए एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इसमें सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार करने वाला 31 जनवरी 2022 का

आदेश भी सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने का कारण नहीं बताता है। ऐसी परिस्थितियों में, एम. आई. बी. को उनके खिलाफ मामले का बचाव करने के लिए बिना किसी वास्तविक उपाय के एक अनिश्चित स्थिति में रखा गया था।

ई.

च

((ii) निर्णय से संबंधित सामग्री का प्रकटीकरण: एमएचए ने अपने फैसले के लिए प्रासंगिक किसी भी सामग्री का खुलासा करने से इनकार कर दिया। एमएचए द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा न करने का दावा कुछ 'शीर्ष गुप्त' दस्तावेजों तक सीमित नहीं था। बल्कि, निर्णय से संबंधित सभी दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया गया है; और

जी.

((ग) खुला न्याय: एमएचए ने उच्च न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों का खुलासा किया। उच्च न्यायालय ने खुलासा की गई सामग्री पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया

45 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (5 जे) बनाम भारत संघ (5 जे), (2019) 1 एससीसी 1 (पैरा 310) में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय देखें।

एच.

642

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

केवल सीलबंद आवरण में संबंधित सामग्री को कार्यवाही से नहीं हटाया जाता है। सामग्री को केवल प्रभावित पक्ष के डॉकेट से हटा दिया जाता है। पक्ष अपने कार्यों का बचाव करता है, जो अक्सर राज्य होता है, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण क्रमशः तर्क देते समय और किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय सामग्री पर भरोसा करते हैं।

54. इस स्तर पर एक सहायक प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या निष्पक्ष और उचित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं, यह तय करने के लिए तीन कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमारी राय है कि अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि समग्र रूप से अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है या नहीं। मेनका गांधी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले के बाद, जहां इस अदालत ने परिणाम (और परिणाम के उद्देश्य) के विपरीत प्रक्रिया (और प्रक्रिया के प्रभाव) को प्राथमिकता दी, यह पर्याप्त है यदि प्रभावित पक्ष यह साबित करता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष और उचित नहीं थी, बिना गैर-अनुपालन के कारण परिणाम पर प्रभाव के किसी भी संदर्भ के। ऐसा करते समय, यह तर्क देना दावेदार की शक्ति के भीतर है कि निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के कई पहलुओं का उल्लंघन किया गया था। हालांकि, अदालत को इस तरह के दावे की वैधता का आकलन करते समय उल्लंघन के दावों को समग्र प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह सरल कारण है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ढाले जा सकते हैं। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता "संदर्भ, तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद लागू करने के लिए एक समान, अपरिवर्तनीय मानक लागू नहीं करती है। 46 न्यायिक निकायों को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को तय करने में पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्राकृतिक न्याय के हर पहलू और घटक का गैर-अनुपालन प्रक्रिया को अनुचित नहीं बनाता है। दावेदार को यह साबित करना होगा कि प्राकृतिक न्याय के एक घटक के गैर-अनुपालन का प्रभाव इतना गंभीर है कि एक घटक-पक्ष के दृष्टिकोण से तर्क देते समय निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के मूल का उल्लंघन किया जाता है। पालन की जाने वाली प्रक्रिया को मूल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो एक प्रक्रिया की तर्कसंगतता को सुनिश्चित करता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

55. अपीलार्थियों ने यह साबित करके अपने बोझ का निर्वहन किया है कि उपरोक्त तीन सिद्धांतों का पालन न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मूल का उल्लंघन है: निष्पक्ष और उचित सुनवाई का अधिकार।

46 ए एंड ओआरएस. वी. यूनाइटेड किंगडम, आवेदन सं। 3455/05 A

एच.

643

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

56. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय न केवल किया जाता है बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाता है। एक तर्कसंगत आदेश निष्पक्ष प्रशासन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने में इसका अत्यधिक महत्व है; विद्वान और अदालतें अब इसे प्राकृतिक न्याय का तीसरा सिद्धांत मानती हैं। 47 एक तर्कपूर्ण आदेश का नियम पाँच महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले, यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह सत्ता के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाता है। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि कारण देने में "न्यायिक निर्णय और मनमाने निर्णय के बीच एक पूरा अंतर होता है।" 48 न्यायमूर्ति भगवती ने मेनका गांधी (ऊपर) में कहा कि नियम "कानून के शासन को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है और अदालत को किसी दिए गए मामले में अपने आवेदन में इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए।" दूसरा, गैर-तर्कसंगत आदेशों का निर्णय को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने का व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। एक गैर-तर्कसंगत आदेश न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने की अदालतों की शक्ति को सीमित करता है क्योंकि न्यायिक समीक्षा का दायरा कानून या तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों तक फैला हुआ है। अपील के अधिकार पर एक सीमा का अनिवार्य रूप से मतलब है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। तीसरा, कारणों की अभिव्यक्ति मनमाना राज्य कार्रवाई की चिंताओं को कम करके एक न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में सहायता करती है। 49 यह विचार 50 की स्पष्टता का परिचय देता है और अप्रासंगिक और बाहरी विचारों को छोड़ता है। चौथा, यह संस्थान की वैधता को बढ़ाता है क्योंकि निर्णय निष्पक्ष प्रतीत होंगे। एक उच्च संभावना है कि एक तर्कपूर्ण क्रम के माध्यम से खोज उचित है। पाँचवाँ, तर्कपूर्ण आदेश सूचना के अधिकार और खुली सरकार के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हैं। गोपनीयता पक्षपात, भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयों को जन्म देती है जो कानून के शासन पर आधारित शासन मॉडल के विरोधी हैं।

ग

डी.

ई.

57. मामले के तथ्यों पर, एम. आई. बी. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने वाले तर्क के सारांश का भी खुलासा करने से इनकार कर दिया है। इसने अनिवार्य रूप से एमबीएल को कोई उपाय के बिना छोड़ दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावी और उचित अवसर प्रदान किए बिना प्रभावी ढंग से कुचल दिया गया है।

च

जी.

47 एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ, (1990) 4 एस. सी. सी. 594; सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ, (1976) 2 एस. सी. सी. 981; सी. सी. आई. बनाम सेल (2010) 10 एस. सी. सी. 744; क्रांति एसोसिएट्स बनाम मसूद अहमद खान, 2010 9 एस. सी. सी. 496 देखें।

48 सर अल्फ्रेड डेनिंग, फ्रीडम अंडर द लॉ (स्टीवंस एंड संस 1949) पी।92 49 रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम जगदीश धरण वाष्णेय, (2009) 4 एससीसी 240

50 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अल्पना रॉय, (2005) 8 एस. सी. सी. 296

एच.

644

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

निर्णय को चुनौती देना। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के मूल का उल्लंघन करता है। अपीलार्थियों ने साबित कर दिया है कि उचित सुनवाई के लिए कारणों का खुलासा करना आवश्यक है। कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब और रद्द करने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका से यह भी संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ऐसी स्थिति में विवश हैं जहां वे निर्णय के खिलाफ प्रभावी रूप से चुनौती देने में असमर्थ हैं।⁵⁸ एमएचए ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के लिए राय बनाने वाली सामग्री का खुलासा केवल उच्च न्यायालय को किया। उच्च न्यायालय ने यह तय करने के बजाय कि क्या कोई अन्य कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी साधनों का उपयोग किया जा सकता था, तुरंत बिना किसी दिमाग के एक सीलबंद लिफाफे में सामग्री प्राप्त की। यह अब प्राकृतिक न्याय का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित पक्ष अपील करने के अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम है। जब राज्य सरकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के तहत जनहित के आधार पर खुलासा न करने का दावा करती है, तो सामग्री को मुकदमे से ही हटा दिया जाता है। इस विधि के विपरीत, जब प्रासंगिक सामग्री को एक सीलबंद आवरण में प्रकट किया जाता है, तो दो चोटें होती हैं जो स्थायी होती हैं। सबसे पहले, प्रभावित पक्ष को दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, दलीलों के दौरान दस्तावेजों पर विरोधी पक्ष (जो अक्सर राज्य होता है) द्वारा भरोसा किया जाता है, और अदालत सामग्री पर भरोसा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। ऐसे मामले में, प्रभावित पक्ष के पास कानूनी उपचार का कोई सहारा नहीं है क्योंकि वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सामग्री से किसी भी निष्कर्ष को साबित करने में असमर्थ होगा।

ग

डी.

ई.

59. निर्णय का यह रूप गोपनीयता और अपारदर्शिता की संस्कृति को कायम रखता है, और निर्णय को चुनौती की पहुंच से बाहर रखता है। प्रभावित पक्ष "त्रुटियों का खंडन करने, चूक की पहचान करने, सूचना देने वालों की विश्वसनीयता को चुनौती देने या झूठे आरोपों का खंडन करने" में असमर्थ होगा।⁵¹ न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार, जिसे अब अनुच्छेद 14 और 21 में पढ़ा गया है, प्रतिबंधित है। सीलबंद आवरण प्रक्रिया का एक संबंधित प्रभाव एक गैर-तर्कसंगत क्रम है। कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ⁵² में, हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने अदालत की ओर से बोलते हुए प्रक्रियात्मक दुर्बलताओं पर टिप्पणी की जो सीलबंद आवरण की प्रक्रिया को कायम रखती है:

च

जी.

"27. कानून का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि वह सभी सामग्री जिस पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा भरोसा किया जाता है।

51 चारकौई बनाम कनाडा (नागरिकता और आप्रवासन), (2007) 1 एस. सी. आर. 350 52 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1570 ए

एच.

645

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

खुलासा किया जाना चाहिए। भले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय सामग्री पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन विवाद के लिए प्रासंगिक जानकारी, जो 'उचित संभावना' के साथ प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करेगी, का खुलासा किया जाना चाहिए। सामग्री का एकतरफा प्रस्तुतिकरण जो दूसरे पक्ष के बहिष्कार के लिए निर्णय का विषय बनाता है, प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन करता है। वर्तमान मामले में, इसके परिणामस्वरूप उन अधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिनका करियर इसके परिणामस्वरूप सीधे प्रभावित होता है।

28. प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (इस मामले में ए. एफ. टी.) को एक सीलबंद लिफाफे में इसका खुलासा एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा निर्णय की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बनाता है। सीलबंद लिफाफे में खुलासा दो समस्याओं को कायम रखता है। सबसे पहले, यह पीड़ित पक्ष को किसी आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करता है क्योंकि मुद्दों का निर्णय सीलबंद लिफाफे में प्रदान की गई साझा नहीं की गई सामग्री के आधार पर आगे बढ़ा है। सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुँचता है जिसे तब प्रभावी रूप से चुनौती की पहुँच से बाहर रखा जाता है। दूसरा, यह अपारदर्शिता और गोपनीयता की संस्कृति को कायम रखता है। यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हाथों में पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह एक मुकदमे में शक्ति के संतुलन को एक प्रमुख पक्ष के पक्ष में झुकाता है जिसका सूचना पर नियंत्रण होता है। अक्सर यह राज्य नहीं है। कारणों के साथ एक न्यायिक आदेश न्याय प्रणाली की पहचान है। यह कानून के शासन का समर्थन करता है। हालांकि, सीलबंद आवरण अभ्यास उस प्रक्रिया को जांच से परे रखता है जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। सीलबंद आवरण प्रक्रिया व्यक्तिगत मामले से लेकर मामले के स्तर और संस्थागत स्तर दोनों पर न्याय वितरण प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करती है।"

ग

डी.

ई.

च

60. सीलबंद लिफाफे में सामग्री के अवलोकन पर, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत फाइलों से संकेत मिलता है कि अधिकारियों की समिति ने खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर ध्यान दिया और पाया कि इनपुट गंभीर प्रकृति के हैं और सुरक्षा मूल्यांकन मानकों के अंतर्गत आते हैं।" एकल न्यायाधीश ने कहा कि "उन परिस्थितियों में, अधिकारियों की समिति ने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने की सलाह दी।" एकल न्यायाधीश इस पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करता है

जी.

एच.

646

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

'निवेश जो गंभीर प्रकृति के थे' की प्रकृति। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा मूल्यांकन मापदंडों का कोई उल्लेख नहीं है जिन पर भरोसा किया गया है। एक गैर-तर्कसंगत आदेश इनपुट की सत्यता का आकलन करने में न्यायिक दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को कायम रखता है। यदि कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है तो आदेश के कारणों की सांठगांठ पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।⁶¹ अपील पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि हालांकि इस मुद्दे की प्रकृति और गंभीरता फाइलों से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अगर चैनल के संचालन के लिए एमबीएल को दी गई अनुमति का नवीनीकरण किया जाता है तो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। डिवीजन बेंच ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का भी खुलासा नहीं किया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अदालत के दिमाग में क्या था जिसके कारण यह माना गया कि मंजूरी से इनकार करना उचित था, यह देखने के बावजूद कि मुद्दे की प्रकृति और गंभीरता स्पष्ट नहीं है। एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा अपनाई जाने वाली सीलबंद आवरण प्रक्रिया ने अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के लिखित उपचार के अधिकार को प्रदान कर दिया है, जिसे संविधान 53 का 'हृदय और आत्मा' और संविधान 54 की एक मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है, एक सूखा चर्मपत्र। सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा न करना, जो लाइसेंस को नवीनीकृत करने की अनुमति से इनकार करने का एकमात्र आधार है और केवल एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करने से संविधान के तहत अपीलार्थी की प्रक्रियात्मक गारंटी प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा एक औपचारिक आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों के लिखित उपचार के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने अपीलार्थियों को एक भूलभुलैया में छोड़ दिया है जहाँ वे अंधेरे में लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपीलार्थियों को प्रतिभूति मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा न करने और केवल एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को खुलासा करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मूल-एक निष्पक्ष और उचित कार्यवाही के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है।

ग

डी.

ई.

च

जी. क्या एमबीएल के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन उचित है

62. एसजी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर बयान में कहा कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि (i) खुफिया जानकारी जिसके आधार पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया गया था, वे 'गुप्त और संवेदनशील' हैं और (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

जी.

53 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, भारत की संविधान सभा की बहस (खंड। VII, 9 दिसंबर 1948

54 एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1995) 1 एससीसी 400 ए

एच.

647

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

निरस्त कर दिया गया क्योंकि: सबसे पहले, निर्णय खुफिया सूचनाओं पर आधारित है जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से प्रकृति में 'संवेदनशील' हैं और दूसरा, ये सूचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हैं। भारत संघ ने पूर्व में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है -

सेना की सुरक्षा सेवाएँ (ऊपर) और डिजी केबल नेटवर्क

(ऊपर) यह तर्क देना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तब लागू नहीं होंगे जब राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार शामिल हों। इस तर्क की वैधता का आकलन यह तय करने से पहले किया जाना चाहिए कि क्या राज्य ने प्रक्रियात्मक गारंटी पर उल्लंघन को उचित ठहराते हुए अपने बोझ का निर्वहन किया है।

जी. 1 प्राकृतिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा: डिजी और पूर्व सैनिकों में निर्णय

ग

63. पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं (ऊपर) में,

अपीलार्थी को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का व्यवसाय दिया गया था। विमान नियम 1937 के नियम 92 में कहा गया है कि व्यवसाय सुरक्षा मंजूरी के अधीन प्रदान किया जाएगा। अपीलार्थी को सूचित किया गया कि सुरक्षा मंजूरी 'राष्ट्रीय हित' के आधार पर वापस ले ली गई है। अपीलार्थी ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की। रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया था कि अपीलार्थी को ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा मंजूरी वापस लेने के लिए भरोसा किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि फाइल में दस्तावेजों को 'गुप्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अपीलार्थी के साथ साझा नहीं किया जा सकता था। दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 'सीलबंद लिफाफे' में रखा गया था। दस्तावेजों के अवलोकन पर, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि आरोपों के सार का खुलासा किया जाए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि राष्ट्रीय हित में सामग्री का खुलासा अपीलार्थी को नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही शुरू की। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं शामिल हैं, तो पक्ष 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन पर जोर नहीं दे सकता'। यह भी कहा गया कि न्यायालय के लिए यह संतुष्ट करने के लिए खुला है कि सरकार का यह दावा कि राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, वास्तव में सच है। इस न्यायालय ने जमोरा 55 के निर्णयों पर भरोसा किया और

डी.

ई.

च

जी.

गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाम रहमान 56 का मानना है कि

55 (1916) 2 एसी 77 (पीसी) 56 (2003) 1 एसी 153

एच.

648

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सरकार के निर्णय को तब सम्मान दिया जाना चाहिए जब यह राय हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख मांग सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, सिविल परिषद में निर्णय

सेवा संघ बनाम सिविल सेवा मंत्री 57 पर भरोसा किया गया था

जब राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन संभव नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने मामले में तथ्यात्मक विचारों पर निर्णय नहीं लिया क्योंकि अपीलार्थी को दी गई सुरक्षा मंजूरी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। प्रासंगिक अवलोकन नीचे निकाला गया है:

“16. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का सवाल नहीं है। यह नीति की बात है। यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि कुछ राज्य के हित में है या नहीं। यह कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सेकी में लॉर्ड हॉफमैन को उद्धृत करने के लिए। गृह विभाग के लिए राज्य। बनाम रहमान [(2003) 1 ए. सी. 153:(2001) 3 डब्ल्यूएलआर 877:(2002) 1 सभी ईआर 122 (एचएल)]:(ए. सी. पी. 192 सी)

ग

डी.

“... [राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में] कानून का सवाल नहीं है। यह निर्णय और नीति का विषय है। यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश अन्य देशों के संविधान के तहत, यह निर्णय कि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है या नहीं, न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है। उन्हें कार्यपालिका को सौंपा जाता है।”

ई.

17. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, एक पार्टी जोर नहीं दे सकती है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए।

ऐसे मामलों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, तो वैधानिक बहिष्करण को पढ़ें और प्रदान करें। विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर,

च

हालाँकि, यह अदालत के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए खुला होगा कि क्या कोई उचित तथ्य थे, और उस संबंध में, अदालत को फाइलों को बुलाने और यह देखने का अधिकार है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का यह रुख हो जाता है कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, तो अदालत प्रभावित पक्ष को कारणों का खुलासा नहीं करेगी।

जी.

57 1985 एसी 374 ए

एच.

649

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

18. तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी को पांच साल की अवधि के लिए 17-4-2007 दिनांकित आदेश द्वारा दी गई सुरक्षा मंजूरी पहले ही समाप्त हो चुकी है। उद्धृत करने के लिए:

“मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच की गई है और कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। कंपनी की प्रतिभूति मंजूरी एक अवधि के लिए वैध होगी।

इस पत्र की तारीख से पांच साल के लिए जिसके अंत में इस ब्यूरो का नया अनुमोदन अनिवार्य है।”

(जोर दिया गया)

19. मामले के उस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय के लिए अधिक तथ्यात्मक विवरणों में जाना और योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करना अनावश्यक हो गया है। उसी के अनुसार निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।"

ग

(जोर दिया गया)

64. डिजी केबल नेटवर्क (उपरोक्त) में, डिजिटल पता प्रणाली में एक बहु-प्रणाली संचालक के रूप में काम करने के लिए अपीलार्थी को दी गई अनुमति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि गृह मंत्रालय ने अपीलार्थी को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने रद्द करने के आदेश की चुनौती को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों की एक प्रति दायर की। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व-सैनिक सुरक्षा सेवा (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुमति को रद्द करने के आदेश के पारित होने से पहले अपीलार्थी किसी भी पूर्व सूचना का दावा करने का हकदार नहीं था: "16. भारत संघ द्वारा दायर नोट को पढ़ने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप अनुमति रद्द कर दी गई, हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी रद्द करने के आदेश को पारित करने से पहले किसी भी पूर्व सूचना का दावा करने का हकदार नहीं था।

डी.

ई.

च

17. दूसरे शब्दों में, हमारा विचार है कि इस मामले में निर्धारित कानून के आलोक में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया था

जी.

इस न्यायालय द्वारा पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं (पी) में

लिमिटेड क्योंकि अपीलार्थी अनुमति रद्द करने से पहले किसी पूर्व सूचना का दावा करने का हकदार नहीं था।"

65. पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं में अवलोकन

(ऊपर) कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में है वह नीति का सवाल है न कि

एच.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अदालतों द्वारा निर्णय लेने के लिए कानून की पुष्टि बहुमत की राय में की गई थी

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (5 जे) बनाम भारत संघ 58

आधार अधिनियम की धारा 33 की संवैधानिक वैधता। 66. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने पूर्व-सैनिक संरक्षण सेवाओं (उपरोक्त) में यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों के निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया है ताकि इस सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सके कि सरकार यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं; और जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होते हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता है।

यूनाइटेड किंगडम में न्यायालयों द्वारा निर्धारित साक्ष्य सिद्धांत को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि पूर्व सैनिकों की टिप्पणियों के दायरे को समझा जा सके।

ग

सुरक्षा सेवाएँ (ऊपर)।

67. जमोरा (सुप्रा) में, जिस जहाज पर कब्जा किया गया था, उसमें माल में प्रतिबंधित पदार्थ था। माल ऑस्ट्रिया सरकार का था, और स्वीडन में आयात किया गया था। जहाज को एक जर्मन को किराए पर दिया गया था, जो ऑस्ट्रियाई सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था, और स्वीडिश मालवाहक केवल लेन-देन में एक भूमिका निभा रहे थे। माँग करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूद है, यानी माँग करने वाले जहाजों का अधिकार इस बात पर निर्णय लेने तक कि क्या इसकी निंदा की जानी चाहिए या रिहा किया जाना चाहिए। माँग के अधिकार की सीमाओं में से एक यह है कि क्षेत्र की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए जहाजों की तत्काल आवश्यकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रिवी काउंसिल ने व्यापक रूप से उद्धृत अवलोकन किया कि:

डी.

ई.

“इन सीमाओं में से पहली के संबंध में, उनके प्रमुखों की राय है कि न्यायाधीश को, एक नियम के रूप में, क्राउन के उचित अधिकारी की शपथ पर बयान को इस प्रभाव से मानना चाहिए कि जिस पोत या सामान की माँग की गई है, वह राज्य की रक्षा, युद्ध के अभियोजन, या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों के संबंध में उपयोग के लिए तत्काल आवश्यक है, जो तथ्य के निर्णायक हैं।

च

[...]

जी.

जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एकमात्र न्यायाधीश होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अवांछनीय होगा कि ऐसे मामलों को अदालत में साक्ष्य का विषय बनाया जाए या अन्यथा सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए।”

58 (2019) 1 एससीसी 1 ए

एच.

651

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

हालाँकि, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर माँग के अधिकार के अपवाद का दावा करते हुए सेना अनुबंध निदेशक द्वारा दायर हलफनामे को तर्क की कसौटी पर रखा। यह देखा गया कि 'कोई संतोषजनक प्रमाण' नहीं था कि इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता था: “उनके लॉर्डशिप की राय में जिस आदेश से अपील की गई थी वह गलत था, इसलिए नहीं कि, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा न्यायालय की अभिरक्षा में जहाजों या वस्तुओं की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसलिए कि न्यायाधीश के सामने कोई संतोषजनक सबूत नहीं है कि ऐसा अधिकार प्रयोग करने योग्य था। का शपथ पत्र

सेना अनुबंध निदेशक, आदेश **XXIX** के शब्दों का पालन करते हुए, केवल यह कहते हैं कि महामहिम की ओर से तांबे की मांग करना वांछित है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए तांबे की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, स्वेन होग्लंड का हलफनामा, जिसका जवाब नहीं दिया गया है, यह दिखाने से दूर है कि कोई वास्तविक मामला था जिस पर मुकदमा चलाया जाना था, तत्काल रिहाई के लिए एक मामले का सुझाव देता है।” (जोर दिया गया) **68**। सिविल सेवा संघों की परिषद (ऊपर) में, मंत्री

ग

डी.

सिविल सेवा ने एक निर्देश जारी किया कि सरकारी संचार मुख्यालय के कर्मचारी ट्रेड यूनियनों का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि निर्देश जारी करने से पहले कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों से परामर्श नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सेवा की शर्तों को बदलने से पहले ट्रेड यूनियनों से परामर्श करना एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा थी।

ई.

69. सरकारी संचार मुख्यालय विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय की एक शाखा है जो यूनाइटेड किंगडम की सेना की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और सरकार के लिए खुफिया संकेत प्रदान करती है। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि क्योंकि “पूर्व परामर्श में एक वास्तविक जोखिम शामिल होगा कि यह [जीसीएचक्यू में] उसी तरह के व्यवधान का कारण बनेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था और जिससे बचने का इरादा था।” हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि आम तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक हैं या नहीं, इसका निर्णय सरकार को करना है न कि अदालतों को। हालांकि, यह अवलोकन योग्य था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया गया था जो निर्णय के निष्पक्षता के नियम से अलग होने की गारंटी देता है यदि

च

जी.

एच.

652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सफलतापूर्वक इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह एक अनुचित प्रक्रिया द्वारा आया था:

“सवाल एक सबूत है। यह निर्णय कि क्या किसी विशेष मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक हैं, सरकार के लिए है न कि अदालतों के लिए; अकेले सरकार के पास आवश्यक जानकारी तक पहुंच है, और किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन यदि निर्णय को सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती है, इस आधार पर कि यह एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया गया है जो अनुचित है, तो सरकार इस बात का सबूत पेश करने के लिए बाध्य है कि निर्णय वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर था। इन दोनों बिंदुओं के लिए अधिकार जमोरा [1916] 2 ए. सी. 77 में पाया जाता है।”

ग

अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन पर, न्यायालय संतुष्ट था कि प्रस्थान उचित था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल थीं।

डी.

70. लॉर्ड स्कारमैन ने अपनी राय में कहा कि द ज़मोरा (उपरोक्त) में टिप्पणियाँ न्यायिक कार्य के त्याग का संकेत नहीं थीं, बल्कि एक संकेत थे कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि यह साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए कि न्यायिक कार्यवाही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हित उत्पन्न होता है: “मेरे स्वामी, इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि जहाँ न्यायिक कार्यवाही में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, अदालत को साक्ष्य के आधार पर कार्य करना पड़ता है। कुछ मामलों में एक न्यायाधीश या जूरी को कानून द्वारा संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है कि ब्याज मौजूद साबित होता है: अन्य में, ब्याज एक कारक है जिस पर कार्यकारी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग की समीक्षा में विचार किया जाना चाहिए। एक बार तथ्यात्मक आधार है

ई.

च

साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि न्यायालय संतुष्ट हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हित मामले के निर्धारण में विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है, न्यायालय क्राउन या उसके जिम्मेदार अधिकारी की राय को स्वीकार करेगा कि उसे पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है, जब तक कि यह दिखाना संभव न हो कि राय ऐसी थी जो क्राउन को सलाह देने वाला कोई भी उचित मंत्री परिस्थितियों में उचित रूप से नहीं कर सकता था।

जी.

रखा है। न्यायिक कार्य का कोई त्याग नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों द्वारा ए के रूप में मान्यता प्राप्त एक सामान्य ज्ञान सीमा है।

एच.

653

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

न्यायसंगत क्या है: और यह सीमा न्यायिक समीक्षा के आधुनिक मामले कानून के सामान्य विकास के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।”

(जोर दिया गया)

साक्ष्य के अवलोकन पर, यह माना गया कि मुख्यालय में काम में गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले शामिल होते हैं, और यदि निर्णय से पहले कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों से परामर्श किया जाता तो सुरक्षा से समझौता किया जाता। लॉर्ड स्कारमैन ने देखा कि मंत्री ने कर्मचारियों से परामर्श नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि संघ द्वारा आयोजित सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मंत्री द्वारा इस निष्कर्ष पर यथोचित रूप से पहुँचा जा सकता था।

ग

71. रहमान (ऊपर) में, अपीलार्थी, एक पाकिस्तानी नागरिक, जिसके माता-पिता ब्रिटिश नागरिक थे, ने यूनाइटेड किंगडम में रहने के लिए अनिश्चितकालीन छुट्टी के लिए आवेदन किया। राज्य सचिव ने उनके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह एक आतंकवादी संगठन के साथ शामिल थे। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूनाइटेड किंगडम से उनका निर्वासन सार्वजनिक भलाई और 'राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में' अनुकूल होगा। विशेष आप्रवासन अपील आयोग ने राज्य सचिव के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कहा कि संभावनाओं के नागरिक संतुलन का मानक संतुष्ट नहीं हुआ था। आयोग ने कहा कि हालांकि यह विवादित नहीं था कि अपीलकर्ता ने प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को प्रायोजन, जानकारी और सलाह प्रदान की थी, जिसमें आतंकवादी प्रशिक्षण शामिल हो सकता है, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि ये कार्य 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा हैं। अपील न्यायालय ने आयोग के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार कर लिया।

डी.

ई.

72. अपील न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा खारिज कर दी गई थी। हैडली के लॉर्ड स्लिन ने अपनी राय में कहा कि: (i) जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके परिवार के देश में रहने का अवसर दांव पर है, और जब पहले से हुई विशिष्ट कार्रवाइयों पर भरोसा किया जाता है, तो यह उचित है कि सबूत का नागरिक मानक लागू किया जाए; (ii) जब राज्य सचिव निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक भलाई के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए, तो वह एहतियाती और निवारक सिद्धांतों का हकदार है। ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर वह यथोचित और आनुपातिक रूप से यह निष्कर्ष निकाल सके कि इस बात की वास्तविक संभावना है कि गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचाती हैं; (iii) राज्य सचिव सुरक्षा खतरे का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। उसके मूल्यांकन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उनका निर्णय उपरोक्त दो आधारों पर समीक्षा के लिए खुला है; और (iv) यह आयोजित किया गया था

च

जी.

एच.

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सिविल सेवा संघ परिषद (उपर्युक्त) कि यदि यह प्रतिवाद किया जाता है कि निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नहीं था, तो सरकार को न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए सबूत पेश करना चाहिए कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर है। हालाँकि, 'वर्तमान मामले में यह मुद्दा नहीं है'।

73. लॉर्ड हॉफमैन ने अपनी राय में कहा कि आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ पर राज्य सचिव की राय से अलग नहीं हो सकता है। अर्थात्, यह सवाल सरकार को तय करना है कि क्या उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के निवासी द्वारा किसी विदेशी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के विपरीत होगा। सिविल सेवा संघ परिषद (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि निर्वासन की वैधता पर निर्णय राज्य के सचिव को स्वीकार नहीं किया जाता है। आयोग को यह निर्धारित करना होगा कि (i) कार्यपालिका की राय के लिए तथ्यात्मक आधार कि निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा; (ii) यदि राज्य के सचिव का निर्णय ऐसा था जिस पर एक उचित मंत्री पहुंचा होता; और (iii) कोई अन्य कानूनी बचाव जो अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

ग

डी.

54. इसका मतलब यह नहीं है कि निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा या नहीं, इस पर पूरा निर्णय गृह सचिव को सौंप दिया जाता है, ताकि "उस उद्देश्य को विफल किया जा सके जिसके लिए आयोग की स्थापना की गई थी": आयोग का निर्णय देखें। यह महत्वपूर्ण है कि कार्यपालिका को सौंपी गई जिम्मेदारी के क्षेत्र को न तो धुंधला किया जाए और न ही अतिरंजित किया जाए। चैंडलर के मामले के संदर्भ में लॉर्ड स्कारमैन द्वारा सटीक सीमाओं का विश्लेषण किया गया था।

ई.

सिविल सेवा संघ परिषद बनाम मंत्री में अपने भाषण में

सिविल सेवा [1985] एसी 374,406. उनके विश्लेषण से पता चलता है कि आयोग कम से कम तीन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है जो चहल के निर्णय से आवश्यक साबित हुए। सबसे पहले,

च

कार्यपालिका की इस राय का तथ्यात्मक आधार कि निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा, साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के लिए यह कहना खुला है कि गृह सचिव की इस राय का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि रहमान कश्मीर में आतंकवाद का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे थे। इस संबंध में

जी.

आयोग की गृह सचिव के मूल्यांकन से अलग होने की क्षमता सीमित हो सकती है, जैसा कि मैं समझाऊंगा, अपीलीय प्रक्रिया में निहित विचारों से, लेकिन ए के सिद्धांत से नहीं।

एच.

655

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

शक्तियों का पृथक्करण। बाद के सिद्धांत का प्रभाव केवल अगले बिंदु के अधीन है, ताकि आयोग को यह कहने से रोका जा सके कि हालांकि गृह सचिव की राय कि श्री रहमान कश्मीर में आतंकवाद का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे थे, एक उचित तथ्यात्मक आधार था, लेकिन यह स्वीकार नहीं करता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के विपरीत था। दूसरा,

आयोग गृह सचिव की राय को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि यह "ऐसा था जिसे क्राउन को सलाह देने वाला कोई भी उचित मंत्री परिस्थितियों में उचित रूप से नहीं मान सकता था।" तीसरा, आयोग को एक अपील उन मुद्दों पर हो सकती है जो किसी भी समय कार्यपालिका के अनन्य प्रांत के भीतर नहीं हैं। एक अच्छा उदाहरण वह सवाल है, जो चहल में ही उठा था कि क्या किसी को निर्वासित करने से कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा क्योंकि इस बात का पर्याप्त जोखिम था कि उसे यातना या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय न्यायशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि क्या निर्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, अनुच्छेद 3 के तहत अधिकारों के लिए अप्रासंगिक है। यदि यातना का खतरा है, तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे से निपटने का कोई अन्य तरीका खोजना चाहिए। पर्याप्त जोखिम मौजूद है या नहीं, यह साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन और भविष्यवाणी का सवाल है। इस तरह के सवाल का जवाब देने में कार्यपालिका को कोई संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है।

ग

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

74. उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं: (i) निर्णय से प्रभावित पक्ष को यह स्थापित करना चाहिए कि निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना अनुचित थी;

च

((ख) राज्य यह दावा कर सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

(iii) न्यायालयों को यह आकलन करना होगा कि क्या प्रस्थान उचित था। इस उद्देश्य के लिए, राज्य को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि सबसे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है; और दूसरा, क्या मामले के तथ्यों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक हैं। इस स्तर पर, न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के घटक के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए जिसे निरस्त करने की मांग की जाती है; और

जी.

एच.

656

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

((iv) राष्ट्रीय सुरक्षा दावे को संतुष्ट करते हुए, न्यायालयों को राज्य के मूल्यांकन और निष्कर्ष को उचित महत्व देना चाहिए। न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर करने वाली व्यापक कार्यवाहियों पर असहमत नहीं हो सकते हैं-यानी, सिद्धांत का संवाल जैसे कि क्या किसी नागरिक द्वारा विदेश में आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तथापि, न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए राज्य के मूल्यांकन की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उसने ठोस सामग्री के माध्यम से साबित किया है कि पीड़ित व्यक्ति के कार्य ऊपर स्थापित सिद्धांतों के भीतर आते हैं।

ग

75. प्रत्यर्थी का यह तर्क कि इसका निर्णय

पूर्व-सैनिक संरक्षण सेवा (ऊपर) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जाएगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं गलत हों। उस मामले में जो सिद्धांत स्पष्ट किया गया था वह यह था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब मामले के तथ्यों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक हों। इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा उन कुछ आधारों में से एक है जिन पर उचित प्रक्रियात्मक गारंटी के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की भागीदारी निष्पक्ष रूप से कार्य करने के राज्य के कर्तव्य को बाधित नहीं करेगी। यदि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने के अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, तो इसे मामले के तथ्यों पर अदालत के समक्ष उचित ठहराया जाना चाहिए। सबसे पहले, राज्य को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। दूसरा, राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (ओं) को निरस्त करना उचित है। विदेशों में न्यायशास्त्र से उभरे ये दो मानक आनुपातिकता मानक से मिलते-जुलते हैं। पहला परीक्षण वैध लक्ष्य प्रांग जैसा दिखता है, और औचित्य का दूसरा परीक्षण आवश्यकता और संतुलन प्रांग जैसा दिखता है।

डी.

ई.

च

जी. 2 आनुपातिकता मानक का अनुप्रयोग

76. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से निरस्त करने की अनुमति नहीं देती हैं, अब हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या प्रक्रियात्मक गारंटी पर प्रतिबंध आनुपातिकता मानक के अनुप्रयोग पर उचित है। आधुनिक दंत चिकित्सा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित आनुपातिकता मानक इस प्रकार है:

जी.

(i) किसी अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य (वैध लक्ष्य चरण) होना चाहिए।

एच.

657

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

(ii) इस लक्ष्य (उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरण) को आगे बढ़ाने के लिए उपाय एक उपयुक्त साधन होना चाहिए।

(iii) उपाय कम से कम प्रतिबंधात्मक और समान रूप से प्रभावी (आवश्यकता चरण) होना चाहिए।

(iv) इस उपाय का सही धारक (संतुलन चरण) पर असमान प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

जी. 2 (ए) वैध लक्ष्य चरण

77. इस उद्देश्य के लिए अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले उद्देश्य की वैधता के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए लक्ष्य का पर्याप्त महत्व होना चाहिए। इस स्तर पर, राज्य को यह साबित करने के बोझ का निर्वहन करना आवश्यक है कि कार्रवाई एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में है। राज्य को यह साबित करने के अतिरिक्त बोझ का निर्वहन करने की भी आवश्यकता है कि कार्रवाई वास्तव में उस वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में है जिसे पूरा करने का दावा किया जाता है। भारत संघ का दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी की गोपनीयता के हित में कारणों और दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर राज्य को यह साबित करना आवश्यक है कि गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा वैध उद्देश्य हैं, और गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को गैर-प्रकटीकरण द्वारा पूरा किया जाता है।

ग

डी.

78. इस स्तर पर, अदालत को इस सीमा प्रश्न की जांच करनी होती है कि क्या एक संवैधानिक लोकतंत्र में, एक मौलिक अधिकार को कानून या कार्रवाई के अंतर्निहित उद्देश्य को प्राप्त करने तक सीमित किया जा सकता है।⁵⁹ उचित उद्देश्य निर्धारित करने के मानदंड एक कानूनी प्रणाली से दूसरी में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान एक सामान्य सीमा खंड निर्धारित करता है जो सभी मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए सामान्य आधार निर्धारित करता है।⁶⁰ भारतीय संविधान एक सामान्य सीमा खंड निर्धारित नहीं करता है। भाग III के कुछ प्रावधानों जैसे कि अनुच्छेद 19 और 25 में एक विशिष्ट उद्देश्य आधारित सीमा खंड है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन प्रावधानों में एक स्पष्ट सीमा खंड नहीं है, वे निरपेक्ष हैं। जिन अन्य अधिकारों की कोई स्पष्ट सीमा खंड नहीं है, उन्हें संविधान के प्रावधानों के निहित पठन के माध्यम से सीमित किया जा सकता है। हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है कि संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार प्रासंगिक अलगाव में रहते हैं और जीवित रहते हैं। प्रत्येक से जुड़ा हुआ है

ई.

च

जी.

59 अहरोन बराक (संख्या 38) 247; आधुनिक दंत चिकित्सा में न्यायमूर्ति सीकरी (पैराग्राफ 55)

60 अनुच्छेद 26 (1) में कहा गया है कि मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित एक खुले और लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकारों की सीमा उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए।

एच.

658

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

दूसरा। इसलिए, पूरे पाठ को कैनवास के साथ अर्थ और सामग्री में विकसित होना पड़ता है जो टेपेस्ट्री धारण करता है।

79. अहरोन बराक का तर्क है कि अधिकारों की सीमा के लिए उचित उद्देश्य के स्वीकृत आधारों में से एक जनहित (या सार्वजनिक भलाई) है।⁶¹ हालांकि इस तरह के उद्देश्य का अस्तित्व कभी भी विवाद में नहीं है, लेकिन जनहित की सामग्री स्पष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि जनहित को समाज द्वारा साझा न्याय और सहिष्णुता की धारणाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अदालतों को यह पहचानते हुए कि क्या उद्देश्य वैध है, प्रमुख आवेगों के दायरे में नहीं आना चाहिए, बल्कि संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि, न्यायालय को अनिवार्य रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह निर्णय लेने और नीति बनाने के बीच की बारीक रेखा को पार न करे। संवैधानिक लोकतंत्र में कुछ उद्देश्य लोक हित के बिल्कुल विरोधी होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसका अर्थ और इसका समर्थन करने वाले मूल्य समय के साथ विकसित होते हैं। न्यायालय को उद्देश्य निर्धारित करते समय इस तरह के घटनाक्रमों से अवगत होना चाहिए और संविधान को सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में पढ़ना चाहिए-इतिहास और व्याख्या के समय सामाजिक परिवर्तन की संभावना दोनों को ध्यान में रखते हुए।

ग

डी.

80. संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा को उन आधारों में से एक के रूप में निर्धारित करता है जिनका उपयोग अनुच्छेद 19 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अधिकारों को यथोचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, संविधान के अन्य प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आपातकालीन स्थितियों के दौरान सिद्धांतों से विचलन निर्धारित करते हैं।⁶² इसी तरह, सूचना की गोपनीयता और गोपनीयता अब ऐसे मूल्य हैं जिन्हें संविधान में पढ़ा गया है, विशेष रूप से न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) (ऊपर) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियमन को देखते हुए। इस प्रकार, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियात्मक अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त वैध लक्ष्य हैं।

ई.

च

(I) गोपनीयता और आई. बी. रिपोर्ट

81. राज्य को अब यह साबित करना होगा कि राज्य की कार्रवाई इन दो उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। एमएचए ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा करने के एमबीएल के अनुरोध के जवाब में कहा कि कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट "गुप्त" प्रकृति की होती है। एमएचए ने एक सामान्य दावा किया है कि जांच एजेंसियों की सभी रिपोर्ट गोपनीय हैं। हम स्वीकार नहीं कर सकते

जी.

61 अहरोन बराक (संख्या 38) 289

62 संविधान का अनुच्छेद 359 ए

एच.

659

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ऐसा तर्क। सी. बी. आई. और आई. बी. जैसी जांच एजेंसियों को कई कारणों से असंख्य कर्मियों और संस्थाओं की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता होती है। निजी व्यक्तियों और राज्य के बीच संपर्क बढ़ा है जिसके कारण खुफिया एजेंसियों की भागीदारी भी बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट केवल तथ्य-खोज रिपोर्ट नहीं होती हैं। जैसा कि यह नीचे दी गई सामग्री के निष्कर्षण से स्पष्ट होगा, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट टिप्पणियाँ करती हैं और व्यक्तियों के आचरण पर निष्कर्ष प्रदान करती हैं जिन पर निर्णय लेने वाले प्राधिकरण द्वारा भरोसा किया जाता है। यह तर्क देना कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में गोपनीय जानकारी

हो सकती है, एक बात है लेकिन यह तर्क देना कि ऐसी सभी रिपोर्ट गोपनीय हैं, दूसरी बात है। इस तरह का तर्क गलत है और इसे संवैधानिक मूल्यों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट व्यक्तियों और संस्थाओं के जीवन, स्वतंत्रता और पेशे पर निर्णयों को प्रभावित करती है, और ऐसी रिपोर्टों को प्रकटीकरण से पूर्ण प्रतिरक्षा देना एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के विरोधी है।

ग

(II) राष्ट्रीय सुरक्षा

डी.

82. एमएचए ने यह भी राय दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रासंगिक सामग्री का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या अदालत इस निष्कर्ष की न्यायिक रूप से समीक्षा कर सकती है, और यदि कर सकती है, तो इस तरह की समीक्षा की सीमा। हमें यह आकलन करने से पहले कि क्या कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा दावों की न्यायिक समीक्षा की सीमा पर न्यायशास्त्र का उल्लेख करना चाहिए।

ई.

83. अब यह तय हो गया है कि अदालतें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का सहारा नहीं लेती हैं जब यह दावा किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ हैं

शामिल हैं। मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ 63 में, एक तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा सीमित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिए जाने पर राज्य को अनुमति मिल जाती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य को शपथ पत्र पर अभिवचन करना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि सूचना के प्रकटीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होगा। अदालत ने कहा:

च

जी.

“50. बेशक, भारत का प्रत्यर्थी-संघ तब जानकारी प्रदान करने से इनकार कर सकता है जब संवैधानिक विचार मौजूद हों, जैसे कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, या जब किसी विशिष्ट कानून के तहत कोई विशिष्ट प्रतिरक्षा हो। हालांकि, यह अनिवार्य है

63 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 985

एच.

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

राज्य को न केवल इस तरह की संवैधानिक चिंता या वैधानिक प्रतिरक्षा का विशेष रूप से अनुरोध करना चाहिए, बल्कि उन्हें हलफनामे पर न्यायालय में भी इसे साबित और उचित ठहराना चाहिए। प्रत्यर्थी-भारत संघ को अनिवार्य रूप से अनुरोध करना चाहिए और उन तथ्यों को साबित करना चाहिए जो इंगित करते हैं कि मांगी गई जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करेगा। उन्हें अदालत के समक्ष अपने रुख को उचित ठहराना चाहिए। राज्य द्वारा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान न्यायालय को मूक दर्शक नहीं बनाता है।” मुद्दा यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से संबंधित निष्कर्ष न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है या नहीं। बल्कि यह सबूत के मानक पर है जिसे राज्य द्वारा यह साबित करने के लिए जारी किया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। यह आवश्यक है कि हम इस मुद्दे का विश्लेषण

शुरू करने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द के अर्थ और निहितार्थ को समझें। इस न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सख्त शब्दों में परिभाषित करना संभव नहीं है। 64 राष्ट्रीय सुरक्षा के कई पहलू हैं, जिनमें से कुछ को अनुच्छेद 19 (2) के तहत मान्यता प्राप्त है।

ग

संविधान से। पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं (ऊपर) में, ए

डी.

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा वाक्यांश में 'सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक स्थिरता और शक्ति, पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक सामंजस्य और बाहरी शांति जैसे कारक शामिल होंगे। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 65 में बहुमत के लिए लिखते हुए 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा' के क्षेत्रों का सीमांकन किया क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 19 में जगह पाते हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'राज्य की सुरक्षा' अभिव्यक्ति को 'सार्वजनिक व्यवस्था' के खिलाफ उन अपराधों की एक विशिष्ट श्रेणी को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को कम करना है या

ई.

इसे उखाड़ फेंकना '। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 66, न्याय

एम हिदायतुल्ला (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने 'राज्य की सुरक्षा', 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक अव्यवस्था' अभिव्यक्तियों को अलग किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विकार सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं: 55. इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस न्यायालय के फैसलों में (पहले उद्धृत) "सार्वजनिक व्यवस्था" को "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझने के लिए कहा गया था, "कानून और व्यवस्था" भी उनकी तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है।

च

जी.

64 ए. के. रॉय बनाम भारत संघ, (1982) 1 एस. सी. सी. 271 65 1950 एस. सी. सी. 436

एच.

66 आकाशवाणी 1966 एससी 740 ए

661

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

"सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करता है। तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह देखना आसान होता है कि कोई अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सुरक्षा को नहीं।

राज्य से। "कानून और व्यवस्था का रखरखाव" अभिव्यक्ति का उपयोग करके जिला मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई के क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और भारत रक्षा नियमों में एक खंड जोड़ रहे थे।

(जोर दिया गया)

84. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अभिव्यक्ति का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। जबकि अदालतों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सार्वजनिक व्यवस्था से वैचारिक रूप से अलग करने का प्रयास किया है, अभिव्यक्ति की एक पाठ्यपुस्तक परिभाषा निर्धारित करना असंभव (और शायद मूर्खतापूर्ण) है जो अदालतों को यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या तथ्यात्मक स्थिति वाक्यांश के अर्थ के भीतर आती है। वाक्यांश संदर्भ से अपना अर्थ प्राप्त करता है। राज्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे व्यापक वैचारिक शब्दों में अपने उद्देश्य की पहचान करना पर्याप्त नहीं है। बल्कि, राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह ठोस सामग्री प्रस्तुत करके यह साबित करे कि खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। यह आकलन करना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या ऐसी राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इस तरह के निष्कर्ष के लिए भौतिक समर्थन के बिना दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या राज्य प्रामाणिक तरीके से दावा करता है। न्यायालय को यह निर्धारित करके उद्देश्य के दावे की वैधता का आकलन करना चाहिए कि (i) क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है; और (ii) क्या एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति सामग्री 67 के आधार पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति मानक जो किसी कार्रवाई की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए सबसे निचले मानकों में से एक है, का उपयोग ऐसे दावों के प्रति उनकी अव्यावहारिक धारणा के कारण सभी न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दावों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें मानती हैं कि यह तय करने के लिए राज्य सबसे अच्छी स्थिति में है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को पूरा किया जाएगा। न्यायालय राज्य को अपनी राय बनाने के लिए उचित सम्मान की अनुमति देता है लेकिन सीमित आधारों पर राय की समीक्षा करता है कि क्या

ग

डी.

ई.

च

जी.

67 न्यायिक समीक्षा का यह मानक उस मानक से लिया गया है जो राष्ट्रपति/राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की न्यायसंगतता की सीमित सीमा पर निर्धारित किया गया है। बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ, (2010) 6 एस. सी. सी. 331 में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ लें: अनुच्छेद 79।

एच.

662

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सामग्री और निष्कर्ष के बीच संबंध है। न्यायालय राज्य के फैसले का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकता है कि पहचाने गए उद्देश्य से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होगा। यह कार्यकारी शाखा है न कि न्यायिक शाखा जिसे यह आकलन करने के लिए भारत के भू-राजनीतिक संबंधों की जानकारी है कि क्या कोई कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। 85. अब हम यह आकलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या मामले के तथ्यों पर, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि कार्रवाई गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आगे बढ़ाने में है, जैसा कि तर्क दिया गया है।

(III) सीलबंद आवरण को खोलना

86. 2010 में, एमबीएल ने समाचार और वर्तमान मामलों के टेलीविजन चैनल 'मीडिया वन' को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन को सुरक्षा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा यदि आवेदक प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र है। 68 एमबीएल का आवेदन सुरक्षा मंजूरी के लिए भेजा

गया था।केंद्रीय जांच ब्यूरो 69 ने टिप्पणी की कि एमबीएल के खिलाफ रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। हालाँकि, इंटेलिजेंस ब्यूरो 70 ने एमबीएल के खिलाफ निम्नलिखित प्रतिकूल टिप्पणी की:

ग

डी.

(i) एमबीएल 'मध्यम डेली' से निकटता से जुड़ा हुआ है जिसका संबंध जमात-ए-इस्लामी 71 से है;

ई.

((ii) 'मध्यम डेली' द्वारा किए गए लेखों का कार्यकाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रकृति का था; (iii) आवेदक के कुछ प्रमुख अधिकारी जे. ई. आई.-एच. से जुड़े थे; और

(iv) प्रस्तावित टीवी चैनल जे. ई. आई./एच. की विचारधारा का समर्थन कर सकता है यदि उसे संचालित करने की अनुमति दी जाए।

च

87. आईबी ने जे. ई. आई.-एच. की कथित भूमिका और गतिविधियों पर भी एक नोट प्रस्तुत किया। नोट में कहा गया है:

(i) जे. ई. आई.-एच. का गठन 1941 में अल्लाह के शासन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद -

जी.

68 अपलिकिंग दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 9.2 और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 8.2

69 "सीबीआई "70" आईबी "

एच.

71 " जे. ई. एल./एच "

663

मध्यम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

जे. ई. आई. ने भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में इकाइयों का गठन किया। जे. ई. आई.-एच. धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध करता है; (ii) जे. ई. आई.-एच. पर प्रतिबंध लगा दिया गया था: (i) 1955 में कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए। 1955 में प्रतिबंध हटा लिया गया था; (ii) 1975 में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम 1971 के तहत। 1977 में प्रतिबंध हटा लिया गया था; और (iii) 1992 में, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 72 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में प्रतिबंध को रद्द कर दिया;

(iii) जे. ई. आई.-एच. आधिकारिक और गुप्त माध्यमों के माध्यम से देश में इस्लामी संस्थानों को विदेशी धन आकर्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; और

ग

(iv) जे. ई. आई.-एच. अपने प्रकाशन के माध्यम से, मध्यम दैनिक "अमेरिका विरोधी प्रचार में लिप्त होने के अलावा भारत की विदेश नीति की आलोचना करता रहा है। यह सुरक्षा एजेंसियों/न्यायपालिका की भी आलोचना करता रहा है और अक्सर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से समाचार प्रस्तुत करता है। पता चला है कि जे. ई. आई., केरल के वरिष्ठ पदाधिकारी एक टीवी चैनल शुरू करने के लिए खाड़ी से हवाला चैनलों के माध्यम से धन जुटा रहे हैं।"

डी.

88. एम. एच. ए. ने रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि ये टिप्पणियां सुरक्षा के आधार पर अनुमति से इनकार करने के लिए इतनी प्रबल रूप से प्रतिकूल प्रकृति की नहीं थीं, विशेष रूप से जब आवेदक बारह संस्करणों के साथ एक समाचार पत्र का संचालन कर रहे थे। मध्यम डेली पर आई. बी. की लेखों के 'कार्यकाल' पर रिपोर्ट नीचे दी गई है:

ई.

“मध्यम डेली 12 संस्करण (केरल में 6 स्थानों, कर्नाटक में 2 और सऊदी अरब, कतर, बहरीन और दुबई में 4 स्थानों से प्रकाशित) प्रकाशित करता है, जो जे. ई. आई./एच. द्वारा संचालित इस्लामिक पब्लिशिंग हाउस, कोझिकोड, केरल द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जिन समाचार पत्रों का संयुक्त प्रसार 1.75 लाख है, उनका उपयोग जे. ई. आई./एच. द्वारा प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है।

च

मुसलमान समुदाय। यह भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव को उजागर करता रहा है। हाल ही में उन्होंने

जी.

बैंगलोर बम विस्फोट में मुख्य आरोपी [.] और उनके परिवार के सदस्यों पर कथित लक्षित हमला और कलामस्सेरी बस जलाने के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए [.] के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तीखी आलोचना की और इसकी तुलना [.]

हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ कथित नरम रवैया अपनाया गया

72 “यूएपीए ”

एच.

664 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

देश में बम विस्फोटों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार।”

(जोर दिया गया)

89. 2014 में, जब एमबीएल द्वारा टीवी चैनलों मीडिया-वन लाइफ और मीडिया वन ग्लोबल को अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए फिर से सुरक्षा मंजूरी मांगी गई थी, तो आईबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि ताजा पूछताछ उन मुद्दों की पुष्टि करती है जिन्हें पहले चिह्नित किया गया था। ताजा पूछताछ 'मीडिया वन टीवी द्वारा हाल ही में प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री की जांच' पर आधारित थी। मीडिया वन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री की जांच पर, आईबी ने राय दी कि मीडिया-वन: (i) जे. ई. आई.-एच. की विचारधारा का प्रचार करने की प्रवृत्ति रखता है; (ii) भारत के सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को गलत तरीके से चित्रित करता है; (iii) सरकारी नीतियों की अत्यधिक आलोचना करता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और उग्रवाद से जुड़े कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के लिए।

ग

90. एम. एच. ए. ने उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आई. बी. से नई टिप्पणियां मांगी हैं। बाद की रिपोर्ट में आई. बी. ने तीन निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले, कि एमबीएल के लिए वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत उन शेयरों के माध्यम से है जिनमें जे. ई. आई./एच. कैडरों और सहानुभूति रखने वालों ने कथित तौर पर निवेश किया है। आईबी ने एमबीएल में निवेश करने वाले शेयरधारकों की एक व्यापक सूची प्रस्तुत की। हमने शेयरधारकों की गोपनीयता और गोपनीयता की रक्षा के लिए उनकी सूची नहीं निकाली है। दूसरा, उस पूछताछ ने पुष्टि की है कि मीडिया वन उत्तेजक कार्यक्रम प्रसारित करता है जैसे कि: (i) 5 अगस्त 2015 को, चैनल ने कथित तौर पर आतंकवाद से संबंधित मामलों से निपटने में दोहरे मानकों को अपनाने के लिए भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास किया; (ii) यह दुनिया भर में मुसलमानों के दुख के लिए अमेरिका और इजराइल को

दोषी ठहराता है; और (iii) एमबीएल 'प्रबोधानम वीकली' का प्रकाशन, अपने संपादकीय के माध्यम से मौलिक इस्लामी दृष्टिकोण का प्रचार करता है।

डी.

ई.

च

91. 24 जुलाई 2014 को, एक सीओओ ने सिफारिश की कि 'मीडिया-वन लाइफ' और 'मीडिया वन ग्लोबल' को अपलिक और डाउनलिक करने के प्रस्तावों के संबंध में सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया जा सकता है, और 2011 और 2014 में आईबी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी वापस ली जा सकती है। एमएचए ने नई टिप्पणियां मांगी और इस पर चर्चा करने के लिए कई सीओओ बैठकें आयोजित की गईं। 26 अगस्त 2015 को, एम. आई. बी. ने 'मीडिया वन लाइफ' को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति दी।

जी.

92. हालांकि, 22 जनवरी 2015 को, सीओओ ने गैर-समाचार और वर्तमान मामलों के टीवी चैनल मीडिया-वन लाइफ और मीडिया-वन ग्लोबल को अपलोड/डाउनलिक करने के दो प्रस्तावों (ए) को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने की सिफारिश की।

एच.

665

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

(ख) दो निदेशकों की नियुक्ति के लिए। हालांकि, यह ध्यान दिया गया कि 2011 में दी गई सुरक्षा मंजूरी को वापस नहीं लिया जा सकता है। सी. ओ. ओ. की बैठक के कार्यवृत्त इस प्रकार हैं:

“गृह मंत्रालय ने 30.6.2015 पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे जो प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सुरक्षा संबंधी मापदंड को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। सी. ओ. ओ. ने महसूस किया कि कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ प्रतिकूल सूचनाएँ गंभीर प्रकृति की हैं (कट्टरपंथी संगठन के साथ संबंध) और गृह मंत्रालय के नीति दिशानिर्देशों की धारा संख्या 13 में उल्लिखित सुरक्षा मूल्यांकन मानकों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, सी. ओ. ओ. ने कहा कि नीति में कहा गया है कि एम. एच. ए. द्वारा दी गई सुरक्षा मंजूरी का आमतौर पर संभावित प्रभाव होगा जब तक कि संबंधित मंत्रालय द्वारा इस मामले में अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

ग

अपने अधिदेश का निर्वहन। इसलिए, **2011** में दी गई सुरक्षा मंजूरी को वापस नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, प्रतिकूल निवेश को देखते हुए कंपनी के भविष्य के विस्तार को रोका जा सकता है।”

डी.

(जोर दिया गया)

93. एमएचए ने सीओओ की सिफारिश के आधार पर इन दोनों प्रस्तावों के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस तरह की सिफारिश पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने वाला एम. एच. ए. का आदेश प्रस्तुत की गई फाइल के साथ संलग्न नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख फाइल के आंतरिक नोटों में मिलता है। ऐसा लगता है कि एमएचए को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एमआईबी ने तब तक मीडिया वन लाइफ को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा, सी. ओ. ओ. की टिप्पणियों के बावजूद कि रद्द करना पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है, एम. आई. बी. ने मीडिया वन और मीडिया वन लाइफ को दी गई अनुमति को रद्द करने के लिए एम. आई. बी. को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया। एम. आई. बी. ने एम. एच. ए. से कारण दर्शाओ नोटिस के खिलाफ एम. बी. एल. के जवाब पर विचार करने का अनुरोध किया। इस संबंध में, एम. एच. ए.

ने पाया कि हालांकि उसने मौजूदा समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल 'मीडिया वन' की सुरक्षा मंजूरी वापस नहीं ली थी, लेकिन एम. आई. बी. की कार्रवाई 30 जून 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस तारीख को एम. एच. ए. द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया गया था, उस तारीख तक मीडिया वन और मीडिया वन लाइफ दोनों ही मौजूदा समाचार चैनल थे। एम. एच. ए. की प्रतिक्रिया का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

ई.

च

जी.

“चूंकि एम. एच. ए. ने मौजूदा समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल 'मीडिया वन' की सुरक्षा मंजूरी वापस नहीं ली है, इसलिए यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय है जिसे कारण दशाईं नोटिस जारी करने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराना है

एच.

666

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अनुमति वापस लेने के लिए। साथ ही, चूंकि एम. एच. ए. ने अपने अधिदेश के निर्वहन में दिशानिर्देशों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के लिए कार्रवाई करने के लिए दिनांक 2 के दिशानिर्देशों में नोडल मंत्रालय को लाभ दिया है और एम. आई. बी. ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि एम. एच. ए. ने दिनांक 1 के ओ. एम. के माध्यम से दी गई सुरक्षा मंजूरी को वापस नहीं लिया है। यदि नोडल मंत्रालय की कार्रवाई गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी, तो यह प्रभाव पड़ेगा। हम केवल उन प्रस्तावों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर 27.1.2016 पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था, और बता सकते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने जनादेश के निर्वहन में SCN जारी किया है और वह अपनी कार्रवाई का बचाव कर सकता है। के रूप में

ग

मंजूरी से इनकार करने के कारण को साझा करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इनकार खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर आधारित है जो प्रकृति में गुप्त हैं और आवेदक को इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

डी.

एमएचए के जवाब में आगे कहा गया है कि सुरक्षा मंजूरी को खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था जो गुप्त हैं और आवेदक को इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।’

94. 11 सितंबर 2019 को, एम. आई. बी. ने मीडिया वन लाइफ को दी गई अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमति को रद्द कर दिया। एमबीएल ने निरसन के खिलाफ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। एमएचए ने आईबी से एमबीएल के प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी देने का अनुरोध किया। आईबी ने निष्कर्ष निकाला कि निवेश मापदंडों को आकर्षित करते हैं (क्र. सं. राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए 25 जून 2018 को जारी दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित संख्या 20 और 21)। आई. बी. ने निम्नलिखित दो प्रतिकूल टिप्पणियां कीं:

ई.

च

(ii) आय का मुख्य स्रोत: एम. बी. एल. की आय का मुख्य स्रोत जे. ई. आई.-एच. के संग्रहों द्वारा अपने समर्थकों के माध्यम से निवेश किए गए शेयर हैं। निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्य जे. ई. आई.-एच. के समर्थक हैं; और

जी.

(ii) "स्थापना-विरोधी रुख: समझा जाता है कि मीडिया वन चैनल यू. ए. पी. ए., सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने प्रतिष्ठान विरोधी रुख का समर्थन कर रहा है।

73 "2018 दिशानिर्देश "

एच.

667

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

सरकार की विकासात्मक परियोजनाएं, मुठभेड़ हत्याएं, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, सी. ए. ए./एन. पी. आर./एन. आर. सी.। 95. 2018 के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से ध्यान (i) राष्ट्र की एकता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संरक्षण और अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित मामलों पर है और (ii) आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और देश और उसके नागरिकों के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर है। खंड 3.2 में कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ एम. आई. बी. से उत्पन्न होने वाले क्षेत्र के संवेदनशील प्रस्तावों का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। खंड 4 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सत्यापन "रिकॉर्ड जांच/क्षेत्र पूछताछ और कंपनी, संस्था और उससे जुड़े व्यक्तियों की जांच के लिए अन्य साधनों" के माध्यम से किया जाएगा।" प्रावधान में कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय (इस मामले में, एम. आई. बी.) से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, एम. एच. ए. सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी मांगेगा। खंड 5 में निर्धारित किया गया है कि खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अनुलग्नक सी में निर्धारित सुरक्षा मानकों की सूची के आधार पर एक मूल्यांकन करेंगी। मूल्यांकन रिपोर्ट किए गए खतरे, भौतिककरण की संभावना और समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। अनुलग्नक सी सुरक्षा मापदंडों को निर्धारित करता है। एस. एल. नंबर 13 का

ग

डी.

अनुलग्नक में लिखा है: "टेरर फंडिंग, अंडरवर्ल्ड के साथ वित्तीय संबंध, ड्रग कार्टेल, क्राइम सिंडिकेट्स।" क्र. 20 को "भारत में धार्मिक धर्मांतरण गतिविधियों में भागीदारी" के रूप में पढ़ा जाता है, और क्र. संख्या 22 को "जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सुरक्षा चिंताओं या सुरक्षा प्रणालियों का जानबूझकर या प्रणालीगत उल्लंघन" के रूप में पढ़ा जाता है।

ई.

96. एमबीएल ने मीडिया-वन चैनल को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। एम. आई. बी. ने नवीनीकरण के लिए आवेदन को सुरक्षा मंजूरी के लिए एम. एच. ए. को भेज दिया। एमएचए ने कहा कि अगर कंपनी और उसके निदेशकों को पहले सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है तो अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करने का कोई कारण नहीं है:

च

"3. यह देखा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय नियमित आधार पर एम. एच. ए. को सुरक्षा मंजूरी के नवीनीकरण के प्रस्ताव भेज रहा है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी और उसके निदेशकों को सुरक्षा मंजूरी देने से पहले ही इनकार कर दिया गया है, यदि एम. एच. ए. द्वारा किसी कंपनी और उसके निदेशकों को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है। इसके नवीनीकरण पर विचार करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि यह इंगित करने के लिए विशिष्ट कारण न हों कि स्थिति बदल गई है।

जी.

एच.

668

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सुरक्षा मंजूरी दिशानिर्देश दिनांक 25.06.2018, पैरा 7.4 में कहा गया है कि एम. एच. ए. द्वारा सुरक्षा मंजूरी पर निर्णय का संभावित प्रभाव तब तक रहेगा जब तक कि संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने अधिदेश के निर्वहन में अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से तत्कालीन गृह सचिव और सूचना और प्रसारण सचिव की दिनांक 1 की बैठक में एम. आई. बी. के इस सवाल के जवाब में स्पष्ट किया गया था कि क्या एक क्षेत्र में कंपनी/व्यक्तिगत संस्थाओं को सुरक्षा मंजूरी वापस लेना अन्य क्षेत्रों में भी निकासी के बराबर होगा।

चूंकि एम. आई. बी. को उपरोक्त कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है, इसलिए सुरक्षा मंजूरी दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों पर नए सिरे से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया जा सकता है कि जिन मामलों में कंपनी को सुरक्षा मंजूरी से पहले ही इनकार कर दिया गया है, वहां सुरक्षा मंजूरी के नवीनीकरण के प्रस्तावों को नियमित तरीके से गृह मंत्रालय को तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि इसके लिए पर्याप्त और उचित कारण न हों।"

डी.

97. यह संबोधित करने से पहले कि क्या प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम उस बेपरवाह तरीके का उल्लेख करें जिसमें भारत संघ ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा किया है। केवल यह दावा करने के अलावा कि राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे और हमारे समक्ष प्रस्तुतियों दोनों में, भारत संघ ने यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया कि खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कैसे होगा। भारत संघ ने इस न्यायालय द्वारा दोहराये जाने के बावजूद इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि न्यायिक समीक्षा को केवल 'राष्ट्रीय सुरक्षा' वाक्यांश के उल्लेख पर बाहर नहीं रखा जाएगा। राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग कानून के तहत प्रदान किए गए नागरिक उपचारों से इनकार करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहा है। यह कानून के शासन के अनुकूल नहीं है।

ई.

च

98. जे. ई. आई.-एच. के साथ इसके कथित संबंध और इसके कथित प्रतिष्ठान विरोधी रुख के कारण एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि एमबीएल जे. ई. आई.-एच. से जुड़ा हुआ है, आईबी ने एमबीएल के दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित लेखों के 'कार्यकाल' और एमबीएल के शेयरधारिता पैटर्न पर भरोसा किया है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जे. ई. आई.-एच. का प्रतिष्ठान विरोधी रुख है, आई. बी. ने पूरी तरह से उन कार्यक्रमों पर भरोसा किया है जो मीडिया-वन द्वारा प्रसारित किए गए थे। कुछ ए

जी.

एच.

669

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

आई. बी. की रिपोर्ट में जिन विचारों पर प्रकाश डाला गया था कि एम. बी. एल. का प्रतिष्ठान विरोधी रुख है, वे हैं (i) यह सुरक्षा बलों और न्यायपालिका को गलत तरीके से चित्रित करता है; (ii) इसने देश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया और इसकी तुलना बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल हिंदुओं के प्रति राज्य के कथित नरम रवैये से की; और (iii) यू. ए. पी. ए., सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, सरकार की विकासात्मक परियोजनाओं, मुठभेड़ हत्याओं, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और सी. ए. ए./एन. पी. आर./एन. सी. पर इसकी टिप्पणियां।

99. महत्वपूर्ण रूप से, जे. ई. आई.-एच. के कथित समर्थक शेयरधारकों की सूची के संबंध में, फाइल में शेयरधारकों और जे. ई. आई.-एच. के बीच कथित संबंध पर कोई सबूत नहीं है। आई. बी. की रिपोर्ट विशुद्ध रूप से उन सूचनाओं से ली गई है जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। गोपनीयता के आधार को आकर्षित करने के लिए इस जानकारी के बारे में कुछ भी 'गोपनीय' नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य केवल यह आरोप लगाकर गैर-प्रकटीकरण द्वारा पूरा किया जाएगा कि एमबीएल जे. ई. आई.-एच. के साथ शामिल है जो कथित आतंकवादी संबंधों वाला एक संगठन है। जबकि हमने ऊपर माना है कि अदालतों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा वाक्यांश को परिभाषित करना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण होगा, हम यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे कम हवा में नहीं किए जा सकते हैं। इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन करने वाली सामग्री होनी चाहिए। फाइल पर सामग्री और ऐसी सामग्री से लिए गए निष्कर्ष का कोई संबंध नहीं है। इस जानकारी का खुलासा न करना जनहित के किसी भी पहलू के हित में नहीं होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत कम होगा। सामग्री के अवलोकन पर, कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के हित में होगा।

ग

डी.

ई.

जी. 2 (बी) उपयुक्तता

च

100. हम आनुपातिकता मानक के बाद के पहलुओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह मानते हुए भी कि की गई कार्रवाई गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। आनुपातिकता विश्लेषण के दूसरे भाग में राज्य को यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि क्या उपयोग किए गए साधन उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं। इस स्तर पर, अदालत को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या साधन, यदि साकार हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के हितों की रक्षा करने की संभावना बढ़ जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि चुने गए साधन ही राज्य की कार्रवाई के उद्देश्य को साकार करने में सक्षम होने चाहिए। विश्लेषण का यह चरण दक्षता मानक निर्धारित नहीं करता है। यह पर्याप्त है यदि उपयोग किए गए साधन उन कई तरीकों में से एक हैं जिनके द्वारा उद्देश्य

जी.

एच.

670

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

इसे प्राप्त किया जा सकता है, भले ही यह उद्देश्य को केवल आंशिक रूप से प्रभाव देता हो। 74 ओक्स (ऊपर) के मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपनाए गए साधन "मनमाने, अनुचित या तर्कहीन संबंध पर आधारित" नहीं होने चाहिए। यदि राज्य संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य साधनों का उपयोग करता है तो इस खंड के तहत

आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि चुने गए साधन 'सर्वोत्तम संभव साधन' होने चाहिए, फिर भी साधनों को संविधान के समूह से गुजरना चाहिए।

101. गृह मंत्रालय ने केवल सीलबंद लिफाफे में अदालत को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया। प्रकटीकरण की इस विधि द्वारा, जिस जानकारी को गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होने का दावा किया जाता है, उसे जनता और दावेदार के सामने प्रकट नहीं करके संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। उपयोग किए जाने वाले साधन आवश्यक रूप से शामिल ब्याज की रक्षा के लिए सबसे अच्छा संभव साधन नहीं हो सकते हैं क्योंकि सीलबंद आवरण प्रक्रिया पूर्ण गैर-प्रकटीकरण के विपरीत आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति देती है। हालाँकि, यह अभी भी उस उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध साझा करता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।

ग

डी.

102. दूसरी ओर, सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों के सारांश का खुलासा न करना भी पहचाने गए उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध साझा नहीं करता है। ए बनाम यूनाइटेड किंगडम 75 में, ई. सी. एच. आर. ने माना कि पक्षों के बीच हमेशा 'हथियारों की समानता' होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि प्रक्रियात्मक गारंटी प्रतिबंधित हैं, तो सीमा को पर्याप्त रूप से प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए। सचिव में

ई.

गृह विभाग बनाम ए. एफ. 76 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए राज्य का, जबकि

ए (उपरोक्त) में ईसीएचआर के फैसले की व्याख्या करते हुए कहा गया कि प्रक्रियात्मक गारंटी का एक 'मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम' है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि 'आवेदक के खिलाफ मामले का सार' एक मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम है जिसका खुलासा किया जाना चाहिए। हम क्रमशः ए. एफ. (ऊपर) और ए. (ऊपर) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ई. सी. एच. आर. की टिप्पणियों से सहमत हैं। एम. एच. ए. ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करके एम. बी. एल. की प्रक्रियात्मक गारंटी को अनुचित बना दिया है। सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का सारांश अनुच्छेद 14 के तहत प्रक्रियात्मक गारंटी का 'मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम' है। कारणों के सारांश का खुलासा नहीं करके, एम. एच. ए. ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अनुचित और मनमाना तरीका अपनाया है।

च

जी.

74 अहरोन बराक (संख्या 38) 305 75 आवेदन संख्या। 3455/05

76 2009] यूकेएचएल 28, (पैरा 62-65, 81))

एच.

671

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

जी. 3 (सी) न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन

103. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (5 जे) (ऊपर) में बहुमत के फैसले ने 'आवश्यकता की मध्यम व्याख्या' को अपनाया जो डेविड बिलचिट्ज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 77 लेखक ने आवश्यकता के मजबूत और कमजोर रूपों के बीच एक मध्यम आधार बनाने की कोशिश की। बिलचिट्ज द्वारा तैयार की गई आवश्यकता के उप-घटक इस प्रकार हैं: 78

(क) क्या अन्य संभावित साधन हैं जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया जा सकता था;

(ख) क्या पहचाने गए वैकल्पिक साधन उद्देश्य को 'वास्तविक और सारवान तरीके से' प्राप्त करते हैं;

ग

(ग) क्या विकल्प की पहचान और राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन मौलिक अधिकारों को अलग तरह से प्रभावित करते हैं; और

(घ) चाहे उपाय और विकल्प की समग्र तुलना (और संतुलन) पर, सरकारी उद्देश्य को साकार करने की डिग्री और मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को देखते हुए विकल्प बेहतर है।

डी.

104. चारकौई बनाम कनाडा (नागरिकता और आप्रवासन) 79 में,

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आप्रवासन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम 2001-80 के तहत निर्धारित निरोध की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक दुर्बलताओं से ग्रस्त है। 2001 के अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को कुछ या सभी जानकारी से वंचित किया जा सकता है जिसके आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया था। कनाडाई सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2001 के अधिनियम के प्रावधान कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम 81 की धारा 7 का अनुचित रूप से उल्लंघन करते हैं क्योंकि प्रभावित व्यक्ति के प्रक्रियात्मक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई साधन तैयार किए बिना गुप्त सामग्री के आधार पर राज्य की कार्रवाई की न्यायिक रूप से समीक्षा की जाती है। अदालत ने यूनाइटेड किंगडम में विशेष अधिवक्ताओं की प्रणाली का उल्लेख किया और कहा कि यह प्रणाली

ई.

च

77 डेविड बिलचिट्ज, 'आवश्यकता और आनुपातिकता: एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर?' में

लियोरा लाजर और अन्य (संस्करण), तर्क अधिकार: तुलनात्मक न्यायिक जुड़ाव (हार्ट)

जी.

2014) 49.

78 आइबीआइडी, पृ. 51.

79 (2007) 1 एससीआर 350

80 "2001 ऐक्ट "

81 कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की धारा 7 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार को मौलिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।

एच.

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

प्रभावित पक्ष के हितों की रक्षा करता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया को तथ्यों और कानून पर न्यायिक निर्धारण के व्यक्ति के अधिकार की न्यूनतम हानि और मामले को जानने और पूरा करने के अधिकार के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।'

105. कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के रहस्यों से जुड़े दावों पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर न्यायशास्त्र का उल्लेख किया और कहा कि अन्य कम प्रतिबंधात्मक साधन थे जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की तरह नियोजित किया जा सकता था। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधनों के विश्लेषण के एक भाग के रूप में, हम भारत और अन्य देशों में उपलब्ध वैकल्पिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं जो उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी सहायता करती हैं और जो प्रभावित पक्ष के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करती हैं।

ग

(I) टोटन का दावा: मुद्दे की गैर-न्यायसंगतता

106. संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों ने माना है कि असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालय को राज्य के रहस्यों के प्रकटीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कार्य करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुप्रयोगों में से एक टोटन दावे के माध्यम से है। टोटन दावे के अनुसार, यदि दावे राज्य के रहस्यों पर आधारित हैं, तो उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाता है। यदि विषय वस्तु राज्य गुप्त का मामला है तो कार्यवाही साक्ष्य के स्तर तक पहुंचने से पहले अभिवचनों पर कार्रवाई को खारिज किया जा सकता है। टोटन दावा, यदि अनुमति दी जाती है, तो पूर्व-खोज चरण में मुकदमे को खारिज करने की अनुमति देता है।

डी.

ई.

(II) बंद सामग्री प्रक्रिया और विशेष अधिवक्ता

107. चहल बनाम यूनाइटेड किंगडम 83 में, गृह सचिव ने अपीलार्थी, एक भारतीय नागरिक और एक सिख अलगाववादी को निर्वासित करने का आदेश जारी किया। निर्वासन आदेश के लिए अपीलार्थी की चुनौती का एक आधार यह था कि हालांकि गृह सचिव का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके जोखिम का प्रभावी निर्धारण गृह कार्यालय के एक आंतरिक सलाहकार पैनल द्वारा उस सामग्री के आधार पर किया गया था जिसका उसे खुलासा नहीं किया गया था। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय 84 ने अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार कर लिया और कहा कि प्रक्रिया ने यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद 5 (4) के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया है।

च

जी.

82 टोटन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 92 यूएस 105, 107 (1876) 83 (1996) 23 ईएचआरआर 413

84 "ईसीएचआर "

एच.

673

मध्यम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

मानवाधिकार। 85 अदालत ने कहा कि अन्य कम प्रतिबंधात्मक तरीके हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रक्रियात्मक न्याय की वैध चिंताओं को समायोजित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। न्यायालय ने उस प्रक्रिया का उल्लेख किया जो कनाडा में कनाडाई आप्रवासन अधिनियम 1976 के तहत लागू की जाती है, जिसके तहत एक संघीय न्यायालय का न्यायाधीश सभी साक्ष्यों की कैमरे में सुनवाई करता है; आवेदक को उनके खिलाफ किए गए मामले का सारांश देते हुए एक बयान प्रदान किया जाता है; और गोपनीय सामग्री का खुलासा एक सुरक्षा-स्वीकृत वकील को किया जाता है जो राज्य के मामले की ताकत का परीक्षण करने में अदालत की सहायता करता है।

108. चहल (ऊपर) में फैसले के जवाब में, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने विशेष आप्रवासन अपील आयोग अधिनियम 1997 पारित किया, जिसने सुरक्षा-स्वीकृत विशेष अधिवक्ताओं के लिए बंद दरवाजों के पीछे होने वाली ठोस कार्यवाही में आवेदक का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त किया। दावेदार को सामग्री का खुलासा नहीं किया जाता है। हालांकि, विशेष अधिवक्ता अदालत के समक्ष पक्ष के हित का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि उन्हें बंद कार्यवाही में गैर-प्रकटीकरण योग्य सुरक्षा साक्ष्य के बारे में दावेदार के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है। सभी उद्देश्यों के लिए, बंद सामग्री की कार्यवाही सीलबंद आवरण प्रक्रिया के समान होती है, सिवाय इसके कि प्रक्रियात्मक गारंटी पर सीमाओं को संतुलित करने के लिए एक प्रतिभूति स्वीकृत वकील नियुक्त किया जाता है। आतंकवाद अधिनियम 2000 इसी तरह की प्रक्रिया निर्धारित करता है। तब से यूनाइटेड किंगडम में अदालतें दीवानी कार्यवाही, अर्ध-आपराधिक कार्यवाही 86 और जनहित प्रतिरक्षा दावों में विशेष अधिवक्ताओं का उपयोग कर रही हैं। 87 विशेष अधिवक्ता दो उद्देश्यों को पूरा करता है: सबसे पहले, बंद सामग्री का अधिकतम संभव प्रकटीकरण करना; और दूसरा, प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण करना और बंद रहने वाली किसी भी सामग्री पर प्रस्तुतियाँ करना। 88

ग

डी.

ई.

च

(III) सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा

109. साक्ष्य अधिनियम कुछ संचार और साक्ष्य के प्रकटीकरण को रोकने वाले नियम निर्धारित करता है। धारा 123 में कहा गया है कि नहीं

85 अनुच्छेद 5 (4): “प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तारी या निरोध द्वारा अपनी स्वतंत्रता से वंचित है, वह ऐसी कार्यवाही करने का हकदार होगा जिसके द्वारा उसकी निरोध की वैधता पर अदालत द्वारा तेजी से निर्णय लिया जाएगा और यदि निरोध वैध नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाएगा।”

जी.

86 रॉबर्ट्स बनाम पैरोल बोर्ड, (2005) 2 एसी 738 87 आर बनाम एच, (2004) एसी 134

88 मार्टिन चेम्बरलेन, विशेष अधिवक्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा में न्यायमित्र

यूनाइटेड किंगडम में कार्यवाही, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लॉ जर्नल, समर 2018, वॉल्यूम। 68, संख्या 3, स्वदेशी कानून पर विशेष अंक (ग्रीष्मकालीन 2018), पृ. 496-510

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

व्यक्ति को राज्य के मामलों से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई भी साक्ष्य देने की अनुमति दी जाएगी। साक्ष्य का खुलासा केवल विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा:

123. राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य।- किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य के किसी भी कार्य से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई भी साक्ष्य देना, सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या रोकेगा जो वह उचित समझे।

धारा 124 में प्रावधान है कि एक लोक अधिकारी को आधिकारिक विश्वास में उसे किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा यदि प्रकटीकरण सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है:

ग

124. आधिकारिक संचार।- कोई लोक अधिकारी नहीं होगा

आधिकारिक विश्वास में उसे किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब वह मानता है कि प्रकटीकरण से सार्वजनिक हितों को नुकसान होगा।

डी.

110. धारा 162 में कहा गया है कि एक गवाह जिसे अदालत में दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है, वह दस्तावेज को पेश करने और स्वीकार करने पर किसी भी आपत्ति के बावजूद अदालत में लाएगा। प्रावधान में प्रावधान है कि आपत्ति का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, अदालत दस्तावेज का निरीक्षण करेगी, जब तक कि यह राज्य के मामलों को संदर्भित नहीं करता है। प्रावधान नीचे निकाला गया है:

ई.

162. दस्तावेज का उत्पादन।- पेश करने के लिए बुलाए गए एक गवाह

कोई दस्तावेज, यदि वह उसके कब्जे या शक्ति में है, तो उसे न्यायालय में लाएगा, भले ही उसे पेश करने या उसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति हो। ऐसी किसी भी आपत्ति की वैधता पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

च

न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है, जब तक कि वह राज्य के मामलों को संदर्भित नहीं करता है, या इसकी स्वीकार्यता पर निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए अन्य सबूत नहीं ले सकता है।

111. जनहित उन्मुक्ति का दावा राज्य को इस आधार पर कार्यवाही से सामग्री को हटाने की अनुमति देता है कि इसके प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचेगा। कार्यवाही के सभी तीन पक्ष, यानी आवेदक, राज्य और अदालत कार्यवाही के दौरान ठोस सुनवाई के लिए दस्तावेजों का उल्लेख या उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं यदि अदालत खोज चरण में जनहित प्रतिरक्षा दावे की अनुमति देती है।

जी.

एच.

675

मध्यम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

वास्तव में, जनहित प्रतिरक्षा दावा कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज को अस्तित्वहीन बनाता है। जनहित प्रतिरक्षा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के उद्देश्य को काफी हद तक महसूस करती है।

112. ऊपर पहचाने गए सभी तीन विकल्प उद्देश्य को वास्तविक और मूल तरीके से प्राप्त करते हैं जितना कि यह गैर-प्रकटीकरण को आगे बढ़ाता है। हालाँकि, प्रत्येक वैकल्पिक साधन का मौलिक अधिकारों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे अलग-अलग खंडों में काम करते हैं। जनहित प्रतिरक्षा दावे में, मूल सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों और अदालत द्वारा सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाता है। अदालत कार्यवाही से सामग्री को हटा देती है, और जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही एक बंद सेटिंग में आयोजित की जाती है। एक टोटल दावे में, प्रवेश स्तर पर अदालत स्वयं घोषणा करती है कि यदि राज्य के रहस्यों पर सामग्री का खुलासा करना पड़ सकता है तो यह मुद्दा गैर-न्यायसंगत है। अदालत यह तय करने के लिए कोई संतुलन अभ्यास नहीं करती है कि क्या जानकारी के प्रकटीकरण के कारण होने वाली चोट गैर-प्रकटीकरण के कारण होने वाली चोट से अधिक भारी है। बल्कि, यदि सामग्री, राज्य के अनुसार, राज्य गुप्त से संबंधित है तो आवेदक न्यायिक समीक्षा के उपाय से वंचित है। बंद सामग्री प्रक्रिया के तहत, गैर-प्रकटीकरण योग्य सामग्री पर राज्य द्वारा भरोसा किया जाता है और मूल सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा संदर्भित

किया जाता है।विशेष अधिवक्ता प्रभावित पक्ष के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।हालांकि, विशेष अधिवक्ता को प्रभावित पक्ष के साथ साक्ष्य पर चर्चा करने से रोका जाएगा।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष अधिवक्ता बंद सुनवाई में प्रभावित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनहित प्रतिरक्षा दावों में भी शामिल हैं ताकि यह तय किया जा सके कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं।इस प्रकार, विशेष अधिवक्ता प्रणाली प्रभावित पक्ष की प्रक्रियात्मक गारंटी पर सीमा के प्रभाव को संतुलित करने का एक साधन है।

ग

डी.

ई.

च

113. जब पहचाने गए इन तीन साधनों को निरंतरता पर रखा जाता है, तो जनहित प्रतिरक्षा दावों को एक छोर पर रखा जाएगा क्योंकि उनका अधिकारों पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, जबकि दूसरे छोर पर टोटेन दावे को रखा जाता है।बंद सामग्री प्रक्रिया को बीच में रखा जाएगा क्योंकि विशेष अधिवक्ताओं का उपयोग प्रक्रियात्मक अधिकारों के उल्लंघन को संतुलित करने के प्रयास में किया जाता है।प्रभाव में अंतर को पहले विचार के चरण के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावा और बंद सामग्री प्रक्रिया दावा खोज चरण में उठाए जाते हैं।इस प्रक्रिया के विपरीत, टोटेन दावे के तहत, दावे को गैर-न्यायसंगत माना जाता है।

जी.

एच.

676

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अभिवचन स्तर पर यदि राज्य यह तर्क देता है कि कार्यवाही राज्य के रहस्यों पर आधारित है।दूसरा, टोटेन दावा न्यायिक समीक्षा के मौलिक अधिकार को सीमित करता है क्योंकि राज्य के रहस्यों पर आधारित दावों को गैर-न्यायोचित माना जाता है। हालांकि, एक जनहित प्रतिरक्षा दावे में, जिस भी तरह से दावा तय किया जाता है, पक्षों के पास हथियारों की समानता होगी क्योंकि कार्यवाही के दौरान उन्हीं सबूतों पर भरोसा करना होगा।यह तर्क दिया जा सकता है कि कार्यवाही से दस्तावेजों को हटाने से, वास्तव में, दावा गैर-न्यायोचित हो जाएगा यदि जिन दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, वे कार्रवाई के कारण के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।हमने इस निर्णय की धारा जे में इस तर्क को विस्तार से संबोधित किया है।सीलबंद आवरण प्रक्रिया के समान, बंद सामग्री कार्यवाही में, गैर-प्रकटीकरण योग्य साक्ष्य जो मामले की ठोस सुनवाई में उपयोग किया जाता है, दावेदार के लिए बाहर रखा जाता है।हालांकि, यूनाइटेड किंगडम में बंद सामग्री प्रक्रिया विशेष अधिवक्ताओं से स्वतंत्र नहीं है जिनका उद्देश्य पर्याप्त प्रतिसंतुलन प्रदान करना है।बंद सामग्री कार्यवाही सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा की तुलना में दावेदार की प्रक्रियात्मक गारंटी के लिए अधिक हानिकारक है क्योंकि गैर-प्रकट सामग्री का उपयोग राज्य द्वारा अपने कार्यों का बचाव करने के लिए किया जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत पर भरोसा किया जाता है।इसकी तुलना में, जनहित प्रतिरक्षा में, गैर-प्रकटीकरण योग्य साक्ष्य को खोज चरण में पूरी तरह से हटा दिया जाता है।यद्यपि विशेष अधिवक्ताओं का उद्देश्य पर्याप्त प्रतिसंतुलन प्रदान करना है, फिर भी यह प्रक्रिया दावेदार के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनती है क्योंकि सुरक्षा से मुक्त अधिवक्ताओं को साक्ष्य के बारे में दावेदार के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है।विशेष अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रतिसंतुलन की पर्याप्तता काफी हद तक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है, विशेष रूप से उस सामग्री पर जिसका खुलासा और खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।आरोपों, खुली सामग्री और बंद सामग्री के बीच अंतर्संबंध को ईसीएचआर द्वारा ए (सुप्रा) में उचित रूप से संबोधित किया गया था।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

ग

डी.

ई.

च

“220. अदालत ने आगे माना कि विशेष अधिवक्ता बंद सुनवाई के दौरान साक्ष्य का परीक्षण करके और बंदी की ओर से तर्क देकर पूर्ण प्रकटीकरण की कमी और पूर्ण, खुली, प्रतिकूल सुनवाई की कमी को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, विशेष अधिवक्ता इस कार्य को किसी भी उपयोगी तरीके से तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि बंदी को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई थी ताकि वह विशेष अधिवक्ता को प्रभावी निर्देश दे सके। जबकि इस प्रश्न का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए, न्यायालय आम तौर पर यह मानता है कि, जहां साक्ष्य ए था

जी.

एच.

677

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

काफी हद तक खुलासा किया गया और खुली सामग्री ने निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाई, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक को राज्य सचिव के विश्वास और उसके बारे में संदेह की तर्कसंगतता को चुनौती देने के लिए प्रभावी रूप से एक अवसर से वंचित कर दिया गया था। अन्य मामलों में, यहां तक कि जहां सभी या अधिकांश अंतर्निहित साक्ष्य अप्रकाशित रहे, यदि खुली सामग्री में निहित आरोप पर्याप्त रूप से विशिष्ट थे, तो आवेदक के लिए अपने प्रतिनिधियों और विशेष अधिवक्ता को ऐसी जानकारी प्रदान करना संभव होना चाहिए था जिससे उनका खंडन किया जा सके, यदि ऐसी जानकारी मौजूद थी, बिना उन सबूतों के विवरण या स्रोतों को जाने जो आरोपों का आधार बने। अ.

उदाहरण के लिए कई आवेदकों के खिलाफ लगाया गया आरोप होगा कि उन्होंने निर्दिष्ट तिथियों के बीच एक निर्दिष्ट स्थान पर एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था; आरोप की सटीक प्रकृति को देखते हुए, आवेदक के लिए विशेष अधिवक्ता को दोषमुक्त करने वाले साक्ष्य प्रदान करना संभव होता, उदाहरण के लिए एक बहाना या वहां अपनी उपस्थिति के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण, जो अधिवक्ता को आरोप को प्रभावी ढंग से चुनौती देने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होता।

ग

डी.

हालाँकि, जहाँ खुली सामग्री में विशुद्ध रूप से सामान्य दावे शामिल थे और प्रमाणन को बनाए रखने और निरोध को बनाए रखने का एस. आई. ए. सी. का निर्णय पूरी तरह से या निर्णायक स्तर तक बंद सामग्री पर आधारित था, अनुच्छेद 5 § 4 की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा।”

ई.

(जोर दिया गया)

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा शायद ऊपर सूचीबद्ध वैकल्पिक तरीकों का एक कम प्रतिबंधात्मक साधन है।

च

114. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि ऐसे वैकल्पिक साधन हैं जो राज्य के निपटान में गैर-प्रकटीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, अब हम मौलिक अधिकारों पर पहचाने गए वैकल्पिक साधनों (सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा) और उपयोग किए गए साधनों (सीलबंद आवरण) के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। धारा एफ में, हम पहले ही प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मौलिक उपदेशों पर एक सीलबंद लिफाफे में केवल अदालतों को सामग्री के प्रकटीकरण के प्रभाव पर चर्चा कर चुके हैं और कैसे अदालतें आवेदक के प्रक्रियात्मक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं करती हैं। अगले खंड में, हम जनहित प्रतिरक्षा पर न्यायशास्त्र पर चर्चा करेंगे। अदालतों ने जनहित प्रतिरक्षा दावों से कैसे निपटा है, इसका एक संदर्भ हमें यह विश्लेषण करने की अनुमति देगा कि क्या अदालतों के पास है।

जी.

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

आवेदक के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक गारंटी का उपयोग किया गया है या इसके विपरीत राज्य के दावों के लिए अव्यावहारिक रहे हैं। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक तुलनात्मक विश्लेषण है कि अदालतें सीलबंद आवरण और सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों से कैसे निपटेंगी जो हमें प्रक्रियात्मक अधिकारों पर उनके सापेक्ष प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देगी।

एच. जनहित प्रतिरक्षा पर न्यायशास्त्र का दावा एच. 1 इंडिया

115. इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 और 164 की व्याख्या की है। पंजाब राज्य बनाम सोधी सुखदेव सिंह 89 में, प्रतिवादी, एक जिला और सत्र न्यायाधीश, जिसे सेवा से हटा दिया गया था और बाद में फिर से नियुक्त किया गया था, ने लोक सेवा आयोग और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार का दावा करते हुए एक हलफनामा दायर किया। विशेषाधिकार के दावे की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने संविधान पीठ की बहुमत राय लिखते हुए खुलासा न करने के दावे की समीक्षा की गुंजाइश निर्धारित की। धारा 164 और 123 का अर्थ सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच संघर्ष से निपटने के लिए किया गया था। यह देखा गया कि अदालत को यह आकलन करना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाला प्रकटीकरण निजी हित की चिंताओं से अधिक होगा जो वादी को सामग्री का प्रकटीकरण आगे बढ़ाता है: "13. जिस सिद्धांत पर यह प्रस्थान उचित हो सकता है और उचित है, वह जनहित के सर्वोपरि और सर्वोपरि चरित्र का सिद्धांत है। धारा 123 के तहत विशेषाधिकार के लिए एक वैध दावा इस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ता है कि विचाराधीन दस्तावेज के प्रस्तुत होने से सार्वजनिक हित को नुकसान होगा, और यह कि, जहां सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, तो बाद वाले को पहले वाले के सामने झुकना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वादी जिसका दावा प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप सफल नहीं हो सकता है, वह परिणाम से व्यथित महसूस कर सकता है, और न्यायालय, उक्त निर्णय तक पहुंचने में, असंतुष्ट महसूस कर सकता है; लेकिन यह मूल सिद्धांत की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा कि सार्वजनिक भलाई और हित को निजी अच्छे और निजी हित के विचारों पर हावी होना चाहिए।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

अदालत ने कहा कि जब प्रकटीकरण के खिलाफ जनहित प्रतिरक्षा का दावा किया जाता है, तो अदालत को प्रारंभिक जांच पर होना चाहिए

89 (1961) 2 एससीआर 371 ए

एच.

679

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

शपथ पत्र यह निर्धारित करता है कि दस्तावेज राज्य के मामलों से संबंधित है या नहीं। यदि दस्तावेज राज्य के मामलों से संबंधित है, तो इस बारे में विभाग के प्रमुख का निर्णय कि क्या खुलासा सार्वजनिक हित का उल्लंघन करेगा, अंतिम होगा। दस्तावेज का खुलासा किया जाना चाहिए यदि प्रारंभिक जांच पर अदालत की राय है कि दस्तावेज 'राज्य के मामलों' से संबंधित नहीं है। अदालत के पास केवल हलफनामे की जांच करने की शक्ति होगी और उस दस्तावेज का निरीक्षण नहीं करेगा जिस पर यह निर्धारित करने के लिए प्रतिरक्षा का दावा किया जाता है कि क्या दस्तावेज 'राज्य के मामलों से संबंधित है'।

116. न्यायमूर्ति सुब्बा राव अपनी राय में कानून के इस बिंदु पर बहुमत की राय से अलग थे। विचलन एक सिद्धांत था। जबकि बहुमत ने मुद्दों को सार्वजनिक हित और निजी हित की तर्ज पर खड़ा किया, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण दोनों ही सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सूचना का प्रकटीकरण कार्यवाही में पक्षकार की सहायता करता है लेकिन इसके अलावा प्रकटीकरण न्याय के प्रशासन के उद्देश्य को भी पूरा करता है। न्यायालय द्वारा जांच की सीमा पर, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि न्यायालय के पास विशेषाधिकार के दावे को अस्वीकार करने की शक्ति है। इस उद्देश्य के लिए, अदालत को यह निर्धारित करना होता है कि क्या प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित गैर-प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित से अधिक है। यह देखा गया कि अदालतों को आमतौर पर विशेषाधिकार का दावा करने वाले मंत्री के हलफनामे को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जब अदालत के पास दावे पर अविश्वास करने का कारण हो, तो वह मंत्री की जांच कर सकती है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव न्यायमूर्ति गर्जेन्द्रगढ़कर की इस राय से सहमत थे कि न्यायालय उस दस्तावेज का निरीक्षण नहीं करेगा जिसे प्रकटीकरण से संरक्षित करने की मांग की गई है।

ग

डी.

ई.

117. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण 90 में, प्रत्यर्थी

एक चुनाव याचिका में दस्तावेजों को बुलाने की मांग की गई। राज्य ने प्रतिरक्षा का दावा किया। न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने संविधान पीठ के लिए अपनी सहमति वाली राय में सोधी सुखदेव सिंह (उपरोक्त) की टिप्पणी पर संदेह व्यक्त किया कि न्यायालय के पास उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति नहीं है जिनके लिए विशेषाधिकार का दावा किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दस्तावेज का निरीक्षण किए बिना सार्वजनिक हित पर प्रकटीकरण के प्रभाव को निर्धारित करना मुश्किल होगा। विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे दस्तावेजों को हानिकारक वर्गों और अन्य से संबंधित दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि दस्तावेज हानिकारक वर्गों (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा) से संबंधित हैं, तो यह स्वयं लोक हित का उल्लंघन करेगा। अन्य दस्तावेजों के लिए जो हानिकारक वर्गों से संबंधित नहीं हैं, अदालतों को प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण दोनों में शामिल सार्वजनिक हित के पहलुओं का सर्वेक्षण करना चाहिए।

च

जी.

90 (1975) 4 एस. सी. 428

एच.

680

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

जनहित के विभिन्न पहलुओं के सापेक्ष दावों का आकलन करने के लिए प्रकटीकरण:

“71. बहुत कम लोग इस नियम की आवश्यकता पर सवाल उठाएंगे कि राज्य के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने वाली चीजों को बाहर रखा जाए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल शामिल होता है, तो हो सकता है कि न्यायालय मामले पर विचार करने के लिए उचित मंच न हो और यही कारण है कि एक मंत्री के प्रमाण पत्र को निर्णायक माना जाता है। “जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एकमात्र न्यायाधीश होना चाहिए।” [द जमोरा में वेडिंगटन के लॉर्ड पार्कर, (1916) 2 एसी 77,107] चूंकि कार्यकारी विदेशी संबंधों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इसलिए कोई अन्य अंग ऐसा नहीं कर सकता है।

ग

इस तरह के मामलों का अच्छी तरह से न्याय करें। इसलिए, इन मामलों के संबंध में दस्तावेज एक ऐसे वर्ग में आ सकते हैं जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। [...]

72. न्यायालय के लिए आरक्षित शक्ति उत्पादन का आदेश देने की शक्ति है, भले ही जनहित कुछ हद तक पूर्वाग्रहपूर्ण हो।

डी.

प्रभावित हुए। यह एक मान्यता है कि जनहित के एक से अधिक पहलुओं का सर्वेक्षण करना होगा। जिस सरकार के हित के लिए मंत्री बोलता है, वह पूरे लोक हित को समाप्त नहीं करता है। उस हित का एक अन्य पहलू न्याय के निष्पक्ष प्रशासन की आवश्यकता में देखा जाता है। यह मान लेना उचित प्रतीत होता है कि एक अदालत अपने समक्ष मामले में जनहित के महत्व को मापने के लिए मंत्री की तुलना में बेहतर योग्य है। अदालत को करना होगा

ई.

जनहित के इन विभिन्न पहलुओं के सापेक्ष दावों का मूल्यांकन करें। जबकि कार्यपालिका को यह निर्धारित करने की शक्ति देने के लिए भारी तर्क है कि कौन से मामले सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, वे तर्क कार्यपालिका को यह निर्धारित करने के लिए एक विशेष शक्ति देने के लिए कोई मंजूरी नहीं देते हैं कि कौन से मामले सार्वजनिक हित को प्रभावित कर सकते हैं। एक बार जब राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारों को छोड़ दिया जाता है, तो जनहित के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रशासन स्वयं सुरक्षा दस्तावेजों के कई वर्गों के बारे में जानता है जो केवल आधिकारिक उपयोग के लिए आरक्षित हैं और जिन्हें केवल मुट्ठी भर मंत्रियों या गोपनीयता की शपथ से बंधे अधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है।”

च

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

681

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

118. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 91 में, इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित के आधार पर खुलासा न करने के दावों पर कानून की स्थिति का निपटारा किया। इस मामले में, भारत संघ ने कानून मंत्री, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच पत्राचार के प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा किया। यह तर्क दिया गया था कि जिन दस्तावेजों का खुलासा करने की मांग की गई है, वे एक ऐसे वर्ग के हैं जो प्रकटीकरण से मुक्त हैं, और इस प्रकार अदालतों को अपनी सामग्री की परवाह किए बिना गैर-प्रकटीकरण के दावे की अनुमति देनी चाहिए। न्यायमूर्ति भगवती, जिनके विचार से पाँच अन्य न्यायाधीश सहमत थे, 92 ने खुलासा न करने के दावे को खारिज कर दिया। 93 न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि वर्ग प्रतिरक्षा का दावा पूर्ण नहीं है:

ग

“कार्यपालिका केवल वर्ग प्रतिरक्षा के धर्मशास्त्रीय सूत्र का उपयोग करके एक दस्तावेज को रोककर न्याय के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती है जो पक्षों के बीच न्याय करने के लिए आवश्यक है, अन्यथा वर्ग प्रतिरक्षा का सिद्धांत कार्यपालिका के हाथों में अपनी गलतियों को दफनाने, अपनी अक्षमताओं को छिपाने और कभी-कभी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक भयानक हथियार बन जाएगा। किसी दस्तावेज के संबंध में प्रतिरक्षा के लिए प्रत्येक दावा, जो भी आधार हो जिस पर प्रतिरक्षा का दावा किया जाता है और दस्तावेज की प्रकृति जो भी हो, केवल एक परीक्षण के संदर्भ में अदालत की जांच में खड़ा होना चाहिए, अर्थात्, सार्वजनिक हित की क्या आवश्यकता है-प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण। इसलिए वर्ग प्रतिरक्षा का सिद्धांत अब अभेद्य नहीं है; यह अब न्यायिक जांच से इनकार नहीं करता है; यह अब एक मंत्र नहीं है जिसे अदालत नमन करती है। जब भी किसी दस्तावेज के संबंध में वर्ग प्रतिरक्षा का दावा किया जाता है, तो अदालत को जन हित के एक पहलू को मापना पड़ता है, जिसके लिए आवश्यक है कि दस्तावेज को दूसरे के खिलाफ प्रकट नहीं किया जाना चाहिए कि अदालत को अपने कार्यों को करने में प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि शेष राशि किस तरह से निहित है। और यह अभ्यास एक खुली सरकार के लोकतांत्रिक आदर्श के संदर्भ में किया जाना चाहिए।”

डी.

ई.

च

जी.

91 1981 पूरक एस. सी. सी. 87

92 न्यायमूर्ति गुप्ता (पैराग्राफ 142); न्यायमूर्ति तुलजापुरका (पैराग्राफ 662); न्यायमूर्ति देसाई (पैराग्राफ 855); न्यायमूर्ति पाठक (पैराग्राफ 941 और 942)। न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने एक सहमति वाली राय लिखी।

93 न्यायमूर्ति फजल अली ने खुलासा न करने के दावे को स्वीकार करने से असहमति जताई।

एच.

682

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

119. न्यायमूर्ति भगवती ने आगे कहा कि एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए एक न्यायाधीश की गैर-नियुक्ति, जिसे इस मामले में चुनौती दी गई थी, को केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तीन संवैधानिक अधिकारियों के बीच कोई पूर्ण और प्रभावी परामर्श नहीं था, या यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण था। इसलिए, जो पत्राचार मांगा जाता है, वह एकमात्र दस्तावेजों की साक्ष्य है जो दावे को स्थापित करने में सहायता करेगा। दूसरी ओर, गैर-प्रकटीकरण का प्रभाव रिट याचिका को खारिज करना सुनिश्चित करने

पर होगा। इसके अलावा, यह माना गया कि आवेदक के मामले पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव के अलावा, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों को भी प्रभावित करेगा यदि नियुक्ति प्रक्रिया को जनता के दृष्टिकोण से अलग किया जाता है। इसके अलावा, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण को चुनौती दी जाती है, तो यह साबित करने का भार भारत संघ पर होता है कि स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण नहीं था। यह देखा गया कि भारत संघ केवल गैर-प्रकटीकरण के लिए एक हलफनामा दायर करके इतने भारी बोझ का निर्वहन नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति भगवती ने यह कहते हुए खुलासा न करने के दावे को खारिज कर दिया कि भारत संघ अपने इस दावे को साबित करने में असमर्थ रहा है कि पत्राचार का खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होना चाहिए।

ग

डी.

120. राज नारायण (ऊपर) में न्यायमूर्ति मैथ्यू और सोधी सुखदेव सिंह (ऊपर) में न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा लिए गए विचार को न्यायमूर्ति भगवती ने एस. पी. गुप्ता (ऊपर) में बहुमत के लिए लिखते हुए आंशिक रूप से अपनाया और आगे विकसित किया गया। निर्णय में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का सारांश नीचे दिया गया है:

ई.

(i) खुली सरकार लोकतांत्रिक सरकार के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सूचना का प्रकटीकरण कार्यवाही में प्रभावित पक्ष के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, यह सूचना तक पहुंच और खुली सरकार में सार्वजनिक हित को भी आगे बढ़ाता है। धारा 123 और 162 जिस संघर्ष का निवारण करना चाहते हैं, वह जनहित और निजी हित के बीच नहीं है, बल्कि जनहित की दो परस्पर विरोधी अवधारणाओं के बीच है।

च

((ii) सोधी सुखदेव सिंह (ऊपर) में बहुमत की राय दो विसंगतियों को कायम रखती है। सबसे पहले, यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि कोई दस्तावेज राज्य के मामलों से संबंधित है या नहीं। न्यायालय निरीक्षण के बाद ही सार्वजनिक हित पर अपने प्रकटीकरण के प्रभाव का निर्धारण करता है। यह निष्कर्ष स्पष्ट है क्योंकि सोधी सुखदेव सिंह (उपरोक्त) पहले ही यह मान चुके हैं कि केवल ऐसे दस्तावेज जो जनता को प्रभावित करते हैं।

जी.

एच.

683

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ब्याज को राज्य के मामलों से संबंधित दस्तावेजों के रूप में माना जा सकता है और दूसरा, विभाग के प्रमुख के बजाय अदालत यह निर्धारित करती है कि सूचना के प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित प्रभावित होगा या नहीं। विभाग के प्रमुख द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, अदालत जनहित पर प्रकटीकरण के प्रभाव का आकलन करके यह निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास आयोजित करती है कि क्या दस्तावेज राज्य के मामलों से संबंधित है। अदालत द्वारा इस कवायद को शुरू करने के बाद, विभाग के प्रमुख के लिए यह फिर से तय करना व्यर्थ होगा कि क्या खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।

((ग) प्रतिरक्षा के लिए दावा करने का भार दावा करने वाले व्यक्ति पर है।

ग

(iv) जब जनहित उन्मुक्ति का दावा किया जाता है, तो अदालत को मंत्री या विभाग के प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन पर यह तय करना चाहिए कि क्या खुलासा जनहित के लिए हानिकारक होगा। न्यायालय दस्तावेज का निरीक्षण कर

सकता है यदि वह राज्य के दावे पर संदेह करता है और हलफनामे के अवलोकन पर खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है। न्यायालय के निरीक्षण की इस शक्ति को साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 के संचालन से बाहर नहीं किया गया है;

डी.

(v) दस्तावेजों को प्रकटीकरण से संरक्षण केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रकटीकरण से राजनीतिक आलोचना होगी। खुली सरकार पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज में सरकार के कार्यों की आलोचना के डर के कारण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सीमित नहीं हो सकता है।

ई.

(vi) प्रकटीकरण को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दस्तावेज एक हानिकारक 'वर्ग' से संबंधित हैं। न्यायालय को अभी भी एक संतुलन अभ्यास का संचालन करना चाहिए। वर्ग प्रतिरक्षा 'पूर्ण या अलंघनीय नहीं है'। सभी मामलों में यांत्रिक रूप से लागू किया जाना कानून का नियम नहीं है।

च

(vii) न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या: (क) दस्तावेज का प्रकटीकरण प्रभावी रूप से लोक हित (प्रभाव परीक्षण) के खिलाफ होगा, और (ख) यदि ऐसा है, तो क्या प्रकटीकरण में लोक हित 'इतना मजबूत' है कि इसे न्याय के प्रशासन (संतुलन परीक्षण) में लोक हित पर हावी होना चाहिए; और

जी.

एच.

684

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(viii) संतुलन परीक्षण करते समय, न्यायालय को निम्नलिखित जांचों पर विचार करना चाहिए:

(क) तथ्यों के बारे में: क्या खुलासा न करने से मामले के पक्षकार के हित को नुकसान पहुंचेगा। गैर-प्रकटीकरण के कारण चोट का निर्धारण उस कार्यवाही की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें प्रकटीकरण की मांग की जाती है, दस्तावेज की प्रासंगिकता, इस संभावना की डिग्री कि दस्तावेज मुकदमेबाजी के लिए महत्वपूर्ण होगा, और क्या गैर-प्रकटीकरण के दावे की अनुमति देने से मुद्दा गैर-न्यायसंगत हो जाएगा; और

ग

(ख) सिद्धांततः क्या गैर-प्रकटीकरण न्याय के प्रशासन के अलावा किसी अन्य संवैधानिक सिद्धांत को प्रभावित करेगा।

121. हम सोचते हैं कि जनहित प्रतिरक्षा दावों के संदर्भ में जनहित की विभिन्न अवधारणाओं को संतुलित करने की दिशा में विभिन्न न्यायालयों के दृष्टिकोण का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है क्योंकि एस. पी. गुप्ता (ऊपर) में भारत में विकसित जनहित प्रतिरक्षा पर कानून अन्य सामान्य कानून देशों से निकलने वाले न्यायशास्त्र पर बहुत अधिक निर्भर था। वास्तव में, मुख्य न्यायाधीश रे ने राज नारायण (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 41 में दर्ज किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और धारा 162 के पीछे कानून की नींव अंग्रेजी कानून के समान है।

डी.

ई.

एच. 2 यूनाइटेड किंगडम

122. यूनाइटेड किंगडम में इस विषय का विवरण डंकन बनाम कैमेल लेयरड 94 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय के साथ शुरू हुआ। इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने गैर-प्रकटीकरण के लिए सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे का आकलन करते समय सार से अधिक गठन को प्राथमिकता दी। लॉर्ड साइमन ने दो मुद्दे तैयार किए: (i) वह प्रपत्र जिसमें प्रकटीकरण पर आपत्ति की जानी है; और (ii) यदि आपत्ति उचित रूप में की जाती है, तो क्या न्यायालय को बिना जांच के आपत्ति को निर्णायक मानना चाहिए। लॉर्ड ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-प्रकटीकरण के दावे की अनुमति दी जानी चाहिए यदि आपत्ति का रूप वैध है, और एक निजी नागरिक के हितों को सार्वजनिक हित द्वारा शामिल किया जा सकता है। नतीजतन, अदालतें दावे की वैधता का निर्धारण करते समय दस्तावेजों की जांच नहीं कर सकती हैं क्योंकि यह न्याय के पहले सिद्धांत का उल्लंघन करेगा जो न्यायाधीश को करना चाहिए।

च

जी.

94 [1942] एसी 624 ए

एच.

685

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

वादियों में से एक के साथ हाथ में मामले पर कोई लेन-देन नहीं है सिवाय दूसरे की उपस्थिति में और उसके समान ज्ञान के।' इस प्रकार, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मुद्दे को सार्वजनिक हित की अवधारणाओं के बीच संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि निजी हित और सार्वजनिक हित की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनहित प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग के लिए दो सिद्धांत स्थापित किए: कि एक वादी के हित को सरकार की गोपनीयता को रास्ता देना चाहिए, और मंत्री के पास यह तय करने की एकमात्र शक्ति है कि दस्तावेज को रोक दिया जाना चाहिए या नहीं।

123. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कॉनवे बनाम रिम्मर 95 में अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। लॉर्ड रीड ने कहा कि गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव को निजी हित के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और यह न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित है जो दस्तावेजों के गैर-प्रकटीकरण के कारण घायल होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मौलिक महत्व के तीन सिद्धांतों की स्थापना की। सबसे पहले, यह तय करने की शक्ति कि क्या साक्ष्य को अदालत से रोका जाना है, अदालत के पास रहती है न कि कार्यपालिका के पास। दूसरा, अदालत को इस शक्ति का प्रयोग करते समय न्याय देने में अदालत की असमर्थता के साथ प्रकटीकरण के कारण सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित नुकसान को संतुलित करना चाहिए। न्यायालय को बाद में नुकसान का निर्धारण करते समय 'सही तथ्यों' का पता लगाने और न्यायालय प्रणाली में जनता के विश्वास के व्यापक सिद्धांत पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव का आकलन करना चाहिए। तीसरा, अदालत को निजी तौर पर उस सामग्री का निरीक्षण करने का अधिकार है, जिस पर प्रतिरक्षा का दावा किया जाता है। सामग्री की जांच करने पर, अदालत को यह निर्धारित करना होता है कि क्या सार्वजनिक हित के कारण गैर-प्रकटीकरण आवश्यक है, न कि केवल सार्वजनिक सेवा के कामकाज के लिए फायदेमंद है। लॉर्ड हडसन ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को अपनी जांच में वर्गों की सामान्यताओं को त्याग देना चाहिए और एक तरफ न्याय से इनकार करने की जनता को हुई चोटों और दूसरी तरफ सरकारी दस्तावेजों के रहस्योद्घाटन पर विचार करना चाहिए, जिनका कभी भी सार्वजनिक करने का इरादा नहीं था और जो प्रकटीकरण की अप्रत्याशित संभावना से बाधित हो सकते हैं।' जनहित के दावों के टकराव का निर्धारण अदालत के समक्ष मामले में रोके जाने वाले दस्तावेजों के महत्व (परिणाम का प्रश्न) के आधार पर किया जाना चाहिए, और क्या गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप न्याय का 'पूर्ण' या 'आंशिक' इनकार (प्रक्रिया और परिणाम का प्रश्न) होगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

124. रेग बनाम चीफ कॉन्सटेबल, W.Midlands, एक्स पी।विली 96,

हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से बोलते हुए लॉर्ड वूल्फ ने कहा कि पैमाने पर संतुलन निर्धारित करते समय, न्यायालय को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या प्रकटीकरण में रुचि को 'अन्य वैकल्पिक साधनों' के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है:

95 [1968] एसी 910 96 [1994] डब्ल्यूएलआर 433

एच.

686

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“[...] वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना कोई भी आवश्यक जानकारी प्रदान करना संभव हो सकता है। किसी प्रतिबंधित दस्तावेज पर दस्तावेज के किसी हिस्से का खुलासा करना संभव हो सकता है।

आधार।[...] आमतौर पर कार्रवाई का एक स्पेक्ट्रम होता है जो तब किया जा सकता है जब पक्ष समझदार होते हैं जिसका अर्थ होगा कि गैर-प्रकटीकरण के कारण कोई भी पूर्वाग्रह न्यूनतम तक कम हो जाता है।”

(जोर दिया गया)

125. आर (मोहम्मद) बनाम सचिव में रानी की बेंच डिवीजन

विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के लिए राज्य 97 ने चार लागू किए -

जनहित दावे की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परीक्षण। इस मामले में, एक इथियोपियाई नागरिक जो यूनाइटेड किंगडम का पूर्व निवासी था, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने क्यूबा में एक हिरासत सुविधा में रखा था, जहाँ उस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम सरकार के पास मौजूद जानकारी का खुलासा करने की मांग की, जिसने उनके बचाव का समर्थन किया होगा कि हिरासत में रहते हुए उन्होंने जो स्वीकारोक्ति दी थी, वह अस्वीकार्य थी। अदालत ने माना कि यूनाइटेड किंगडम की सुरक्षा सेवा ने गलत काम करने में मदद की थी। फैसले के दौरान, यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम सुरक्षा और खुफिया सेवाओं को दी गई रिपोर्ट को सात पैराग्राफ में संक्षेपित किया गया था। इन सात पैराग्राफ को न्यायालय द्वारा जनहित प्रतिरक्षा का दावा करके संशोधित करने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि यदि पैराग्राफ प्रकाशित किए जाते हैं तो संयुक्त राज्य सरकार यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने खुफिया साझाकरण संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करेगी, जो बदले में यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा। न्यायालय ने इस दावे को तय करने के लिए एक चार-आयामी परीक्षण लागू किया कि क्या पैराग्राफ को संशोधित किया जाना था: (i) क्या संशोधित अनुच्छेदों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने में कोई सार्वजनिक हित है?

ग

डी.

ई.

च

((ii) क्या इस प्रकटीकरण से किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित को गंभीर नुकसान होगा और यदि ऐसा है तो किस ब्याज को?

जी.

((ग) क्या सीमित प्रकटीकरण के अन्य तरीकों से प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाने से रोका जा सकता है?

((iv) यदि विकल्प अपर्याप्त हैं, तो जनहित का संतुलन कहाँ है?

97 [2009] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 152 (प्रशासक)

एच.

687

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

126. पहले परीक्षण का जवाब देते हुए, न्यायालय ने सार्वजनिक सुनवाई और तर्कपूर्ण निर्णय के सिद्धांतों के प्रति न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर प्रकटीकरण के प्रभाव की पहचान की; और सार्वजनिक बहस को आगे बढ़ाने में जानकारी की भूमिका जो एक स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। मामले के विशिष्ट संदर्भ में, यह देखा गया कि यह खुलासा यातना और अमानवीय व्यवहार पर सार्वजनिक चर्चा को आगे बढ़ाएगा। दाखिल किए गए हलफनामे को उचित महत्व दिया गया था। अदालत ने हलफनामे में कारणों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक चोट का आकलन सद्भावना से किया गया था। यह निष्कर्ष संयुक्त राज्य सरकार के उच्चतम स्तर के सदस्यों द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों के आधार पर निकाला गया था। 'वैकल्पिक साधन परीक्षण' के लिए तथ्यों को लागू करते हुए, अदालत ने कहा कि जिन अनुच्छेदों को संशोधित करने की मांग की गई थी, वे सभी जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं, बल्कि जानकारी के संशोधित भागों का खुलासा करते हैं; और यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिए बिना और खुले न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना जानकारी को और संशोधित करना संभव नहीं होगा। इस परीक्षण का उत्तर देते समय, न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या वादी और राज्य दोनों के हित सूचना के पूर्ण प्रकटीकरण के अलावा अन्य माध्यमों से सुरक्षित किए जा सकते हैं। संतुलन परीक्षण को लागू करते समय, अदालत ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांत जो जानकारी का खुलासा करते हैं, उन सूचनाओं द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं जिन्हें पहले ही सार्वजनिक मंच पर रखा जा चुका है।

ग

डी.

एच. 3 संयुक्त राज्य अमेरिका

ई.

127. संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक निर्णयों ने माना है कि असाधारण परिस्थितियों में, अदालत को राज्य के रहस्यों के प्रकटीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कार्य करना चाहिए। इसका एक उदाहरण

इस सिद्धांत का अनुप्रयोग रेनॉल्ड्स विशेषाधिकार है। रेनॉल्ड्स विशेषाधिकार

एक साक्ष्य सिद्धांत है जहां विशेषाधिकार का सफल दावा मुकदमेबाजी से विशेषाधिकार प्राप्त साक्ष्य को हटा देगा। रेनॉल्ड्स में प्रस्तावित परीक्षण यह है कि "यदि कोई उचित खतरा है तो साक्ष्य की मजबूरी उजागर हो जाएगी। ऐसे मामले जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।" विशेषाधिकार प्राप्त साक्ष्य को मामले से बाहर रखा गया है जिसका परिणाम संयोग से दावों को खारिज करने में भी हो सकता है। 128. यूनाइटेड किंगडम में मानक के विपरीत, प्रकटीकरण में 'सबसे सम्मोहक आवश्यकता' भी विशेषाधिकार के दावे को दूर नहीं कर सकती है यदि अदालत संतुष्ट है कि राज्य के रहस्य दांव पर हैं। आम तौर पर, टोटन बार के विपरीत साक्ष्य को बाहर रखा जाता है जहां मुद्दा घोषित किया जाता है।

च

जी.

एच.

98 संयुक्त राज्य बनाम रेनॉल्ड्स, 345 यू. एस. 1 (1953)

688

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

गैर-न्यायसंगत, यदि जानकारी संरक्षित साक्ष्य के एक वर्ग से संबंधित है। हालांकि, कुछ मामलों में, 'विशेषाधिकार' के आवेदन के लिए कार्रवाई को खारिज करने की आवश्यकता हो सकती है और इस बिंदु पर, रेनॉल्ड्स विशेषाधिकार टॉटन बार के साथ मिल जाता है।

129. बिन्याम मोहम्मद बनाम जेप्पेसेन डेटाप्लान 99 में नौवें सर्किट के लिए यू. एस. कोर्ट ऑफ अपीलस ने कहा कि तीन परिस्थितियों में, रेनॉल्ड्स विशेषाधिकार के आवेदन पर मामले की समाप्ति उचित है: (i) यदि वादी अपना मामला प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर सकता है; (ii) यदि वादी प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित करता है, लेकिन यदि विशेषाधिकार प्रतिवादी को ऐसी जानकारी से वंचित करता है जो प्रतिवादी को एक वैध बचाव प्रदान करेगी, तो अदालत प्रतिवादी को एक संक्षिप्त निर्णय दे सकती है; और (iii) भले ही दावे विशेषाधिकार प्राप्त साक्ष्य पर भरोसा किए बिना सैद्धांतिक रूप से स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ना असंभव हो सकता है क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त साक्ष्य गैर-विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से अविभाज्य है। 130. संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों द्वारा पालन की जाने वाली जांच का मानक तीन बुनियादी सिद्धांतों पर यूनाइटेड किंगडम से अलग है: सबसे पहले, रेनॉल्ड्स विशेषाधिकार में स्थापित मानक यह पहचानना है कि क्या जानकारी 'संरक्षित वर्गों' से संबंधित है; दूसरा, अदालत प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण के दावों को संतुलित करने का अभ्यास नहीं करती है। यदि जानकारी संरक्षित वर्ग से संबंधित है, तो मामले और व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव की परवाह किए बिना दावे की अनुमति दी जाती है; और तीसरा, सबूत का बोझ प्रभावित पक्ष पर है कि वह अपने मामले को गैर-विशेषाधिकार प्राप्त साक्ष्य के साथ साबित करे, न कि गैर-प्रकटीकरण की आवश्यकता को साबित करने के लिए राज्य पर।

ग

डी.

ई.

एच. 4 कनाडा

131. यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों के समान, सूचना के गैर-प्रकटीकरण पर कनाडाई न्यायशास्त्र व्यक्तिगत दस्तावेजों की जांच की ओर 'वर्ग' जांच से दूर चला गया है। 100 कनाडाई न्यायालयों का सुसंगत दृष्टिकोण यह रहा है कि दस्तावेजों को केवल 'कार्यकारी शाखा के उचित कामकाज के लिए और इसके अनुचित आचरण को सुविधाजनक बनाने के लिए' रोका जा सकता है। 101

च

जी.

132. कनाडा साक्ष्य अधिनियम 1985 की धारा 38 उन सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए शर्तों को निर्धारित करती है जिन्हें संरक्षित करने की मांग की जाती है।

99 614 एफ 3 डी 1070 (9 वीं सी. आई. आर. 2010) (संयुक्त राज्य अमेरिका) 100 कैरी बनाम मैजेस्टी, (1986), 72 एन. आर. 81 (एस. सी. सी.) 101 आई. बी. आई. डी.

एच.

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

न्यायालय कनाडा के महान्यायवादी द्वारा दायर गैर-प्रकटीकरण के दावे की वैधता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विश्लेषण करता है: (i) प्रासंगिकता परीक्षण: जिस जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई है, क्या वह मामले के लिए प्रासंगिक है। जानकारी की प्रासंगिकता साबित करने के लिए सबूत का भार प्रकटीकरण का दावा करने वाले पक्ष पर है।

((ii) चोट परीक्षण: क्या यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राष्ट्रीय रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।¹⁰³ प्रकटीकरण के कारण क्षति साबित करने का भार प्रकटीकरण का विरोध करने वाले पक्ष पर है।¹⁰⁴ न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि कार्यपालिका के चोट के दावे का कोई तथ्यात्मक आधार है या नहीं। इस स्तर पर अदालत को जानकारी की प्रकृति और उस चोट की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जिसे संरक्षित करने की मांग की गई है।

ग

(क) न्यायालय को प्रकटीकरण का आदेश देना चाहिए यदि राज्य न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ है कि सूचना का प्रकटीकरण हानिकारक है; और

डी.

(ख) न्यायालय को एक संतुलन अभ्यास करना चाहिए यदि राज्य ने साबित कर दिया है कि खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा;

((iii) वैकल्पिक परीक्षण: क्या पूर्ण प्रकटीकरण के विकल्प हैं जो एक निष्पक्ष मुकदमे की रक्षा करेंगे।

ई.

((iv) संतुलन परीक्षण: न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित गैर-प्रकटीकरण ¹⁰⁵ में सार्वजनिक हित से अधिक है। यदि ऐसा होता है, तो जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। न्यायालय को संतुलन अभ्यास करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए:

च

(ए) दावे को साबित करने या बचाव करने में जानकारी का 'सापेक्ष महत्व'-यानी, क्या जानकारी मामले के लिए 'आवश्यक' और 'महत्वपूर्ण' है;

(ख) प्रकटीकरण के कारण होने वाली चोट की सीमा;

जी.

102 रिबिक बनाम कनाडा (महान्यायवादी), 2003 एफ. सी. ए. 246 103 कनाडा साक्ष्य अधिनियम 104 रिबिक (एन 102) की धारा 38.06 (1)

105 कनाडा साक्ष्य अधिनियम 106 आर बनाम अहमद, (2011) एससीसी 6 की धारा 38.06 (2)

एच.

690

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

- (ग) क्या मानवाधिकारों के मुद्दों, पूरा जवाब देने का अधिकार और दांव पर लगे आपराधिक संदर्भ में बचाव जैसे उच्च हित हैं;
- ((घ) खुले न्यायालय के सिद्धांत का महत्व; और
- (ङ) क्या संशोधित जानकारी पहले से ही जनता को ज्ञात है।

133. उपर्युक्त क्षेत्राधिकारों में गैर-प्रकटीकरण के लिए जनहित प्रतिरक्षा दावों पर चर्चा के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

(i) सभी क्षेत्राधिकारों में कानून की पहले की स्थिति यह थी कि अदालतों को सरकार के इस दावे का बचाव करना चाहिए कि दस्तावेजों का खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा। हालांकि, इस स्थिति में भारी बदलाव आया है। यह अब कानून की एक तय स्थिति है कि अदालतों के पास जनहित प्रतिरक्षा दावों की वैधता का आकलन करने की शक्ति है। इस तरह की शक्ति की सीमा विवाद की हड्डी है;

ग

डी.

((ii) अदालतों द्वारा जनहित प्रतिरक्षा दावों की जांच की सीमा चार प्राथमिक कारकों पर निर्भर करती है: (क) सूचना का खुलासा न करने के कारण हुई क्षति की पहचान; (ख) वर्ग के दावों की अनुमति की सीमा; (ग) सबूत का बोझ; और (घ) दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता;

ई.

(iii) गैर-प्रकटीकरण के कारण चोट की पहचान और गैर-प्रकटीकरण के लिए आधार का मूल्यांकन वर्ग के दावों की अनुमति, प्रमाण का बोझ और साक्ष्य की आवश्यकता के मूल्यांकन के न्यायालय के मानक को प्रभावित करता है। जांच का स्तर तब अधिक होता है जब सूचना के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव की पहचान अदालत के समक्ष तथ्यों के संकीर्ण संदर्भ के आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन और कानून के शासन पर इसके व्यापक प्रभावों के आधार पर की जाती है; (iv) भारत, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा की अदालतों ने माना है कि प्रासंगिक सामग्री का गैर-प्रकटीकरण सार्वजनिक हित और प्रकटीकरण की मांग करने वाले पक्ष के हितों को प्रभावित करता है। सूचना का खुलासा न करने से खुली सरकार के सिद्धांत को नुकसान पहुंचता है जो बुनियादी ए में से एक है।

च

जी.

एच.

691

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

लोकतंत्र का आधार। यह नागरिकों को चर्चा शुरू करने या सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के अवसर से वंचित करता है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों ने गैर-प्रकटीकरण के दावे को स्थगित कर दिया है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इतना कि अदालत प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण के दावों के बीच संतुलन अभ्यास नहीं करती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतें इसके प्रभाव के विपरीत गैर-प्रकटीकरण के उद्देश्य को प्रमुखता देती हैं;

(v) पी. आई. आई. दावों के मूल्यांकन पर भारत (एस. पी. गुप्ता में), यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में निर्धारित मानक इस हद तक समान है कि संवैधानिक शासन के व्यापक सिद्धांतों पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव पर भी विचार किया जाता है।

(vi) कनाडा में, उत्पादन की मांग करने वाले पक्ष को राज्य द्वारा पी. आई. आई. दावा किए जाने के बाद मांगी गई सामग्री की प्रासंगिकता साबित करने की आवश्यकता होती है। प्रासंगिकता परीक्षण को परीक्षणों में से एक के रूप में शामिल करने से सबूत का बोझ बढ़ जाता है जो अन्यथा आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत उस स्तर पर इस बात से अवगत है कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर पेशी का विरोध कर रहा है। इस तरह के दावों को हमेशा अदालतों द्वारा एक अवज्ञापूर्ण स्वर के साथ पूरा किया जाता है। दूसरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खोज चरणों और आपत्ति चरणों के एकीकरण की ओर ले जाता है। यह एकीकरण समस्याग्रस्त है क्योंकि खोज स्तर और आपत्ति स्तर पर न्यायालय के विचार अलग-अलग हैं। दस्तावेजों की खोज करने वाले पक्ष को कार्यवाही के लिए दस्तावेज की प्रासंगिकता को प्रथम दृष्टया साबित करना चाहिए। एक बार जब पक्ष इस बोझ का निर्वहन कर देता है, और अदालत प्रकटीकरण का आदेश देती है, तो राज्य इस आधार पर प्रकटीकरण पर आपत्ति कर सकता है कि इससे सार्वजनिक हित को नुकसान होगा। इस स्तर पर जनहित को नुकसान पहुँचाने का भार पूरी तरह से राज्य पर है। आपत्ति उठाए जाने के बाद, प्रकटीकरण की प्रासंगिकता को केवल संतुलन स्तर पर तौला जाना चाहिए। जनहित साबित करने के बोझ को राज्य द्वारा निर्वहन करने की आवश्यकता से पहले ही दस्तावेज की प्रासंगिकता की पहचान करना जनता के अनुप्रयोग में एक मौलिक गलत धारणा पैदा करता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

692

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ब्याज प्रतिरक्षा जो दस्तावेजों के उत्पादन के लिए एक अपवाद है। इसके अलावा, प्राथमिक स्तर पर, पक्ष द्वारा देखे बिना कार्यवाही के लिए दस्तावेज की प्रासंगिकता को साबित करना असंभव होगा; और (vii) एक बार प्रकटीकरण के कारण चोट साबित हो जाने के बाद, यूके और कनाडा में अदालतें सार्वजनिक हित के परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करने के लिए संरचित आनुपातिकता परीक्षण का पालन करती हैं।

134. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार, कार्यवाही का एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास मौजूद जानकारी के ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए खोज के लिए आवेदन दायर कर सकता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के कब्जे या शक्ति में किसी भी मामले से संबंधित दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए निर्देश की मांग करते हुए कोई हलफनामा दायर किए बिना एक आवेदन, 107 दायर कर सकता है। न्यायालय या तो आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या स्थगित कर सकता है यदि वह आवेदन की सुनवाई पर संतुष्ट है कि वाद के चरण में ऐसी खोज आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय खोज को 'दस्तावेजों के कुछ वर्गों' तक सीमित करने का आदेश जारी करेगा। आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा यदि मुकदमे के उचित निपटान या लागत बचाने के लिए दस्तावेजों की खोज आवश्यक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रावधान 'मुकदमे का उचित निपटान' वाक्यांश का उपयोग करता है। उक्त अभिव्यक्ति के उपयोग में प्रक्रियात्मक और मूल निष्पक्षता की आवश्यकताओं की भावना शामिल है। यदि न्यायालय यह मानते हुए आवेदन की अनुमति देता है कि खोज आवश्यक है, तो दूसरे पक्ष को एक हलफनामा दायर करना चाहिए जिसमें उन दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जाए जो मामले से संबंधित उनके कब्जे में हैं। शपथ पत्र को परिशिष्ट सी में प्रपत्र संख्या 5 में निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।' 108 जिस प्रपत्र में शपथ पत्र देना आवश्यक है, वह नीचे दिया गया है:

डी.

ई.

च

नं. 5

दस्तावेजों के प्रति विश्वास (ओ. 11, आर. 13.) (नंबर 1 में जैसा शीर्षक है, ऊपर)

में, उपरोक्त नामित प्रतिवादी सी. डी., शपथ लेता हूं और इस प्रकार कहता हूं:—

जी.

107 सी. पी. सी. 1908 का आदेश 11 नियम 12 सी. पी. सी. 1908 ए का 108 आदेश 11 नियम 13

एच.

693

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

1. मेरे पास इस मुकदमे में विचाराधीन मामलों से संबंधित दस्तावेज हैं जो यहां पहली अनुसूची के पहले और दूसरे भागों में दिए गए हैं।

2. मुझे पहली अनुसूची के दूसरे भाग में दिए गए उक्त दस्तावेजों को यहाँ प्रस्तुत करने पर आपत्ति है।

3. यहाँ दूसरी अनुसूची में दिए गए इस वाद में विचाराधीन मामलों से संबंधित दस्तावेज मेरे पास हैं लेकिन अब मेरे पास नहीं हैं।

4. अंतिम-उल्लिखित दस्तावेज मेरे कब्जे या अधिकार में अंतिम थे। [बताएँ कि उनका कब और क्या हुआ है और अब वे किसके कब्जे में हैं।]

ग

5. मेरी जानकारी, जानकारी और विश्वास के अनुसार, मेरे पास अभी और कभी भी, अपने कब्जे, अभिरक्षा या शक्ति में, या अपने वकील या एजेंट के कब्जे, अभिरक्षा या शक्ति में, या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या शक्ति में, कोई खाता, लेखा पुस्तिका, वाउचर, रसीद, पत्र, ज्ञापन, कागज या लेखन, या ऐसे किसी भी दस्तावेज की कोई प्रति या उद्धरण, या कोई अन्य दस्तावेज जो भी इस मुकदमे या उनमें से किसी में विचाराधीन मामलों से संबंधित है, या जिसमें उक्त पहली और दूसरी अनुसूची में निर्धारित दस्तावेजों के अलावा और उनमें से किसी के संबंध में कोई प्रविष्टि की गई है।

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

135. अदालत द्वारा सभी दस्तावेजों के प्रकटीकरण का निर्देश दिए जाने के बाद, जिस पक्ष को सभी संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण करने का निर्देश दिया जाता है, वह संहिता के अनुलग्नक सी में निर्धारित प्रपत्र में अपने कब्जे में विशिष्ट दस्तावेजों के प्रकटीकरण पर आपत्ति कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश XI नियम 13 सी. पी. सी. निर्धारित करता है कि परिस्थितियों की आवश्यकता होने पर खोज के रूप को बदला जा सकता है। खोज, निरीक्षण और उत्पादन पर सी. पी. सी. के प्रावधानों का उल्लेख करने का उद्देश्य इन प्रावधानों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत को स्पष्ट करना और उसका विस्तार करना है। अर्थात्, जबकि एक पक्ष दूसरे पक्ष के कब्जे में दस्तावेजों की खोज चाहता है, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि

दस्तावेजों का प्रकटीकरण कार्यवाही के परिणाम के लिए प्रासंगिक होगा। इस तरह का विचार खोज के चरण में उत्पन्न नहीं होता है। यह केवल उचित है कि बोझ

च

जी.

एच.

694

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सबूत पूरी तरह से उस पक्ष पर निर्भर करता है जो सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाने के लिए और सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा के दावे को सही ठहराने के लिए खुलासा करने पर आपत्ति करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खोज के चरण में उत्पादन की मांग करने वाले पक्ष पर जो बोझ डाला जाता है, वह खोज पर आपत्ति के स्तर पर ऐसी खोज का विरोध करने वाले पक्ष पर लगाए गए बोझ के साथ नहीं लगाया जाता है।

136. एस. पी. गुप्ता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि राज्य जनहित उन्मुक्ति के आधार पर दस्तावेजों के प्रकटीकरण पर आपत्ति करता है, तो न्यायालय शपथ पत्र में दिए गए कारणों के आधार पर आपत्ति की वैधता का आकलन करेंगे। अदालत के पास दस्तावेज का निरीक्षण करने की शक्ति है यदि हलफनामे के अवलोकन पर, अदालत

ग

इस बात पर कोई संदेह है कि क्या दस्तावेज के मामलों से संबंधित है

राज्य '।109 इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गैर-प्रकटीकरण के कारणों (आधारों के साथ) को निर्धारित करने वाला हलफनामा पर्याप्त विस्तार से बनाया जाए ताकि अदालतें पी. आई. आई. के दावे का आकलन कर सकें। एस. पी. गुप्ता (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा है कि दावा मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए जो संबंधित विभाग का राजनीतिक प्रमुख है या उसे विफल करने पर विभाग के सचिव द्वारा किया जाना चाहिए। दावा हमेशा शपथ पत्र के रूप में किया जाना चाहिए। सरकार को औचित्य के दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए शपथ पत्र में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी की सीमा उस जांच के मानक पर आधारित है जिसे न्यायालय जनहित प्रतिरक्षा दावों का आकलन करने के लिए लागू करता है।

डी.

ई.

I. जनहित प्रतिरक्षा दावों का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक

137. जनहित प्रतिरक्षा दावे का सार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए एक अपवाद की तलाश करना है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुपालन से विचलन, यह साबित होने के बाद कि पक्ष को गैर-अनुपालन के कारण एक निष्पक्ष और उचित सुनवाई से वंचित कर दिया गया है, आनुपातिकता मानक पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

च

138. उपरोक्त चर्चा के अलावा, हमारी राय है कि अदालतों को निम्नलिखित कारणों से जनहित प्रतिरक्षा के दावों का आकलन करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग करना चाहिए:

जी.

(i) सबसे पहले, राज्य जनहित प्रतिरक्षा के लिए दावा करते समय एक से विचलित होने के लिए एक समायोजन की मांग करता है

109 एस. पी. गुप्ता (पैराग्राफ 77)

एच.

695

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

प्राकृतिक न्याय का स्थापित सिद्धांत, अर्थात् उस मामले को जानने का अधिकार जो प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने के कारण किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है। यह दावा अपनी प्रकृति से संविधान के अनुच्छेद 21 से बहने वाले निष्पक्ष मुकदमे या सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है। जनहित उन्मुक्ति के दावे की वैधता का आकलन करते समय अदालतों की भूमिका यह निर्धारित करने तक सीमित है कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार का उल्लंघन है।

उचित है;

((ii) दूसरा, यद्यपि एस. पी. गुप्ता (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पी. आई. आई. के दावे का आकलन करने के लिए संरचित आनुपातिकता के मानक का उपयोग नहीं किया क्योंकि यह वर्तमान रूप में मौजूद है, लेकिन जो मानक निर्धारित किया गया था वह आनुपातिकता मानक के उप-पहलुओं से मिलता-जुलता था क्योंकि इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था: (i) प्रभाव और गैर-प्रकटीकरण का उद्देश्य नहीं; और (ii) प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण (तथ्यों और सिद्धांत दोनों पर) के प्रभावों को संतुलित करना। इस न्यायालय ने 'दस्तावेजों के वर्ग' के आधार पर दावे से ध्यान हटा दिया और व्यक्तिगत सामग्री के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित किया। ये दोनों सिद्धांत संरचित आनुपातिकता के मानक के महत्वपूर्ण घटक हैं जो निर्धारित किए गए थे।

ग

डी.

इस न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) (ऊपर) में;

ई.

((iii) आनुपातिकता मानक एक मानक चार चरणीय परीक्षण निर्धारित करके औचित्य की संस्कृति शुरू करने के अलावा, जिसे संतुष्ट किया जाना चाहिए, अदालतों को प्रत्येक चरण के भीतर उस न्यायशास्त्र को लागू करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है जो इस विषय पर अदालतों द्वारा पहले ही विकसित किया जा चुका है; और

च

((iv) अंत में, पी. आई. आई. दावा सामान्य कानून सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय पर विभिन्न सामान्य कानून देशों से उत्पन्न न्यायशास्त्र पर भारत के न्यायालयों द्वारा हमारी संवैधानिक योजना द्वारा अनुमत सीमा तक भरोसा किया गया है। इस विषय पर अन्य सामान्य कानून देशों से उत्पन्न न्यायशास्त्र का एक प्रेरक मूल्य है। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा दोनों की अदालतें पी. आई. आई. दावे की वैधता का आकलन करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग करती हैं। 139. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए अदालतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संरचित आनुपातिकता मानक को फिर से तैयार किया जाना चाहिए

जी.

एच.

[2023] 10 एस सी आर।

यदि आवश्यक हो तो लोक हित प्रतिरक्षा पर न्यायशास्त्र की पंक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और अनुच्छेद 19 (6) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के बीच शब्दावली में अंतर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 में उचित प्रतिबंध खंड निर्धारित करते हैं कि

संप्रभुता के हितों में 'यथोचित रूप से प्रतिबंधित' किया जा सकता है और

भारत की अखंडता [.] धारा 124 में कहा गया है कि प्रकटीकरण पर प्रतिबंध केवल तभी उचित है जब जनहित को नुकसान पहुंचे। इस प्रकार, धारा 124 जनहित प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग के लिए एक उच्च मानक निर्धारित करती है।

140. आनुपातिकता मानक केवल संतुलन चरण में उल्लंघन के प्रभाव का परीक्षण करता है। आनुपातिकता मानक की उपयुक्तता और वैध लक्ष्य दोनों को प्रभावों के विपरीत उद्देश्य की भाषा में तैयार किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 में कहा गया है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और अनुच्छेद 21 और 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित सूचना का अधिकार जनहित को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 में निहित सिद्धांत यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को खत्म करने के लिए कोई भी उद्देश्य पर्याप्त महत्व का नहीं हो सकता है। इस तरह का प्रतिबंध अनुचित है। यह केवल जनहित की चोट है जो दस्तावेजों का खुलासा न करने को उचित ठहराती है।

ग

डी.

141. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा आधुनिक दंत चिकित्सा (ऊपर) में निर्धारित आनुपातिकता मानक को साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों और एस. पी. गुप्ता (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियों द्वारा निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म किया जाना चाहिए। एक वैध लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उपाय के अलावा, एक वैध लक्ष्य को नुकसान होना चाहिए। आनुपातिकता मानक के सभी उप-पहलुओं को साबित करने के लिए सामग्री के प्रकटीकरण का विरोध करने वाले पक्ष पर बोझ है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के सिद्धांतों पर आधारित संरचित आनुपातिकता मानक इस प्रकार है: (i) क्या सूचना के प्रकटीकरण से जनता को नुकसान होगा।

ई.

च

ब्याज (चोट चरण);

((ii) क्या कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी वैकल्पिक साधन है; जिसके द्वारा सार्वजनिक हित को हुए नुकसान की रक्षा की जा सकती है (आवश्यकता चरण); और

जी.

((iii) क्या गैर-प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित प्रकटीकरण (संतुलन चरण) में सार्वजनिक हित से अधिक है।

142. संतुलनकारी चरण में, जैसा कि इस अदालत द्वारा एस. पी. गुप्ता (ऊपर) और यूनाइटेड किंगडम और ए. में अदालतों में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

एच.

कनाडा में, मामले के तथ्यों और सिद्धांत के व्यापक प्रश्नों के आधार पर विचारों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या गैर-प्रकटीकरण मुद्दे को गैर-न्यायसंगत बना देगा, सामग्री की सापेक्ष प्रासंगिकता-इस बात पर कि क्या सामग्री 'महत्वपूर्ण' है या 'आवश्यक' है, या दावेदार के खिलाफ मामले का सार है। सिद्धांतों के प्रश्नों पर, न्यायालय प्रेस की स्वतंत्रता जैसे अन्य संवैधानिक अधिकारों पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव पर विचार करेगा।

जे. जनहित प्रतिरक्षा या सीलबंद आवरण: कम प्रतिबंधात्मक साधन

143. न्यायालय को सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा के दावों का आकलन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 की सामग्री के आधार पर संशोधित संरचित आनुपातिकता मानक का पालन करना चाहिए। संरचित आनुपातिकता मानक के तहत, अदालत गैर-प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित के दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजों के प्रकटीकरण का विरोध करने वाले पक्ष पर सबूत का बोझ डालती है। आनुपातिकता परीक्षण किसी क्रिया की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए एक सख्त मानक निर्धारित करता है। आनुपातिकता के संरचित मानक के विपरीत, जिसका उपयोग अदालत द्वारा सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए, अदालतों द्वारा सीलबंद लिफाफे में सामग्री को सुरक्षित करने के लिए शक्ति का प्रयोग अस्थायी और असाधारण रहा है।

ग

डी.

144. संविधान का अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 145 के तहत अपनी शक्ति के अनुसरण में, सर्वोच्च न्यायालय नियम 1966 110 को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में सीलबंद लिफाफे में अदालत को दस्तावेजों के प्रकटीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। 1966 के नियमों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश XIII नियम 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए एक पक्ष सभी अभिवचनों, निर्णयों, फरमानों या आदेशों, दस्तावेजों और कार्यवाही में किए गए या प्रदर्शित गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने का हकदार होगा। नियम 7 नियम के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। नियम में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेजों का अधिकार नहीं है जो (i) गोपनीय हों; (ii) अदालत या मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया गया हो; और (iii) जिनका खुलासा सार्वजनिक हित में नहीं है। नियम में कहा गया है कि उपरोक्त खंडों में से किसी के भीतर आने वाले दस्तावेजों का खुलासा केवल अदालत या मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किया जा सकता है। आदेश XIII नियम 7 संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

ई.

च

जी.

एच.

110 “ 1966 नियम ”

698

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“7. इस आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी पक्ष या व्यक्ति को किसी भी गोपनीय प्रकृति के कार्यवृत्त, पत्र या दस्तावेज या भेजे गए, दायर किए गए या पेश किए गए किसी भी पत्र की प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देता है या जिसे गोपनीय प्रकृति का मानता है या जिसका प्रकाशन जनता के हित में नहीं माना जाता है, सिवाय मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत और उसके अनुसार।” 145. सीलबंद लिफाफे में कार्यवाही से संबंधित सामग्री प्राप्त करने की अदालत की शक्ति को आदेश XIII नियम 7 से पढ़ा जाता है। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में बंद सामग्री प्रक्रिया के विपरीत, सीलबंद आवरण प्रक्रिया विधायिका का नहीं बल्कि अदालतों का निर्माण है। वास्तव में, नियम 7 सीलबंद लिफाफे में सामग्री प्राप्त करने की अदालत की शक्ति को निर्धारित करते हुए जनहित प्रतिरक्षा के आधार पर गैर-प्रकटीकरण को भी मान्यता देता है। यह प्रावधान सीलबंद लिफाफे में सामग्री को सुरक्षित करने के लिए अदालत द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए किसी भी दिशानिर्देश को निर्धारित नहीं करता है। हालांकि, समग्र रूप से नियम इंगित करता है कि अदालत सीलबंद लिफाफे में सामग्री को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है यदि सामग्री गोपनीय है या जिसका खुलासा सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जनहित प्रतिरक्षा के दावे भी उन्हीं नुकसानों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह इरादा नहीं था कि सीलबंद आवरण प्रक्रिया जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही का स्थान लेगी जो गोपनीयता के दावों से निपटने के लिए एक स्थापित विधि का गठन करती है। सीलबंद आवरण प्रक्रिया को उन नुकसानों को कवर करने के लिए शुरू नहीं किया जा सकता है जिन्हें जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था।

ग

डी.

ई.

146. सीलबंद आवरण प्रक्रिया और जनहित प्रतिरक्षा दावों दोनों में, जिन दस्तावेजों को प्रकटीकरण से रोकने की मांग की जाती है, उन्हें आवेदक के वकील के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। कार्यवाही, वास्तव में, एकतरफा रूप से आयोजित की जाती है जहां प्रकटीकरण का दावा करने वाले पक्ष के वकील को कार्यवाही में रिकॉर्ड के एक हिस्से तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। हालांकि, सीलबंद कवर प्रक्रिया और जनहित प्रतिरक्षा दावों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले मामले में, अदालत उस सामग्री पर निर्भर करती है जो कार्यवाही के दौरान सीलबंद कवर में प्रकट की जाती है, जबकि दूसरे मामले में दस्तावेजों को कार्यवाही से पूरी तरह से हटा दिया जाता है और दोनों पक्ष और न्यायनिर्णायक ऐसी सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। सीलबंद आवरण प्रक्रियाएँ प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय दोनों के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। अल रावी बनाम सुरक्षा सेवा 111 में, संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय

च

जी.

एच.

111 (2011) यूकेएससी 34 ए

699

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

साम्राज्य ने माना कि बंद सामग्री प्रक्रिया सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा की तुलना में अधिक नुकसान का कारण बनती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बंद सामग्री प्रक्रिया सीलबंद आवरण प्रक्रिया के समान है, उतनी ही प्रासंगिक सामग्री जो आवेदक को प्रकट नहीं की जाती है, मूल सुनवाई के दौरान उपयोग की जाती है। उस मामले में, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या न्यायालय के पास पूरे या मुकदमे के एक हिस्से के लिए एक बंद सामग्री प्रक्रिया का आदेश देने की शक्ति है। एक बंद कार्यवाही में, दावेदार का प्रतिनिधित्व एक विशेष अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा जो दावेदार से निर्देश लेने में असमर्थ होगा। यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बंद सामग्री प्रक्रिया, सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा से संबंधित कानून के विपरीत, खुले न्याय और प्राकृतिक न्याय दोनों के सिद्धांतों से अलग है। लॉर्ड डायसन ने अपनी राय में कहा:

“41. [...]पी. आई. आई. प्रक्रिया उन सामान्य कानून सिद्धांतों का सम्मान करती है जिनका मैंने उल्लेख किया है। यदि प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दस्तावेजों का खुलासा किया जाता है, तो वे दोनों पक्षों और अदालत के लिए उपलब्ध हैं। यदि उनका खुलासा नहीं किया जाता है, तो वे न तो अन्य पक्षों के लिए उपलब्ध हैं और न ही अदालत के लिए। दोनों पक्षों को मुकदमे के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। हथियारों में कोई अन्याय या असमानता नहीं है। एक बंद सामग्री प्रक्रिया का प्रभाव यह है कि बंद दस्तावेज केवल उस पक्ष के लिए उपलब्ध हैं जिसके पास वे हैं, दूसरे पक्ष के विशेष अधिवक्ता और अदालत। मैं पहले ही विशेष अधिवक्ता प्रणाली की सीमाओं का उल्लेख कर चुका हूँ।”

डी.

ई.

147. कार्यवाही से जानकारी को पूरी तरह से हटाने के दो प्रभाव होते हैं। सबसे पहले, यह दावेदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर सकता है, जिससे मुद्दा गैर-न्यायसंगत हो जाता है। दूसरा, यह प्रतिवादी (इस मामले में, राज्य) को रक्षाहीन बना सकता है। अदालत को यह तय करते समय इन विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या जनहित प्रतिरक्षा दावा कम प्रतिबंधात्मक साधन है। इस प्रकार, दूसरे चरण में, जांच इस बात में बदल जाती है कि क्या एक सफल पी. आई. आई. दावे पर बाहर रखी गई जानकारी को कार्यवाही से उचित रूप से हटाया जा सकता है। 148. कार्यवाही में राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना पर न्यूजीलैंड विधि आयोग की रिपोर्ट संवेदनशील जानकारी से निपटने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया प्रदान करती है। 112 पहला विचार यह है कि क्या जानकारी को पक्ष को एक संतुलन पर प्रकट किया जाना चाहिए

च

जी.

112 विधि आयोग, द क्राउन इन कोर्ट: अदालती कार्यवाही अधिनियम और कार्यवाही में राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना की समीक्षा (दिसंबर 2015, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड)

एच.

रिपोर्ट 135

700

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

विचार करें। दूसरा विचार यह है कि क्या जानकारी को कार्यवाही से उचित रूप से बाहर रखा जा सकता है। आयोग ने सिफारिश की कि अदालत को बंद सामग्री कार्यवाही का विकल्प केवल तभी चुनना चाहिए जब सामग्री कार्यवाही के लिए पर्याप्त रूप से प्रासंगिक हो कि सूचना को बाहर करने और इसके बिना आगे बढ़ने के बजाय एक बंद प्रक्रिया का उपयोग करना न्याय के हित में होगा।” अर्थात्, न्यायालय का निष्कर्ष है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार इतने अधिक हैं कि वे कार्यवाही में दस्तावेज की प्रासंगिकता पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन जानकारी को कार्यवाही से उचित रूप से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ऊपर पहचाने गए दो चोटों में से एक का कारण बन सकता है। आयोग ने सिफारिश की है कि इस तरह के अन्याय को दूर करने के लिए बंद कार्यवाही का पालन करना न्याय के हित में होगा। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्याय के हित की रक्षा के लिए जनहित प्रतिरक्षा प्रक्रिया के अलावा बंद सामग्री प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यूजीलैंड के विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी माना गया कि हालांकि एक बंद प्रक्रिया का विकल्प राज्य के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन राज्य के लिए यह साबित करना मुश्किल होगा कि यह न्याय के हित में होगा क्योंकि यह दावेदार से जानकारी को रोकना चाहता है और उनके खिलाफ इसका उपयोग करना चाहता है। आयोग की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं: “ 5.51 इस दूसरे चरण में, अदालत यह निर्धारित करती है कि मूल सुनवाई के हिस्से के लिए एक बंद प्रक्रिया के उपयोग का आदेश दिया जाए या नहीं। न्यायालय को केवल आदेश देना चाहिए कि मूल सुनवाई के हिस्से को बंद कर दिया जाए जहां यह संतुष्ट हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी कार्यवाही के

लिए पर्याप्त रूप से प्रासंगिक है कि जानकारी को बाहर करने के बजाय एक बंद प्रक्रिया का उपयोग करना न्याय के हित में है और मामले को इसके बिना आगे बढ़ाना है। हालाँकि उन मामलों में एक बंद प्रक्रिया उपलब्ध होगी जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी क्राउन के मामले के लिए फायदेमंद थी, क्राउन के लिए न्याय परीक्षण के हितों को संतुष्ट करना बहुत कठिन होगा क्योंकि यह दूसरे पक्ष से जानकारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका उपयोग उनके खिलाफ भी कर रहा है। कुछ मामलों में जहाँ क्राउन किसी कार्रवाई का बचाव कर रहा है, अदालतें मान सकती हैं कि यह उचित है, लेकिन हम अनुमान लगाएंगे कि यह काफी दुर्लभ होगा। यह अधिक संभावना है कि एक बंद प्रक्रिया न्याय के हित में होगी जहाँ यह गैर-क्राउन पक्ष को पूर्वाग्रहित करेगा यदि अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी को बाहर करती है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

149. यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक ए के सफल दावे पर प्रासंगिक सामग्री के बहिष्कार के प्रभाव पर विचार किया।

एच.

701

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

अल रावी (ऊपर) में ब्याज प्रतिरक्षा। उस मामले में, राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि न्यायालय को कुछ वर्गों के मामलों में एक बंद सामग्री प्रक्रिया का आदेश देने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि जहाँ प्रतिवादी अपने बचाव को पूरी तरह से (या कभी-कभी बिल्कुल नहीं) तैनात नहीं कर सकता है यदि एक खुली प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह तर्क दिया गया था कि जनहित प्रतिरक्षा अभ्यास के बाद कार्यवाही से प्रासंगिक सामग्री को बाहर रखने से अदालत के सही परिणाम तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, राज्य का मामला यह था कि अदालत के पास असाधारण परिस्थितियों में जनहित प्रतिरक्षा अभ्यास के लिए एक बंद सामग्री प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। जबकि अदालत ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि अदालतें बंद सामग्री प्रक्रिया के साथ एक सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं, न्यायाधीश इस बात पर असहमत थे कि क्या सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा प्रक्रिया के अलावा एक बंद सामग्री प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, न कि वैकल्पिक रूप से।

ग

150. लॉर्ड डायसन ने अपनी राय में कहा कि अदालत के पास जनहित प्रतिरक्षा दावे के अलावा बंद सामग्री प्रक्रिया को निर्देशित करने की शक्ति नहीं है क्योंकि: (i) बंद सामग्री प्रक्रिया जनहित प्रतिरक्षा प्रक्रिया का विरोधी है। बंद सामग्री प्रक्रिया में हथियारों की कोई समानता नहीं है; (ii) दस्तावेज के कब्जे वाले पक्ष को इस बात की एकमात्र जानकारी है कि दस्तावेज उनके मामले में फायदेमंद होगा या नहीं। दावेदार, जिसके पास सामग्री तक पहुंच नहीं है, उसे पता नहीं होगा कि क्या सामग्री उनके मामले को प्रभावित करेगी। इस प्रकार यह उन्हें एक प्रतिकूल स्थिति में डाल देगा जिससे प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से किसी एक पक्ष के लिए अनुचित हो जाएगी और (iii) अदालतों को दावेदार और प्रतिवादी के मामले में किसी दस्तावेज की प्रासंगिकता तय करने का अभ्यास करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।

डी.

ई.

151. लॉर्ड केर ने अपनी राय में राज्य के तर्क के साथ दो अतिरिक्त समस्याओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव कि न्यायाधीश के समक्ष सभी साक्ष्य रखना कार्यवाही से संभावित रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य को रोकने से बेहतर है, भ्रामक है। लॉर्ड केर ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायनिर्णायक एक उचित परिणाम तक पहुंच जाएगा क्योंकि न्यायाधीश सभी साक्ष्यों को देखता है क्योंकि वास्तव में मूल्यवान होने के लिए, साक्ष्य को चुनौती का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

च

जी.

“93. अपीलार्थियों का दूसरा तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि न्यायाधीश के समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री को रखना, हर मामले में, संभावित रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य को रोकने से बेहतर है। यह प्रस्ताव भ्रामक रूप से आकर्षक है—जिसके लिए, अपीलार्थी संकेत देते हैं,

एच.

702

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क्या एक स्वतंत्र मध्यस्थ की तुलना में बेहतर हो सकता है जिसकी पक्षों के बीच विवाद के लिए सभी सबूतों तक पहुंच हो? हालाँकि, तर्क की केंद्रीय भ्रांति इस अनकही धारणा में निहित है कि, क्योंकि न्यायाधीश सब कुछ देखता है, वह एक उचित परिणाम तक पहुँचने के लिए बेहतर स्थिति में होने के लिए बाध्य है। यह धारणा

गलत जगह पर है। वास्तव में मूल्यवान होने के लिए, साक्ष्य को चुनौती का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मैं और आगे जाता हूँ। साक्ष्य जो चुनौती से अछूता है, सकारात्मक रूप से गुमराह कर सकता है। यह ठीक इसी वजह से है कि किसी के प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाए गए मामले को जानने का अधिकार और इसे चुनौती देने का अवसर एक निष्पक्ष मुकदमे की अवधारणा में ऐसा केंद्रीय स्थान रखता है। न्यायाधीश चाहे कितना भी चतुर और मेहनती क्यों न हो, प्रस्तावित प्रक्रिया प्रासंगिक सामग्री के उत्पादन और इसे प्रस्तुत करने के तरीके पर एक पक्ष को काफी नियंत्रण सौंपती है। इस तरह की प्रक्रिया से विवादास्पद मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई को जो खतरा होता है, वह स्पष्ट और निर्विवाद दोनों है।”

ग

डी.

(जोर दिया गया)

152. लॉर्ड केर ने आगे कहा कि राज्य जनहित प्रतिरक्षा दावों के साथ एक स्वस्थ दुविधा का सामना कर रहा है क्योंकि वह अपने दावे का बचाव करने के लिए अधिक से अधिक सामग्री का उत्पादन करना चाहेगा और जनहित प्रतिरक्षा दावों का आराम से सहारा नहीं लेगा क्योंकि यदि उनके दावे की अनुमति दी जाती है, तो सामग्री को कार्यवाही से ही हटा दिया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यह राज्य के लिए एक बंद सामग्री प्रक्रिया की मांग करने के लिए लुभावना होगा, यह दावा करते हुए कि सभी दस्तावेजों का खुलासा होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होगा।

ई.

153. लॉर्ड मैन्स (जिनके साथ लॉर्ड हेल सहमत हुए) और लॉर्ड क्लार्क ने कहा कि अदालत के पास जनहित प्रतिरक्षा दावे का फैसला होने के बाद कुछ परिस्थितियों में एक बंद सामग्री प्रक्रिया का आदेश देने की शक्ति है। हालाँकि, वे इस बात पर असहमत थे कि वे कुछ परिस्थितियाँ क्या होंगी। लॉर्ड मैन्स के विचार में, जनहित प्रतिरक्षा दावे की अनुमति के बाद, अदालत एक बंद

सामग्री प्रक्रिया का आदेश दे सकती है यदि सामग्री प्रतिवादी के कब्जे में है और दावेदार अपने दावे को खारिज होने से बचाने के लिए ऐसी प्रक्रिया के लिए सहमति देता है।लॉर्ड क्लार्क के विचार में, जनहित प्रतिरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पक्षों को अपने-अपने पदों पर विचार करना चाहिए और न्यायाधीश के समक्ष अभ्यावेदन करना चाहिए जो मामले के तथ्यों के आधार पर एक बंद सामग्री प्रक्रिया का आदेश दे सकते हैं।

च

जी.

एच.

703

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

154. न्यूजीलैंड के विधि आयोग की सिफारिशें और अल रावी (ऊपर) में लॉर्ड क्लार्क और लॉर्ड मैन्स की राय जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही के पूरा होने के बाद एक अतिरिक्त कदम के रूप में बंद सामग्री कार्यवाही शुरू करती है।सीलबंद आवरण प्रक्रिया के समान एक बंद सामग्री प्रक्रिया में न्यायालय उस सामग्री पर निर्भर करता है जिसे दावेदार कार्यवाही का निपटान करते समय गुप्त नहीं रखता है।जनहित उन्मुक्ति कार्यवाही के समापन पर हुए अन्याय (ओं) को संतुलित करने के लिए बंद सामग्री कार्यवाही शुरू करने की मांग की जाती है।

155. दावेदार अपनी आँखें बंद करके आग के गड्ढे में कूद रहा होगा, भले ही वह एक सीलबंद आवरण प्रक्रिया के लिए सहमत हो।जैसा कि लॉर्ड केर ने अल रावी (ऊपर) में टिप्पणी की, यह दावा कि बंद सामग्री प्रक्रिया एक बेहतर परिणाम प्रदान करेगी, इस धारणा पर आधारित है कि न्यायनिर्णायक निष्पक्ष है।हालांकि, इस धारणा से परे, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अदालत को ऐसी सामग्री से गुमराह किया जा सकता है जो निरीक्षण और परीक्षा के अधीन नहीं है।इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां अदालत एक अनुचित निर्णय देती है और इस तरह का अनुचित निर्णय न्यायिक समीक्षा और गुण-दोष पर सार्वजनिक आलोचना दोनों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ग

डी.

156. हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनहित प्रतिरक्षा दावे की अनुमति देने से दावेदार और प्रतिवादी की प्रक्रियात्मक गारंटी को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, एक सीलबंद आवरण प्रक्रिया एक निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करेगी।जनहित उन्मुक्ति कार्यवाही का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा यदि प्रतिवादी को जनहित उन्मुक्ति कार्यवाही के समापन के बाद एक बंद सामग्री प्रक्रिया का अनुरोध करने का विकल्प प्रदान किया जाता है, जिसे प्रतिवादी अनुमति देता है।बल्कि, हमारी राय है कि कार्यवाही से साक्ष्य को पूरी तरह से हटाने की जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही का प्रभाव राज्य को जनहित प्रतिरक्षा के सीमित दावे करने के लिए राजी करेगा।इसके अलावा, जैसा कि लॉर्ड डायसन ने टिप्पणी की, प्रक्रिया दावेदार के लिए स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह होगी क्योंकि वे दस्तावेज की सामग्री से अनजान हैं।

ई.

च

जी.

157. यह तर्क दिया जा सकता है कि कार्यवाही से दस्तावेजों को हटाने से कार्यवाही गैर-न्यायसंगत हो जाएगी यदि जिन दस्तावेजों को संरक्षित करने की मांग की जाती है, वे कार्रवाई के कारण के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं।हालांकि तर्क एक सरसरी नज़र में योग्यता रखता है, लेकिन गहराई में जाने पर यह पानी नहीं पकड़ता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, संतुलन में अदालत के लिए प्रासंगिक विचारों में से एक

जनहित प्रतिरक्षा दावे पर निर्णय लेने का चरण यह है कि क्या सामग्री का खुलासा न करने से मुद्दा गैर-न्यायसंगत हो जाएगा। अदालत सामग्री की प्रासंगिकता और गैर-प्रकटीकरण के कारण मुद्दे की संभावित गैर-न्यायसंगतता का विश्लेषण करते हुए निर्देश दे सकती है कि सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए। बैलेंसिंग प्रांग का उद्देश्य इस तरह के दावों के परस्पर विरोधी दावों और प्रभावों पर विचार करना है। भले ही प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे, फिर भी अदालतें सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा के दावे को खारिज कर सकती हैं यदि गैर-प्रकटीकरण मुद्दे को गैर-न्यायसंगत बना देगा, और मामले के तथ्यों पर यह निर्णय लिया जाता है कि गैर-प्रकटीकरण के कारण होने वाली चोट प्रकटीकरण के कारण होने वाली चोट से अधिक है।

ग

158. अदालतें दस्तावेज के गोपनीय भागों को संशोधित करने और दस्तावेज की सामग्री का सारांश प्रदान करने की कार्यवाही को अपना सकती हैं, बजाय इसके कि वे एक सफल सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे पर दस्तावेज को कार्यवाही से निष्पक्ष रूप से बाहर करने के लिए सीलबंद आवरण प्रक्रिया का विकल्प चुनें। दोनों पक्षों को केवल दस्तावेज के संशोधित संस्करण या कार्यवाही में सारांश का उल्लेख करने की अनुमति दी जा सकती है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही जनहित और गोपनीयता के आधार पर गैर-प्रकटीकरण से निपटने के लिए एक कम प्रतिबंधात्मक साधन है। यह अंतिम मुद्दे का जवाब देने के लिए छोड़ देता है: यदि जनहित प्रतिरक्षा एक कम प्रतिबंधात्मक साधन है, तो क्या सीलबंद आवरण की प्रक्रिया का बिल्कुल भी उपयोग किया जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो किन परिस्थितियों में न्यायालय को सीलबंद आवरण में साक्ष्य प्राप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति होगी। हालांकि यह इस निर्णय के दायरे से बाहर होगा कि संभावित स्थितियों को निर्धारित किया जाए जब सीलबंद आवरण प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, यह कहना पर्याप्त है कि यदि उद्देश्य को सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा कार्यवाही या किसी अन्य कम प्रतिबंधात्मक माध्यम से प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, तो सीलबंद आवरण प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय को संभावित प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों का विश्लेषण करना चाहिए जिनका उपयोग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और ऐसे साधन जो प्रक्रियात्मक गारंटी के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं, उन्हें अपनाया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

159. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रत्यर्थियों ने लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं करके, प्रासंगिक सामग्री का खुलासा नहीं करके और केवल सीलबंद लिफाफे में अदालत को सामग्री का खुलासा करके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निष्पक्ष सुनवाई के अपीलार्थी के अधिकार का उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी यह साबित करने में असमर्थ थे कि अपीलार्थियों पर प्रतिबंध 'ए'

जी.

एच.

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उचित था। इसलिए, लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार करने वाले 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश और 2 मार्च 2022 के उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए।

गारंटी। के सारवान चुनौती: अनुमति के नवीनीकरण से इनकार करने में एम. आई. बी. की कार्रवाई की वैधता

160. अपनी दलीलों के दौरान, श्री हुजेफा ए अहमदी ने प्रक्रियात्मक गारंटी के उल्लंघन पर दलीलों के अलावा, अदालत से अनुरोध किया कि वह उस सामग्री पर विचार करे जो केवल एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को प्रकट की गई थी ताकि यह तय किया जा सके कि क्या अनुमति के नवीनीकरण को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इस प्रकार, इस निष्कर्ष के बावजूद कि हम 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश और प्रक्रियात्मक आधार पर 2 मार्च 2022 के उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए ऊपर पहुंच गए हैं, हम एम. एच. ए. द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार के आधार पर अनुमति के नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश को ठोस चुनौती देने पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।

ग

डी.

161. 2010 में, एमबीएल ने समाचार और वर्तमान मामलों के टेलीविजन चैनल, 'मीडिया वन' को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए आईबी और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। सी. बी. आई. ने टिप्पणी की कि एम. बी. एल. के खिलाफ रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। आई. बी. ने बताया कि एम. बी. एल. का 'मध्यम डेली' के साथ घनिष्ठ संबंध है और मध्यम डेली द्वारा प्रकाशित लेखों का महत्व प्रतिकूल है। लेखों के प्रतिकूल संदर्भ पर अपने निष्कर्ष को साबित करने के लिए, आईबी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव और "मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार हिंदू कट्टरपंथियों" के खिलाफ कथित रूप से नरम रवैये पर मध्यम दैनिक की रिपोर्टों का उल्लेख किया। एमएचए ने रिपोर्ट पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि टिप्पणियां सुरक्षा आधार पर अनुमति से इनकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थीं, जिससे एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी मिल गई। 162. 2014-2019 के बीच, इसी तरह की रिपोर्ट आईबी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जब एमबीएल के अन्य प्रस्तावों के लिए सुरक्षा मंजूरी मांगी गई थी। आई. बी. ने एम. बी. एल. की आय के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल टिप्पणी की, जो कथित तौर पर जे. ई. आई.-एच. के समर्थकों से था, और इसके प्रतिष्ठान विरोधी रुख पर। अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए कि एम. बी. एल. प्रतिष्ठान विरोधी रुख अपना रहा है, यू. ए. पी. ए., सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, सरकार की विकास परियोजनाओं, मुठभेड़ हत्याओं, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, एन. आर. सी., एन. पी. आर., भारतीय न्यायपालिका के कथित "आतंकवाद के मामलों में दोहरे मानकों" पर इसकी रिपोर्टों का संदर्भ दिया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

706

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

और सुरक्षा बलों का कथित रूप से गलत चित्रण। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर एमएचए ने सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या ये कारण सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं, और इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एमबीएल के प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करते हैं।

163. प्रेस की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक घटक के रूप में संरक्षित है, केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती है। अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों में "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में शामिल हैं।" हम इस फैसले के भाग सी में पहले ही कह चुके हैं कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता है। एक समाचार चैनल के संचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी से इनकार करना प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है, और इस तरह के प्रतिबंध केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों पर संवैधानिक रूप से अनुमत हैं।

ग

डी.

164. यद्यपि न्यायालय आधुनिक दंत चिकित्सा (ऊपर) और न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) (ऊपर) में निर्णयों के बाद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसे आम तौर पर विधायी कार्रवाई के क्षेत्र में लागू किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों के सभी उल्लंघनों का परीक्षण आनुपातिकता के मानक पर किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत अदालत के पास मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले 'कानूनों' को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। प्रावधान के उद्देश्य के लिए, 'कानून' में प्रशासनिक कार्रवाई शामिल है। कानून की स्थिति कि मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने वाली प्रशासनिक कार्रवाई का आनुपातिकता मानक पर परीक्षण किया जाना है, इस अदालत द्वारा अपने पहले के फैसलों में स्थापित किया गया है।¹¹³ इस प्रकार, अनुमति के नवीनीकरण से इनकार करने वाली एम. आई. बी. की कार्रवाई की आनुपातिकता मानक के आधार पर न्यायिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

ई.

च

165. आधुनिक दंत चिकित्सा (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित आनुपातिकता मानक के पहले परीक्षण के लिए न्यायालय को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले उपाय का कोई वैध लक्ष्य है। अनुच्छेद 19, संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के विपरीत, उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिनके लिए मान्यता प्राप्त अधिकारों को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार,

जी.

113 ओम कुमार बनाम भारत संघ, (2001) 2 एस. सी. सी. 386; भारत संघ बनाम गणयुथम, (1997) 7 एस. सी. सी. 463 ए.

एच.

707

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

चुनौती दी गई राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य आवश्यक रूप से अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों का पता लगाने योग्य होना चाहिए ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा मंजूरी को दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया था: एमबीएल का कथित स्थापना विरोधी रुख, और जे. ई. आई.-एच. के साथ एमबीएल का कथित संबंध।

166. एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालती है। प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को कठिन तथ्यों के साथ पेश करे जो उन्हें ऐसे विकल्प चुनने में सक्षम बनाते हैं जो लोकतंत्र को सही दिशा में ले

जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी दृष्टिकोण के साथ सोचने के लिए मजबूर करता है। सामाजिक-आर्थिक राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा करेगा।

ग

167. सरकार की नीतियों पर चैनल, मीडिया-वन के आलोचनात्मक विचारों को 'प्रतिष्ठान विरोधी' नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग अपने आप में एक उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस को प्रतिष्ठान का समर्थन करना चाहिए। एम. आई. बी. की उन विचारों के आधार पर एक मीडिया चैनल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने की कार्रवाई, जो चैनल संवैधानिक रूप से रखने का हकदार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव पैदा करती है। सरकारी नीति की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित किसी भी आधार के साथ कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं लाया जा सकता है।

डी.

ई.

168. जे. ई. आई.-एच. की कथित भूमिका और गतिविधियों पर आई. बी. द्वारा प्रस्तुत नोट में कहा गया है कि संगठन को तीन बार प्रतिबंधित किया गया था और तीनों प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया था। इस संगठन को पिछली बार 1992 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1947 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अदालत ने 1994 में प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। इस प्रकार, जब जे. ई. आई.-एच. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, तो राज्य के लिए यह तर्क देना अनिश्चित होगा कि संगठन के साथ संबंध राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त, एमबीएल को जे. ई. आई.-एच. से जोड़ने के लिए फाइल में एकमात्र सबूत जे. ई. आई.-एच. के कैडरों द्वारा एमबीएल के शेयरों में कथित निवेश है। इसके समर्थन में आईबी ने शेयरधारकों की एक सूची प्रस्तुत की है। हालाँकि, उन्हें जे. ई. आई.-एच. से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इस प्रकार, यह आरोप कि एमबीएल जे. ई. आई.-एच. से जुड़ा हुआ है, गलत है, सबसे पहले, क्योंकि जे. ई. आई.-एच. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जे. ई. आई.-एच. के समर्थकों द्वारा किए गए निवेश से प्रभावित होगा।

च

जी.

एच.

708

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

भारत की सुरक्षा, और दूसरी बात, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि जे. ई. आई.-एच. के समर्थकों द्वारा किए गए निवेश से राज्य की सुरक्षा प्रभावित होगी, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शेयरधारक जे. ई. आई.-एच. के समर्थक हैं। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के उद्देश्य का कोई वैध लक्ष्य या उचित उद्देश्य नहीं है।

169. आईबी ने नोट किया है कि एमआईबी के खिलाफ उपरोक्त सामग्री क्र. सं. को आकर्षित करती है। सुरक्षा मंजूरी प्रस्तावों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2018 के दिशानिर्देशों से जुड़े सुरक्षा मापदंडों की संख्या 20 और 22। एसएल

संख्या 20 "भारत में धार्मिक धर्मांतरण गतिविधियों में भागीदारी" के रूप में पढ़ा जाता है, और क्र. सं. संख्या 22 "सुरक्षा चिंताओं या सुरक्षा प्रणालियों के जानबूझकर या प्रणालीगत उल्लंघन के रूप में पढ़ता है जो सुरक्षा को खतरे में डालता है।

ग

जनता "।एस. एल. में सुरक्षा मापदंडों के लिए एम. बी. एल. के खिलाफ प्रस्तुत सामग्री के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। सुरक्षा मापदंडों की संख्या 20 और 22।एम. बी. एल. को केवल भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित भेदभाव पर रिपोर्ट प्रकाशित करने या एम. बी. एल. के शेरधारिता पैटर्न के संदर्भ में सुरक्षा चिंताओं का उल्लंघन करने के लिए धार्मिक धर्मांतरण में लिप्त नहीं कहा जा सकता है।

डी.

एल. निष्कर्ष और दिशाएँ

170. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है और 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के आदेश और 2 मार्च 2022 के उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

ई.

(i) सुरक्षा मंजूरी अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के नवीनीकरण के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक है;

(ii) एम. आई. बी. के आदेश और प्रक्रियात्मक आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी गई है:

च

(क) मेनका गांधी (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक बनाया गया था। प्रभाव यह है कि अदालतों ने माना है कि मामले के परिणाम से स्वतंत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने में एक अंतर्निहित मूल्य है। प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों को रद्द किया जा सकता है, भले ही गैर-अनुपालन मामले के परिणाम को प्रभावित न करे। प्राकृतिक ए के सिद्धांतों का मूल

जी.

एच.

709

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

न्याय प्रक्रिया में तर्कसंगतता की सांस लेता है। दावेदार पर यह साबित करने का भार है कि अपनाई गई प्रक्रिया प्रक्रियात्मक गारंटी के मूल का उल्लंघन करती है;

(ख) अपीलकर्ताओं ने साबित कर दिया है कि 31 जनवरी 2022 के एम. आई. बी. के अनुचित आदेश और अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने और केवल अदालत को इसका खुलासा करने से एम. बी. एल. के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद उत्तरदाताओं पर यह साबित करने का बोझ पड़ता है कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वह उचित थी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की आवश्यकताओं का अनुपालन करती थी। आनुपातिकता के मानक का उपयोग प्रक्रिया की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए किया गया है।

ग

(ग) पूर्व सैनिकों के संरक्षण में इस अदालत के निर्णय

सेवाएं (उपरोक्त) और डिजी केबल नेटवर्क (उपर्युक्त) आयोजित की गई

कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब मामले के तथ्यों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक हों;

डी.

(घ) यद्यपि गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियात्मक गारंटी को सीमित करने के उद्देश्य से वैध उद्देश्य हैं, राज्य यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि ये विचार वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में उत्पन्न होते हैं। सभी जांच रिपोर्टों के प्रकटीकरण से पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है; (ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों में शामिल होने के दावे की वैधता का मूल्यांकन इस परीक्षण पर किया जाना चाहिए कि (i) क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का प्रकटीकरण न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है; और (ii) क्या एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति रिकॉर्ड पर सामग्री से समान निष्कर्ष निकालेगा;

ई.

च

(च) यह मानते हुए भी कि गैर-प्रकटीकरण गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए साधन आनुपातिकता मानक के अन्य पहलुओं को संतुष्ट नहीं करते हैं। एमबीएल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों के सारांश का खुलासा न करना, जो प्रक्रियात्मक गारंटी का मूल अपरिवर्तनीय न्यूनतम है, उपयुक्तता को संतुष्ट नहीं करता है;

जी.

एच.

710

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(छ) अदालतें संरचित आनुपातिकता मानक के आधार पर जनहित प्रतिरक्षा दावों की वैधता का आकलन करती हैं, जो सीलबंद आवरण प्रक्रिया के समान नुकसान का समाधान करती हैं। सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावों के मूल्यांकन के दायरे के विपरीत होने पर सीलबंद लिफाफे में सामग्री को सुरक्षित करने की अदालतों की शक्ति काफी हद तक दिशाहीन और तदर्थ है। लोकहित प्रतिरक्षा दावों में अदालतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समीक्षा के मानक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए सीलबंद आवरण कार्यवाही में इस तरह के मानक की कमी इंगित करती है कि सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे कम प्रतिबंधात्मक साधन हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि जनहित प्रतिरक्षा के दावे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं, सीलबंद आवरण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

ग

(ज) अदालतें दस्तावेज के गोपनीय भागों को संशोधित करने और दस्तावेज की सामग्री का सारांश प्रदान करने का पाठ्यक्रम ले सकती हैं ताकि एक सफल सार्वजनिक हित प्रतिरक्षा दावे के बाद सामग्री को उचित रूप से बाहर किया जा सके; और

डी.

(iii) एम. आई. बी. के आदेश को चुनौती देने की अनुमति ठोस आधारों पर दी गई है। मीडिया चैनल के संचालन की अनुमति का नवीनीकरण न करना प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है जिसे केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आधारों पर ही यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। एम. बी. एल. को प्रतिभूति मंजूरी से इनकार करने के कारण, अर्थात्, इसका कथित प्रतिष्ठान विरोधी रुख और जे. ई. आई.-एच. से शेरधारकों का कथित संबंध, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिबंध के लिए वैध उद्देश्य नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, शेरधारकों के किसी भी संबंध को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था।

ई.

च

171. जबकि हमने निष्कर्ष निकाला है कि एक जनहित प्रतिरक्षा दावा एक कम प्रतिबंधात्मक साधन है, दावे की सुनवाई करते समय प्रक्रियात्मक गारंटी को अदालत द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायालय और उस सामग्री के गैर-प्रकटीकरण की मांग करने वाला पक्ष है जो जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही के लिए गोपनीय है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जनहित प्रतिरक्षा दावे का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपक्रम करते समय आवेदक के मामले में सामग्री की प्रासंगिकता जैसे कारकों पर विचार करे। हालाँकि, वह आवेदक जिसका ए में प्रतिनिधित्व नहीं है

जी.

एच.

711

मध्यमम ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत और हमारा संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

कार्यवाही प्रभावी रूप से बाधित होगी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर चिंताओं पर ऐसी सामग्री हो सकती है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता है; प्रक्रियात्मक गारंटी का संवैधानिक सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसे एक मृत पत्र में नहीं बदला जा सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में, यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब वे संघर्ष में हों तो इन दोनों विचारों को संतुलित करें। जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाहियों में प्रक्रियात्मक गारंटी को संभावित नुकसान से दावेदार को बचाने के लिए, हमने अदालत में एक न्याय मित्र नियुक्त करने की शक्ति को मान्यता दी है। न्याय मित्र की नियुक्ति गोपनीयता की चिंताओं को न्याय वितरण प्रक्रिया की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करेगी।

ग

172. न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र को राज्य द्वारा रोकी जाने वाली सामग्री तक पहुंच प्रदान की जाएगी। न्यायमित्र को कार्यवाही से पहले आवेदक और उनके वकील के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनके मामले का पता लगाया जा सके ताकि वे प्रकटीकरण की आवश्यकता पर प्रभावी प्रस्तुतियाँ दे सकें। हालाँकि, जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही शुरू होने के बाद न्यायमित्र आवेदक या उनके वकील के साथ बातचीत नहीं करेगा और वकील ने उस दस्तावेज़ को देखा है जिसे रोके जाने की मांग की गई है। न्यायमित्र अपनी पूरी क्षमता से आवेदक के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। न्यायमित्र शपथ द्वारा बाध्य होगा कि वह आवेदक या उनके वकील सहित किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामग्री का खुलासा या चर्चा नहीं करेगा।

डी.

ई.

173. संविधान के अनुच्छेद 145 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय केवल खुली अदालत में दिए जाएंगे। यद्यपि जनहित उन्मुक्ति कार्यवाही एक बंद व्यवस्था में होगी, न्यायालय को खुली अदालत में दावे को अनुमति देने या खारिज करने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। हम उस आपत्ति से अवगत हैं जो उठाई जा सकती है कि दावे की अनुमति देने के कारणों को उचित ठहराने वाले आदेश को अनिवार्य रूप से उसी सामग्री पर जानकारी का खुलासा करना होगा जिसकी वह रक्षा करना चाहता है। ऐसे मामलों में न्यायालय को अभी भी उन सिद्धांतों पर एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करने की आवश्यकता है जिन पर उसने विचार किया था और लागू किया था, भले ही जिस सामग्री का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, वह तर्कपूर्ण आदेश से संशोधित हो। हालांकि, तर्कपूर्ण आदेश से संशोधित सामग्री को अदालत के रिकॉर्ड में संरक्षित किया जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में अदालतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

च

जी.

174. तदनुसार दीवानी अपीलों की अनुमति दी जाती है। एम. आई. बी. अब चार सप्ताह के भीतर इस फैसले के संदर्भ में नवीनीकरण अनुमति जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा और अन्य सभी प्राधिकरण आवश्यक जारी करने में सहयोग करेंगे।

एच.

712

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अनुमोदन। इस न्यायालय का अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाती।

175. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: शुभांशु दास, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.